असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

03 मार्च, 2020

षोडश विधान सभा 03 मार्च, 2020 ई0

---------- मंगलवार, तिथि ----------

पंचदश सत्र 13 फाल्गुन,1941(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर-काल ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना पर हूँ ।

अध्यक्ष : आप तो हमको गवर्नर हाऊस में ही सूचना दे दिये थे । क्या है सूचना ?

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, दैनिक भास्कर में निकला हुआ है कि सरकार के नाराज मंत्री ने कहा है कि भूमि विवाद को लटकाकर अफसर रखते हैं और जब उनको पैसा दिया जाता है तब उसका निपटारा करते हैं ।

अध्यक्ष : अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-क-11(श्री संजय सरावगी)</u>

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय,1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वन्य प्राणी द्वारा मानव मृत्यु के लिए मुआवजे हेतु विभागीय संकल्प संख्या-421 दिनांक 5.9.2015 द्वारा प्रावधान किया गया है कि वन्य प्राणी से मृत्यु के मामले में नियमानुसार सहाय्य राशि का भुगतान किया जाता है । सर्पदंश से मृत्यु के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि विगत पांच वर्षों में सर्पदंश से मृत्यु संबंधी कोई दावा क्षेत्रीय वन प्रमंडलों से प्राप्त नहीं हुआ है ।

3- सर्प वन्य प्राणी की परिभाषा में आच्छादित है । इसके अलावे आपदा प्रबंधन विभाग के परिपत्र के अनुसार बाढ़ के दौरान सर्पदंश से मृत्यु व्यक्ति के आश्रित को अनुग्रह अनुदान भुगतेय है । साथ-ही बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के तहत सर्पदंश से मृत्यु दुर्घटना की श्रेणी में आता है, जिसमें अनुदान देय है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पिछले पांच साल में सर्पदंश से मौत के लिए किसी ने आवेदन नहीं दिया है वन विभाग में मुआवजा के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमलोग विधायक हैं, हमलोगों को भी नहीं पता है कि सर्पदंश से मौत के लिए वन विभाग अलग से मुआवजा देता है ।

अध्यक्ष : पता है, इसलिए आपने सवाल किया है ।

टर्न–1/अंजनी/दि0 03.03.2020

श्री संजय सरावगी : पांच साल से पता नहीं था, इधर पता चला है तभी हमने सवाल किया है। अध्यक्ष महोदय, पहले यह कि क्या सर्पदंश से वन विभाग 5 लाख रूपया देगी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी पहले यह बतायें और दूसरा अगर देगी तो पिछले पांच सालों में राज्य में जितने सर्पदंश से मौत हुई है, क्या वन विभाग उसका फिर से निरीक्षण करके, पता करके उन सभी परिवारों को जिनके परिवार सर्पदंश से मौत हुई है, वन विभाग उनको 5 लाख रूपया की अनुदान राशि देगी ?

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, चूंकि सर्प जो है, वह वन्य प्राणी की सूची में आता है और अगर कोई वन्य प्राणी के कारण किसी की अगर मृत्यु होती है, जैसे कोई शेर है, चीता है, बाघ है या हाथी, बांका जिले में इस प्रकार के कई घटनायें प्रतिवेदित हुई है, बाघ के कारण लोगों की मौत हो गयी तो पांच लाख रूपया देने का प्रावधान है । अगर माननीय सदस्य को इसकी जानकारी नहीं है तो इसका कोई उपाय हमारे पास नहीं है लेकिन नियम के तहत अगर कोई आवेदन करेगा तो सर्पदंश के मामले में भी 5 लाख रूपये का मुआवजा दिया जायेगा लेकिन इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, नहीं तो कोई कह देगा कि सर्पदंश से मृत्यु हो गयी तो कोई भी जो अस्वभाविक मृत्यु होती है, उसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफ0आई0आर0, सारे दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है । अगर उसके साथ कोई भी अगर आवेदन देगा तो निश्चित तौर पर वन विभाग उसको उचित मुआवजा देगी ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने कहा कि 5 लाख रूपया मिलेगा । लेकिन सर्पदंश से मौतें हो रही हैं, हम भी जान रहे हैं और पूरा सदन भी जान रहा है तो क्या सरकार उसका सर्वेक्षण करायेगी, जिनकी मौत हो गयी है.....

अध्यक्ष : सर्वेक्षण की क्या जरूरत है ?

श्री संजय सरावगी : सर्वेक्षण नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जिन लोगों को पता नहीं थाख्र

अध्यक्ष : अब कोई नहीं है, क्या पूछ रहे हैं, इसमें सर्वेक्षण की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सर्पदंश या अन्य वन्य प्राणियों के घात या अघात से अगरकिसी की मृत्यु होती है तो उसके दावा करने की अवधि क्या है ताकि वे मुआवजा लेने में सफल हो सकें ।

श्री भोला यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस दिशा में, वन्य प्राणी में सर्पदंश को भी शामिल किया गया है, इसके जागरूकता के लिए सरकार

के स्तर पर क्या कार्रवाई अभी तक की गयी है जिला में और प्रखंड स्तर पर, इसकी जानकारी सरकार दे ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, कौन वन्य प्राणी है, यह राज्य सरकार तय नहीं करती है, यह भारत सरकार का जो वन विभाग है, उसमें पूरे देश के लिए एक सूची बनायी है कि कौन-कौन प्राणी वन्य प्राणी की श्रेणी में आते हैं । जो सांप है, वह वन्य प्राणी के श्रेणी में आते हैं । अगर कोई मृत्यु हुई है तो उसको एक विहित प्रक्रिया के तहत आवेदन देना पड़ेगा फोरेस्ट डिपार्टमेंट में और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही उनको मुआवजा दिया जायेगा ।

श्री राहुल तिवारी : सर्पदंश से जो आकस्मिक मृत्यु होती है, उसमें सरकार की तरफ से मुआवजा का प्रावधान है लेकिन उसमें एक समस्या यह आती है कि अधिकारीगण कहते हैं कि जो बाढ़ में सर्पदंश से मरेंगे, उन्हीं को पैसा दिया जायेगा और अगर ऐसे मरते हैं सर्पदंश से तो उनको पैसा नहीं दिया जायेगा । मंत्री महोदय कह रहे हैं कि सभी को दिया जायेगा तो इस तरह का पत्र सरकार के द्वारा निर्गत हो जाना चाहिए तो कोई समस्या नहीं आयेगी ।

अध्यक्ष : राहुल जी, मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि बाढ़ के समय में जो सर्पदंश से मृत्यु होती है, उसको आपदा राहत वाले प्रोवीजन के तहत मिलता है, इसलिए उसका अलग प्रावधान है और माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि सांप जो है, वह वन्य प्राणी के श्रेणी में निर्धारित है, इसलिए इसके काटने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो उसके लिए सभी आवश्यक कागजात यानी उसका जो यू0डी0 केस होता है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, उन सब कागजात को लगाकर देंगे तो मुआवजा मिल जायेगा । सभी आदमी ध्यान रख लीजिए कि यह वन विभाग देगा और वह जिला प्रशासन देता है। इसलिए अगर कोई वन विभाग के संबंधित पदाधिकारी के यहां देता है तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि उनको पांच लाख रूपया दिया जायेगा ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-15(श्री ललित कुमार यादव)</u>

अध्यक्ष : इसका उत्तर आप देखे हैं ?

श्री ललित कुमार यादव : देख लिए हैं महोदय ।

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का लगभग 329 पद रिक्त है । समस्तीपुर, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी और खगड़िया जिलों में पदस्थापित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है, जिसमें अधिकतम

03 अथवा रिक्ति के अनुसार 03 से अधिक प्रखंडों का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है ।

राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के व्याख्याताओं की नियुक्ति/चयन हेतु आयोजित परीक्षा का बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है, जिसमें 455 अभ्यर्थी अंतिम रूप से सफल घोषित किये गये हैं। मार्च,2020 तक उनकी पदस्थापन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी । तत्पश्चात् अप्रैल,2020 में राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में पदस्थापित अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के व्याख्याताओं को वहां से हटा कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जाएगा ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से सीधा संबंधित है और माननीय मंत्री जी से हमने पूछा कि कितने पद रिक्त हैं, माननीय मंत्री जी का जवाब नहीं है कि कितना पद रिक्त है । संभवत: 534 प्रखंड हैं राज्य में और लगता है कि 350 पद रिक्त हैं और एक साल से.....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि 329 पद रिक्त हैं, उत्तर नहीं पढ़े हैं?

श्री ललित कुमार यादव : उत्तर देखे हैं ।

अध्यक्ष : आप कहिए तो जवाब पढ़ा देते हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मेरा प्रश्न भी यही है कि 329 पद रिक्त है राज्य में और 534 प्रखंड हैं । महोदय, आधे से भी कम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पदस्थापन है और एक साल से पद रिक्त है तो इससे हम राज्य के शिक्षा की क्या गुणवत्ता की उम्मीद कर सकते हैं ? महोदय, एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सात-सात प्रखंड के प्रभार में है, जबकि माननीय मंत्री जी का पत्र है कि तीन प्रखंड से ज्यादे के प्रभार में नहीं रहेंगे तो साल भर से राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता की क्या स्थिति होगी, यह हम, आप समझ सकते हैं । महोदय, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि मार्च तक पदस्थापन कर देंगे, फिर कह रहे हैं कि व्याख्याता जो अवर शिक्षा संवर्ग के पदाधिकारी हैं, हम उस शिक्षण संस्थान से लेंगे तो वह प्रक्रिया उनकी पूरी हुई कि नहीं और पूरी हुई तो मार्च ....

अध्यक्ष : वही प्रक्रिया के तहत कह रहे हैं कि अप्रील, 2020 तक पूरी होगी । वही तो कह रहे हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, कबतक हो जायेगा ?

अध्यक्ष : अप्रील 2020 तक ।

श्री ललित कुमार यादव : माननीय मंत्री जी तो कह रहे हैं कि मार्च तक ही पदस्थापन कर देंगे, अप्रील तक पूरा करेंगे...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग से व्याख्यातों की नियुक्ति के लिए परीक्षाफल प्रकाशित हो रहा है, 455 लोगों की अनुशंसा प्राप्त होगी तो मार्च तक उनको बहाल कर देंगे और वे जब बहाल हो जायेंगे तब हमको जो स्पेयर होंगे, उन सबको बी0ई0ओ0 बनाकर पोस्ट कर देंगे अप्रील तक । जवाब संतोषजनक है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, संतोषजनक है लेकिन साल भर से राज्य की शिक्षा की क्या गुणवत्ता रही है, माननीय मंत्री जी इसको संज्ञान में लें ।

अध्यक्ष : अल्पसूचित प्रश्न समाप्त हुआ ।

टर्न-2/राजेश-राहुल/03.03.20

अध्यक्ष: अब तारांकित प्रश्न लिय जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 644 (श्री उपेन्द्र पासवान)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत गढ़पुरा प्रखण्ड के राहुल नगर में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय भवनहीन है । भवनहीन विद्यालय को नजदीक के विद्यालय में संबद्ध कर संचालित किए जाने का विभागीय प्रावधान है । उक्त विद्यालय से तीन किलोमीटर की दूरी पर उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय है एवं माध्यमिक विद्यालय कोरई है, जिसके कारण राहुल नगर ग्राम में स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय को उक्त विद्यालय से संबद्ध नहीं किया जा सका है, वर्तमान में यह विद्यालय कच्चे मकान में संचालित है, उक्त विद्यालय का भवन निर्माण राज्य निधि के मद से किया जाएगा ।

श्री उपेन्द्र पासवान: अध्यक्ष महोदय जी, यह अत्यंत पिछड़ा इलाका है, राहुल नगर और इस विद्यालय में दलित वर्ग के बच्चे और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों का ही इस विद्यालय में नामांकन होता है । अभी वर्तमान में 252 छात्र-छात्राओं का नामांकन है और 252 विद्यार्थी ही इस विद्यालय में शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं और वहां 5 शिक्षक भी पदस्थापित हैं लेकिन वहां भवन नहीं है, सारे बच्चे आकाश के नीचे ही शिक्षा अध्ययन करते हैं.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: उन्होंने कहा है कि राज्य की निधि से विद्यालय का निर्माण कराएंगे ।

श्री उपेन्द्र पासवान: अध्यक्ष महोदय जी, मेरा पूरक प्रश्न है कि राज्य की निधि से उस भवनहीन विद्यालय में कब तक भवन का निर्माण हो जाएगा । वह विद्यालय भवनहीन है, छात्र-छात्राऐं वर्तमान में भी आकाश के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बरसात में वहां

भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है । माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि यह विद्यालय भवन राज्य की निधि से बनाया जाएगा लेकिन वह कब तक बनाया जाएगा ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विद्यालय की चर्चा की है उसके बारे में तो हमने पहले बताया था लेकिन इस तरह के कई विद्यालय राज्य में हैं जिनको भवन की जरूरत है और राज्य मंत्री परिषद् से ये स्वीकृत हो गए हैं, अगले छ: माह में हम इनके भवनों का निर्माण करा देंगे ।

अध्यक्ष: आज शिक्षा मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ आए हैं ।

श्री उपेन्द्र पासवान: अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही जानना चाहता हूं कि सारे भवनहीन विद्यालयों का कब का निर्माण करा देंगे ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय, मैंने स्वयं स्वीकार किया है कि राज्य में बहुत से भवनहीन विद्यालय हैं क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे प्रश्न आते रहते हैं और लोग भी हमसे मिलते हैं तथा हमें इन सारे विद्यालयों के भवन निर्माण की चिन्ता है और मंत्री परिषद् से ये स्वीकृत हो चुके हैं और छ: महीने के अन्दर ऐसे भवनहीन विद्यालयों के भवनों का निर्माण करा दिया जाएगा ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि पूरे बिहार में भवनहीन विद्यालयों की संख्या कितनी है ?

अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्रहलाद जी आप पूरक पूछिये ।

श्री प्रहलाद यादव: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये नवसृजित प्राथमिक विद्यालय छोटे-छोटे बच्चों के लिए सृजित किए गए थे, अब पूरे बिहार में किसी को मकान है, किसी को जमीन है लेकिन आपने क्या चतुराई की है कि पूरे बिहार में आपने प्राथमिक विद्यालयों को टैग कर दिया है दूसरे विद्यालयों में, जिसके कारण यह समस्या आ रही है, क्या यह पिछले सत्र में भी हुआ था, वैसे प्राथमिक विद्यालय जिनका अपना भवन है, जमीन है, निश्चित रूप से वे टैग नहीं होंगे । क्या माननीय मंत्री जी बता सकते हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय पहले जहां चल रहे थे उन्हें वहां चलाने का विचार रखते हैं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी आप भी पूरक सुन लिजिए और एक ही बार जवाब दे दीजिएगा ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय, इनका तो सुन लिया है, इनका तो जवाब दे ही देता हूं लेकिन इससे पहले ललित बाबू पूछ रहे थे कि पूरे बिहार में भवनहीन विद्यालयों की संख्या कितनी है, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि भवनहीन विद्यालयों की संख्या 947 है, जिनके भवन निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और मंत्री परिषद् से इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है और छ: माह के अन्दर ऐसे भवनहीन विद्यालयों के भवनों का निर्माण हम करा देंगे ।

अध्यक्षः माननीय विनोद जी, पहले मंत्री जी ने जो पूरक का जवाब दिया वो सुन लीजिए कि प्रदेश में जितने भवनहीन विद्यालय हैं उनकी संख्या 947 है और छः महीने के अन्दर भवनहीन विद्यालयों के भवनों का निर्माण करा देंगे । अब आपका क्या पूरक है ?

श्री विनोद प्रसाद यादवः महोदय, मेरा पूरक यह है कि शिक्षा विभाग ने जिन विद्यालयों के लिए राशि दी थी और अब उस राशि को वापस ले लिया है शिक्षा विभाग ने, चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, तो क्या उन विद्यालयों को पुनः राशि उपलब्ध कराने का विचार रखते हैं और यदि विचार रखते हैं तो कब तक रखते हैं ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः माननीय सदस्य जी, ये आपका जो प्रश्न है वह अलग प्रश्न है । आप इसको अलग से प्रश्न कीजिए, तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि छः महीने में इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह चुनाव वर्ष है और इस चुनाव वर्ष में छः महीने के बाद, अध्यक्ष महोदय जी आप स्वयं जानते हैं कि इस राज्य में आचार संहिता आ जाएगी । सर्व शिक्षा अभियान में अभी इनके पास कुछ राशि उपलब्ध है या नहीं और वैसे तो प्राथमिकता में दलित, पिछड़ों के जो प्राथमिक विद्यालय हैं जो माननीय मंत्री जी 947 विद्यालयों की बात कर रहे हैं उनका निर्माण कराने के लिए अभी इनके पास राशि है या नहीं और अगर राशि है तो उसके निर्माण का काम शुरू क्यों नहीं करा रहे हैं ?

श्री अत्रीमुनी उर्फ शक्ति सिंह यादवः महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर इस सदन को बताया था कि राज्य के अन्दर जितने भी भवनहीन विद्यालय हैं उन विद्यालयों को राज्य निधि से कराया जाएगा और अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण करा लिया जाएगा, यह पिछली अनुदान मांग में सदन को इन्होंने आश्वस्त किया था, आज माननीय मंत्री जी पुनः कह रहे हैं कि हम छः महीने में भवनहीन विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर लेंगे तो माननीय मंत्री जी इस बात का क्या मतलब है, आपने पहले आवश्वासन दिया था सदन को अनुदान मांग पर अब आपने बात बदलकर फिर से छः माह का समय ले लिया ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य जी, मंत्री जी अपनी बात पर कायम हैं, पिछली बार उन्होंने कहा था अगले वित्तीय वर्ष में करायेगें अगला वित्तीय वर्ष अब शुरू होगा, तो छः महीने के अन्दर ये प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण करा देंगे ।

श्री लाल बाबू रामः महोदय, पूरे बिहार में 2003 में सभी दलित बस्ती एवं दलित बहुल क्षेत्र में नवसृजित विद्यालय खोले गए थे और सभी को निकटवर्ती विद्यालयों से टैग किया गया था.....

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य जी आप पूरक पूछिए ।

श्री लाल बाबू रामः महोदय, मैं पूरक पूछ रहा हूं और आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जिस भी दलित बहुल क्षेत्र में नवसृजित विद्यालय खोले गए थे उन सभी विद्यालयों को निकटवर्ती विद्यालयों में टैग कर दिया गया है, महोदय जब वहां पर पूछा जाता है कि क्यों टैग कर रहे हैं तो सरकार द्वारा जवाब दिया जाता है कि जमीन नहीं है और भवन नहीं है । महोदय, हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि जो भी सरकार द्वारा निर्देश मिले हैं कि नवसृजित विद्यालयों को मिडिल स्कूल में टैग किया जाए, क्या माननीय मंत्री इस निर्देश का वापस करते हैं और यदि वापस करते हैं तो कब तक वापस करते हैं ।

अध्यक्षः अब हो गया ।

टर्न-3/सत्येन्द्र-मुकुल/03-03-2020

तारांकित प्रश्न संख्याः 645 (श्री सरोज यादव)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि उप विकास आयुक्त, भोजपुर के ज्ञापांक 25/वि॰ दिनांक 11.01.2020 के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, भोजपुर के पत्रांक 49 दिनांक 14.01.2020 के द्वारा मानक के अनुसार व्यय से अधिक राशि की निकासी करने वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। तदोपरान्त प्राप्त स्पष्टीकरण एवं अभिलेख मंतव्य के साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, भोजपुर के पत्रांक-90, दिनांक-28.01.2020 के द्वारा उप विकास आयुक्त, भोजपुर को कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित किया गया है। कृत कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

श्री सरोज यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जब भी मामला आता है, तो कार्रवाईधीन रहता है, प्रक्रियाधीन रहता है लेकिन देखिये इन्हीं के विभाग का टोटल 22 लैटर है और बाईसों लैटर में डेढ़ साल से एक जगह एम.डी.एम. बंद था, एम.डी.एम. डेढ़ साल तक बंद था, उसमें सभी लोगों को जांच पटना से टीम गई डिप्टी डायरेक्टर की अध्यक्षता में जांच की गई और जांच में यह आया कि ये-ये लोग दोषी हैं और सारे लोगों को दोषी करार किया गया लेकिन हमेशा लेटर निकाला गया लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं होती है और डी.डी.सी. महोदय द्वारा लेटर निकाला गया था कि 24 घंटा के अंदर में स्पष्टीकरण दीजिये अन्यथा बाध्य होकर के आप लोगों पर एफ.आई.आर. दर्ज किया जाएगा और ये लेटर जनवरी में ही निकला था

अध्यक्ष महोदय यह 11.01.2020 को और उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जहां डेढ़ साल तक एम.डी.एम. बंद था ....

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, इसको दिखवा लीजिए इसलिए कि अगर डी.डी.सी. या किसी वरीय अधिकारी ने जांच करवायी है और गड़बड़ी पाई गई है तो कार्रवाई तो हो ही जानी चाहिए।

श्री सरोज यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो एक लॉफूसपुर कन्या प्राथमिक विद्यालय है उसमें डेढ़ साल तक एम.डी.एम. बंद था। मैंने लगातार डेढ़ साल से 35 लेटर देने का काम किया है माननीय मंत्री जी को और प्रधान सचिव को।

अध्यक्षः सरोज जी, आपका पूरक क्या है ?

श्री सरोज यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि इसमें जो-जो लोग दोषी हैं उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गयी और जो बी.आर.सी. थे उनको जिला के अकाउंटेंट बनाकर फिर उसको रख लिया गया और जो गरीब बेचारा अकाउंटेंट था उसको चयनमुक्त करके उसको सेवा से हटा दिया गया।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः महोदय, मैं माननीय सदस्य की बातों से सहमत हूं । मामला गंभीर है और डी.डी.सी. को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। हम समझते हैं कि एक महीने के अंदर ये निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई हो जाएगी।

तारांकित प्रश्न संख्याः 646 (श्री मेवालाल चौधरी)

श्री विनोद कुमार सिंह, मंत्रीः महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मुंगेर जिलान्तर्गत अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए **हाजीसुजान** मुंगेर में एक जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास संचालित है जिसमें कुल 41 छात्र आवासित हैं। वर्तमान में मुंगेर जिलान्तर्गत **टेटिया बम्बर** प्रखंड में अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण कराने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री मेवालाल चौधरीः महोदय, क्या ये **इनप्रिंसिपुल** एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही छात्रावास बनाया जाएगा या और अन्य जगह छात्रावास बनाया जाएगा?

श्री विनोद कुमार सिंह, मंत्रीः महोदय, मुंगेर जिलान्तर्गत पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आर.डी. एण्ड डी.जे. कॉलेज परिसर में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास निर्मित है जिसका जीर्णोद्धार किया जाना है और दूसरा जो **हाजीसुजान,** मुंगेर में एक जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास संचालित है जिसमें वर्तमान में 41 छात्र आवासित हैं। उक्त दोनों छात्रावासों की कुल आवासन क्षमता 200 है। इसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय, आज से तीन महीना पहले, हम सदन को जानकारी कराना चाह रहे हैं कि सभी माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद् के अपने स्तर से

पत्र हम भेजे थे और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि छात्रावास के लिए एक एकड़ जमीन आप उपलब्ध कराइये और उसको अविलंब हम भारत सरकार को प्रस्ताव देंगे तो कुछ लोगों ने अपना पत्र का जवाब दिया और बहुत सारे लोग नहीं दिये हैं तो माननीय सदस्य को लगता है कि चिट्ठी उनको मिली है लेकिन उसका जवाब अभी तक दे नहीं पाये हैं और छात्रावास का निर्माण करवायेंगे।

श्री मेवालाल चौधरी: महोदय, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। **टेटिया बम्बर** प्रखण्ड वहां से तकरीबन 40-45 किलोमीटर है। महोदय, माननीय मंत्री जी के चिट्ठी का जवाब मैंने दिया है और ये भी बड़ा स्पष्ट तौर से कहा है कि यहां पर जमीन की उपलब्धता है। अगर आपके माध्यम से निवेदन करेंगे महोदय कि अगर जमीन की उपलब्धता है और सरकार चाह रही है, बड़ा अच्छा होगा।

अध्यक्ष: ठीक है, जो जमीन उपलब्ध है, आप माननीय मंत्री जी को सूचना उपलब्ध करा दीजियेगा, सरकार कार्रवाई करेगी।

श्री मेवालाल चौधरी: ठीक है।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या: 647 (श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव)</u>

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय,(क) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय के माध्यमिक संभाग में 12 शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक संभाग में 10 शिक्षक कार्यरत हैं। इसमें विज्ञान एवं अंग्रेजी के दो-दो शिक्षक हैं जबकि भौतिकी एवं हिन्दी विषय में एक-एक शिक्षक सम्मिलित हैं।

(ख) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय के वरीयतम शिक्षक को प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया गया है। इस विद्यालय में पदस्थापित लिपिक दिनांक-31.12.2019 को सेवानिवृत्त हुए हैं।

(ग) छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसे दिनांक-27.03.2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रक्रिया से प्रश्नगत विद्यालय में भी स्वीकृत पद के विरूद्ध उपलब्ध रिक्ति पर संबंधित नियोजन इकाई (जिला परिषद्, पूर्वी चम्पारण) द्वारा नियोजन किया जायेगा। प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची विभाग द्वारा तैयार कर ली गई है। प्रोन्नति में आरक्षण से संबंधित मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन रहने के कारण सभी तरह के प्रोन्नति पर वर्तमान में रोक लगा हुआ है। प्रोन्नति पर रोक के हटने के उपरांत प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति की कार्रवाई की जायेगी। लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा नीति निर्धारित की जा रही है। इसके उपरांत लिपिक के पद पर नियोजन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहेंगे कि यह जो बता रहे हैं कि मनोविज्ञान, संगीत एवं भौतिकी का शिक्षक वहां उपलब्ध है। महोदय, हम कहना चाहेंगे कि मंत्री महोदय उसको दिखवा लें फिर से अपने से दिखवा लें, वहां पर शिक्षक भी नहीं है और वहीं नहीं जितना भी मिडिल स्कूल से जितना भी हाई स्कूल जो बनाया गया है उसमें कहीं शिक्षक नहीं है। शिक्षक नहीं है और वहां पर पढ़ाई बाधित है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो विद्यालय हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है उसमें शिक्षक देने का काम करें ताकि वहां पर पढ़ाई सुचारू ढंग से चल सके।

तारांकित प्रश्न संख्याः 648 (श्री ललन पासवान)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः कंडिका (1), (2) एवं (3) के प्रसंग में विश्वविद्यालय के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जिला पदाधिकारी, रोहतास एवं कुलसचिव, वीर कुवंर सिंह विश्वविद्यालय, आरा को महाविद्यालय के लिए संदर्भित भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध पत्र भेजा गया है। राज्य सरकार के स्तर से विभागीय पत्रांक-415, दिनांक 24.02.2020 द्वारा जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को प्रश्नाधीन महाविद्यालय के सम्यक संचालन हेतु नियमानुसार शहरी क्षेत्र में न्यूनतम 2.5 एकड़ अथवा ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 5 एकड़ भूखण्ड उपलब्ध कराने हतु अनुरोध किया गया है। जिला पदाधिकारी, रोहतास से इस संदर्भ में प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा।

टर्न-4/मधुप-हेमंत/03.03.2020

श्री ललन पासवान : महोदय, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यह कॉलेज 40-50 वर्षों से 35 डिसमिल जमीन पर है और 8 हजार छात्र-छात्राएँ वहाँ पढ़ते हैं । उस कॉलेज से रेलवे लाईन सटे हुए गुजरता है, दर्जनों छात्र-छात्राएँ कट चुके हैं । हमारे यहाँ वहाँ बगल में करूप जहाँ ये बता रहे हैं मंत्री जी, एक एकड़ नहीं, दो एकड़, जो ये नियम की बात कर रहे हैं, वहाँ 40 से 50 एकड़ जमीन है जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनने की बात थी, वहाँ से चला गया, जब चाहें मंत्री जी तब जमीन की उपलब्धता है, कलक्टर से हमारी बात हुई है, जमीन देने के लिए कलक्टर तैयार हैं लेकिन माननीय मंत्री जी अगर माँगे और उसकी कार्रवाई हो, समय-सीमा के अन्दर, मैंने कहा कि दर्जनों नहीं सैकड़ों छात्र-छात्राएँ 30-40 वर्षों में कटकर मर चुके हैं रेलवे लाईन पर । वहाँ बगल में जमीन है ।

कबतक ? समय-सीमा बतायें, जमीन की उपलब्धता कराकर कबतक इस कॉलेज की स्थापना करेंगे ? बगल में करूप है, 2.5 कि0मी0, 1 कि0मी0, 1.5 कि0मी0 की दूरी पर, समय-सीमा बतावें ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, जिला पदाधिकारी को कहा गया है, इसपर रिपोर्ट माँगा गया है । जमीन की उपलब्धता हो जाती है तो बहुत जल्द यह काम हो जायेगा । इसलिए....

श्री ललन पासवान : समय-सीमा बतायें ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, जिला पदाधिकारी को कहा गया है, फिर बात भी करेंगे।

श्री अशोक कुमार (208) : महोदय, जिस कॉलेज की चर्चा हो रही है, उससे आधा कि0मी0 की दूरी पर, 2 एकड़ नहीं, माननीय मंत्री जी को 8 एकड़ जमीन दिया बिहार सरकार की है, वहीं पर शिफ्ट कर दें । मिश्रीपुर में, खाता-मौजा जो कहिए, मैं दे देता हूँ । 8 एकड़ बिहार सरकार की जमीन है, उसके सटे है, उसी प्रखंड का कॉलेज उसी प्रखंड में रह जाय, मैं जमीन दिया ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब तो माननीय सदस्यगण सरकार की मदद को तैयार हैं, जमीन चिन्हित करके दे रहे हैं, वैसे प्रश्न में भी खाता संख्या और प्लॉट संख्या दिया हुआ है । उसको भी देखवा लीजिए और अशोक जी जो कह रहे हैं, 8 एकड़ जमीन, उसके बारे में भी कलक्टर को निदेश देकर दोनों माननीय सदस्यों से जमीन का ब्यौरा मँगवाकर आगे की कार्रवाई कर दीजिए ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 649 (श्री मुद्रिका प्रसाद राय)

अध्यक्ष : श्री मुद्रिका प्रसाद राय ।

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 650 (श्री मो0 आफाक आलम)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत जलालगढ़ प्रखण्ड स्थित मध्य विद्यालय, सरसौनी एवं मध्य विद्यालय, कठैली में चहारदिवारी है ।

श्री मो0 आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, चहारदिवारी वहाँ पर नहीं है । उत्क्रमित हाई स्कूल है और मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितना भी उत्क्रमित हाई स्कूल बना है, चहारदिवारी है ही नहीं । उसमें जो स्मार्ट क्लास के लिए टी0वी0 वगैरह दिया गया है, कई जगह से चोरी भी हो गई है । इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए चहारदिवारी का होना बहुत जरूरी

है । कहीं चहारदिवारी नहीं है, जहॉ-जहॉ भी बनी है, वैसे ही सब है । कबतक बनवायेंगे ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : माननीय सदस्य इसका पूरक देख लें ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : महोदय....

अध्यक्ष : आप कहॉ पूर्णियां जा रहे हैं अवधेश जी !

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : पूर्णियां जिलान्तर्गत जलालगढ़ प्रखण्ड स्थित मध्य विद्यालय, सरसौनी एवं मध्य विद्यालय, कठैली के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रश्न है, तो कहना है कि दोनों विद्यालय में प्लस टू तक का भवन निर्माण किया गया है, जो चहारदिवारी विहीन है, प्लस टू वाला । मध्य वाले की चहारदिवारी पहले से ही निर्मित है ।

श्री मो0 आफाक आलम : दो-तीन जगह के बारे में हम बता रहे हैं, वहॉ पर है ही नहीं । उत्क्रमित जो मध्य विद्यालय हुआ है, उसी के बारे में हम कह रहे हैं । उत्क्रमित मध्य विद्यालय, यहॉ लिखे हुए हैं, सर । इसकी जॉच करवा ली जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, जॉच करवा ली जाय ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब है, वह मध्य विद्यालय का है और माननीय विधायक जी जो कह रहे हैं, उत्क्रमित उच्च विद्यालय का....

अध्यक्ष : वही तो वे बताये मंत्री जी ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : जरा सुन लिया जाय, अध्यक्ष जी । आप इसकी जॉच कराकर, अगर नहीं है तो माननीय सदस्य जी का स्पष्ट कहना है, माननीय मंत्री जी के जवाब को चुनौती नहीं दे रहे हैं, मगर माननीय मंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि आप जॉच करके, अगर नहीं है तो वहॉ चहारदिवारी का निर्माण करा दीजिए ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अशोक कुमार (208) : महोदय....

अध्यक्ष : आप उधर के बारे में कह रहे थे तो हमको समझ में भी आ रहा था, अब पूर्णियां भी आप चले जा रहे हैं !

श्री अशोक कुमार (208) : अध्यक्ष महोदय, चहारदिवारी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं । महोदय, सदन की एक गरिमा है और माननीय सदस्य किसी चीज का सवाल उठाते हैं और पदाधिकारी द्वारा उसके ठीक नकारात्मक जवाब हाउस में माननीय मंत्री के द्वारा दिलवाया जाता है तो सदन यह जानना चाहता है कि माननीय मंत्री जी का जवाब सही है या माननीय सदस्य का सवाल सही है ? चूंकि पदाधिकारी जो गलत कर रहे हैं, इसलिए सदन की कमिटी से जॉच कराकर अगले हफ्ते में सदन में रिपोर्ट आवे और जिन पदाधिकारियों ने गलत रिपोर्ट किया है, उसपर कानूनी कार्रवाई की जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपने जो बताया, पूछा उन्होंने, यह उत्क्रमित उच्च विद्यालय या मध्य विद्यालय दोनों के प्रांगण में कोई कंफ्यूजन या दुविधा है क्या ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : मध्य विद्यालय में चहारदिवारी है लेकिन जो उत्क्रमित हुआ है, उसमें चहारदिवारी की आवश्यकता है और हमलोग कोशिश करेंगे कि उसकी चहारदिवारी बन जाय ।

श्री मो0 आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, इसमें हम साफ-साफ लिखे हुए हैं, मध्य विद्यालय उत्क्रमित कठैली में है और सरसौनी भी, दो जगह है । ऐसी कई जगह हैं, जहॉ-जहॉ भी बना है, सब जगह वैसे ही है ।

अध्यक्ष : अब आप बैठिये न !

उन्होंने कहा है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय में चहारदिवारी है, उत्क्रमित उच्च विद्यालय में नहीं है, उसकी आवश्यकता है, हम उसके लिए कार्रवाई करेंगे ।

श्री मो0 आफाक आलम : कबतक करेंगे ?

अध्यक्ष : जल्दी करवा दीजिएगा ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : जल्दी करवा देंगे ।

श्री मो0 आफाक आलम : आश्वासन तो मंत्री जी दें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 651(श्री विजय कुमार खेमका)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है...

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, पदाधिकारीगण मंत्री जी को गलत सूचना देते हैं और मंत्री जी उसी को पढ़कर माननीय सदस्य को संतुष्ट करना चाहते हैं...

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये ।

माननीय मंत्री, कला संस्कृति एवं युवा विभाग ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि किसी महोत्सव/उत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा देने की कार्रवाई कला संस्कृति युवा विभाग, बिहार द्वारा नहीं की जाती है । बेलौरी स्थित शीतला महोत्सव के आयोजन हेतु दिनांक- 15.03.2020 को जिला पदाधिकारी, पूर्णियां के माध्यम से 2 लाख रुपये से कराने हेतु स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है । वित्तीय वर्ष 20-21 के सांस्कृतिक कैलेण्डर में उक्त महोत्सव को जोड़ने की भी कार्रवाई की जा रही है ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय....

अध्यक्ष : अब तो हो ही गया, कार्रवाई की जा रही है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से पूर्णिया की जनता की ओर से मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 652(श्री सत्यनारायण सिंह)

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिलान्तर्गत डिहरी प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय, भैंसहा भवनहीन एवं भूमिहीन है । यह विद्यालय सिंचाई विभाग की भूमि पर वर्ष 1961 में सामुदायिक सहभागिता से बने तीन कमरे के भवन में संचालित था ।

कनीय अभियंता डिहरी, बिहार शिक्षा परियोजना, रोहतास द्वारा दिनांक-21.11.2019 को स्थलीय निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि उक्त विद्यालय के एक कमरे की छत जर्जर है, एक कमरे की दीवार में दरार है तथा सभी कमरों के दरवाजे एवं खिड़कियाँ टूटी हैं । साथ ही, उक्त सामुदायिक भवन में भैंसहा गांव का सामुदायिक कार्य भी होता है । अतएव प्राथमिक विद्यालय, भैंसहा को 300 मीटर की दूरी पर अवस्थित मध्य विद्यालय, मानिकपुर में शिफ्ट किया गया है ।

टर्न-5/आजाद:अंजली/03.03.2020

श्री सत्यनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम कहे भी है कि यह 1961 से चल रहा है और तीन कमरा था, उस गये और उसमें मात्र 5 हजार रू0 लगाकर के गांव वाले के सहयोग से कमप्लीट है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अगर उसको डी0ई0ओ0 के साथ जाकर जॉच करा लें, जहां शिफ्ट किये हैं, उससे जहां अच्छा हो, चूँकि इरीगेशन पर तो कई जगहों पर विद्यालय चल रहा है और 1961 से चल रहा है और प्राथमिक विद्यालय है, छोटे-छोटे बच्चे दूसरे गांव में जाकर पढ़ रहे हैं, एक तो जमीन मिलता नहीं है और बौन्ड्री किया हुआ है, उसमें शास्त्री जी की मूर्ति है, उतने दिन से चल रहा है तो मेरा मंत्री जी से आग्रह होगा कि आप कह रहे हैं कि भवन टूटा हुआ है तो आप उसकी जॉच करा लें, अगर भवन ठीक है तो वही चलाया जाय, क्या ऐसा माननीय मंत्री जी करना चाहेंगे ?

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, जो जवाब आया है और जो निरीक्षण करने के उपरान्त यह जवाब आया है । वह भवन बिल्कुल जर्जर है, कभी भी दुर्घटना हो सकती थी, ऐसी स्थिति में राज्य में कई ऐसे विद्यालयों को शिफ्ट किया गया है । जब यहां पर भवन बन जायेगा तो फिर वह विद्यालय यहां पर आ जायेगा । यह उस भवन की स्थिति को देखकर, जर्जर स्थिति को देखकर के ऐसा निर्णय किया गया है और ऐसा

राज्य के कई जगहों पर किया गया है । भवन का निर्माण हो जायेगा तो फिर वह विद्यालय चला आयेगा ।

अध्यक्ष : अभी मंत्री जी, पिछले प्रश्न के उत्तर में आपने बताया था कि जिन भवनविहिन विद्यालयों के पढ़ाई को दूसरे विद्यालय से टैग कर दिया गया है, स्थानान्तरित कर दिया गया है तो वैसे विद्यालयों में अगले 6 महीना के अन्दर आप भवन बनाने जा रहे हैं ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : भवन बन जायेगा तो फिर यहां आ ही जायेगा ।

अध्यक्ष : यह भी तो उसी कैटेगरीज में आता है ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : जी, उसी कैटेगरीज में ।

अध्यक्ष : तो आप अपने उस बात को माननीय सदस्य को नहीं बता रहे हैं ।

श्री सत्यनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह डी0ई0ओ0 का रिपोर्ट आया, वहां अधिकारी का कि भवन जर्जर है और एक माननीय सदस्य हम भी वही के बगल के हैं तो वह रिपोर्ट कहता है तो सही है और हम कह रहे हैं तो गलत है । तो मेरा आग्रह होगा कि कोई उच्च कमेटी से जॉच करा लें ।

अध्यक्ष : उच्च कमेटी से क्या, आप कहिए कोई सिनियर ऑफिसर जायेगा और इनको भी साथ रखेगा ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : ठीक है ।

श्री सत्यनारायण सिह : हमको भी उसमें साथ रखे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-653 (सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान)</u>

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के वर्तमान नीति के अनुसार र्सि उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है, जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है । कटिहार जिले का कोढ़ा प्रखंड कटिहार सदर अनुमंडल के क्षेत्रान्तर्गत है, जहां पूर्व से डी0एस0 कॉलेज, कटिहार, के0बी0 झा कॉलेज, कटिहार एवं एम0जे0एम0 महिला कॉलेज, कटिहार अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में संचालित हो रहे हैं । अतः कोढ़ा प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री शकील अहमद खॉ : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : पहले इनको तो पूछने दीजिए ।

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान : अध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार की नीति जैसे अभी प्राथमिक विद्यालय को शिफ्ट किया गया विद्यालय भवन के अभाव में, अगर सरकार चाहे तो यह पॉलिसी ला सकती है, क्योंकि वहां पर प्लस-2 विद्यालय है तो वहां के

विद्यार्थी 20 से 25 कि0मी0 फल्का ब्लॉक से जाते हैं कटिहार , 18 कि0मी0 कोढ़ा से जाते हैं, बच्ची जिसके कारण पढ़ाई में कठिनाई होती है लड़कियों को तो अगर सरकार चाहे तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना ही कहना चाहती हूँ कि वहां के विद्यालय सभी हैं, हाईस्कूल हैं, लेकिन अगर प्लस-2 चाहेंगे तो सरकार चाहेगी तो पॉलिसी बनाकर खोला जा सकता है, यह सरकार के अधीन में है ।

अध्यक्ष : चलिए शकिल साहेब ।

श्री शकील अहमद खॉ : मैं मिनिस्टर साहेब से यही प्रश्न करना चाहता हूँ कि यह टका सा जवाब हर बार दिया जाता है कि सब-डिविजन के लेवल पर कॉलेजेज हैं, पिछले 15 साल से आपलोग हैं और आबादी की संख्या भी बढ़ी है । एज ए पॉलिसी इस बात के लिए एग्री करें कि जबकि आबादी बढ़ी है और सब-डिविजन पर कॉलेजेज हो सकते हैं, उसकी भी हालत बहुत खराब है, इसमें कोई शक नहीं है । आप इसको खोलेंगे, जमीन आवंटन करेंगे, ब्लिडिंग बनायेंगे, टीचर्स रखेंगे, यह कमीटमेंट सरकार कौन है, यह सरकार तो सेवा के लिए है न, आप टेका सा जवाब मत दीजिए, पॉलिसी के लेवल पर बताईए कि सरकार ब्लॉक लेवल पर जब आबादी बढ़ गई है और कॉलेजेज की दूरी बढ़ी है, पढ़ने का क्रम का ज्यादा बढ़ गया है तो पॉलिसी के लेवल पर आप बताइए और कमीटमेंट देना चाहिए, यह होती है सरकार, इसलिए यह कमीटमेंट आप दीजिए ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न सं0-654, माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, शिक्षा विभाग ।

श्री शकील अहमद खॉ : इसका जवाब मिलना चाहिए न । कब बनेगा.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सवाल का जवाब, जरा सवाल पर पूरक पूछने से पहले नियमावली भी पढ़ लीजिए, नीतिगत प्रश्न पर पूरक नहीं पूछा जाता है, वह सुझाव दिया गया है, सुझाव सरकार के यहां दर्ज हो गया, अब सरकार कौन नीति बनायेगी या कौन नीति बनाये, वह प्रश्न से, ध्यानाकर्षण से नहीं पूछा जा सकता है ।

चलिए, श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0-654(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक हैं

वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-259 दिनांक-22.02.2002 के द्वारा बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय द्वारा (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम 1981 की धारा-6 एवं संशोधित अधिनियम 1993 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के प्रत्येक राजकीयकृत उच्च विद्यालयों के लिए एक प्रबंध समिति के गठन का प्रावधान किया गया है ।

उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय भी राजकीयकृत कोटि के विद्यालय हैं । ऐसे विद्यालयों को वर्ग-1 से वर्ग-12 तक संचालित किया जाना है । इसमें वर्ग-1 से वर्ग-8 के लिए विद्यालय शिक्षा समिति गठित है । तत्काल विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा इस कोटि के विद्यालय का प्रबंध किया जा रहा है ।

विभाग के स्तर पर उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग-9 से वर्ग-12 तक के कक्षाओं सहित पूरे विद्यालय के प्रबंधन के लिए नीति निर्धारण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हो गया है ।

अध्यक्ष : आप संतुष्ट हैं ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : नहीं, हम पूरक पूछना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : तब पूछिए ।

(व्यवधान)

बैठिए ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये उत्तर में प्रबंधन समिति के बारे में कहा गया है, वो विरोधाभाषी वक्तव्य है । हमारे क्षेत्र में जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय हैं, उसमें तीन-चार उच्च विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन माननीय सदस्य के द्वारा हुआ है और इन्होंने जवाब में लिखा है कि अभी नीति निर्धारण हो रहा है तो बताया जाय कि उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में माननीय सदस्यों की अध्यक्षता में प्रबंध समिति का गठन होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कब तक होगा ?

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पष्ट मामला है, हमलोगों ने जिन मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित किया है, वहां प्रबंधकारिणी समिति का गठन नहीं हुआ है क्योंकि वह एक ही भवन और एक ही परिसर में है और वर्ग 1 से 8 तक वहां शिक्षा समिति पहले से कार्यरत है तो शिक्षा समिति उसको देख रही है । अब उसका उत्क्रमित हुआ है, इस संबंध में अभी कोई नीति नहीं बनी है कि वहां विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति अन्य विद्यालयों में है, उसका गठन किया जाय या नहीं ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब है कि एक ही विद्यालय में मध्य विद्यालय भी चल रहा है और उच्च विद्यालय भी । महोदय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय में आधे से अधिक में अपना भवन भी है और अपना क्लास भी अलग चल रहा है, मध्य विद्यालय को उत्क्रमित उच्च विद्यालय को कोई मतलब नहीं है तो वैसे मध्य विद्यालय जिसका अपना भवन है, अपना सब चीज अलग है, उसमें कब तक प्रबंध समिति का गठन करना चाहते हैं, चूँकि राज्य भर का सवाल है ।

अध्यक्ष : मध्य विद्यालय में या उच्च विद्यालय में ?

श्री ललित कुमार यादव : उत्क्रमित मध्य विद्यालय में ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, उत्क्रमित जो विद्यालय हुए हैं, उस संबंध में अभी कोई नीतिगत फैसला नहीं हुआ है लेकिन शिक्षा समिति वर्ग 1 से 8 तक में शिक्षा समिति काम कर रही है और अब ये उत्क्रमित हुआ है, इस संबंध में हमलोग शीघ्र कोई फैसला लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक ही भवन में चल रहा है, सरकार की घोषित नीति थी कि हम अलग से प्लस-2 विद्यालय का भवन बनायेंगे और बना भी सभी जगह । जितने प्लस-2 उत्क्रमित हुए अध्यक्ष महोदय, सभी में अलग से भवन बना है और उसके लिए सरकार ने राशि दी है और तब वहां पर वर्ग संचालन प्रारंभ हुआ और सरकार की पूर्व से नीति है कि जो भी उच्च विद्यालय होगा, उसमें माननीय विधायक प्रबंध समिति के अध्यक्ष होंगे । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि पूर्व से जो नीति है ठीक है, मध्य विद्यालय तक तो शिक्षा समिति है जो वार्ड मेम्बर की अध्यक्षता में होती है लेकिन मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि पूर्व से नीति है कि उच्च विद्यालयों में माननीय विधायकों की अध्यक्षता में वहां प्रबंधन समिति का गठन करेगी तो क्या कारण है कि सरकार बोल रही है कि हम अभी नीति नहीं बनाये हैं तो क्या पूर्व से जो नीति है कि माननीय सदस्य, माननीय विधायक की अध्यक्षता में वहां प्रबंध समिति काम करेगी तो क्या सरकार सभी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को निदेश देना चाहती है कि जो पूर्व से नीति है, उस नीति पर सरकार और विभाग अमल करें ।

टर्न-6/शंभु/03.03.20

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना का कद्र करता हूँ और मैंने बताया है कि जब कोई भी विद्यालय उत्क्रमित हुआ और अब वह हाईस्कूल हो गया है तो स्वाभाविक है कि वहां मैनेजमेंट कमिटी बनेगी । इस संबंध में प्रक्रियाधीन है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए न ।

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : मेरी पूरी बात आपने नहीं सुनी । मेरी पूरी बात को सुनिये आप, मेरी पूरी बात को सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग मंत्री जी की पूरी बात सुने नहीं असली बात अब बोलनेवाले हैं, बोलिये मंत्री जी ।

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : असली बात हम अब बोलनेवाले हैं । एक महीने के अंदर प्रबंधकारिणी समिति का गठन.....

अध्यक्ष : माइक के सामने जरा अच्छा से बोलिये ।

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : एक माह के अंदर आप सब लोगों की भावना को देखते हुए एक माह के अंदर प्रबंधकारिणी समिति का गठन कर दिया जायेगा । खुश हैं ?

अध्यक्ष : सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए । माननीय मंत्री जी ने कहा है और इसीलिए हम कह रहे थे कि आप लोग असली बात सुनने तक धैर्य रखते नहीं हैं, आधा सुने और बोलने लगे । आप लोगों की भावना को देखकर माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जिस तरीके से उच्च विद्यालयों के लिए- आप सुनिए न, फिर बीच में आप तो मंत्री की भी नहीं सुनते हैं, किसी की भी नहीं सुनते हैं, बीच में आप ही बोलियेगा तो सुनियेगा कब ? इसलिए मंत्री जी ने कहा है कि जैसे उच्च विद्यालयों में प्रबंध समिति होती है उसी तरह से जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय हैं उसमें भी एक महीना के अंदर प्रबंधकारिणी समिति बना दी जायेगी । मंत्री जी, यही बात है न ?

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : जी ।

अध्यक्ष : देखिए कितनी सीधी बात है ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : मंत्री जी बतायें ये बात ।

अध्यक्ष : अरे, मंत्री जी क्या बोले हैं नहीं बोले हैं यह केवल आप ही नहीं सुनते हैं आसन भी सुनता है, हमेशा याद रखियेगा ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, सदन में माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करता हूँ कि इतना बढ़िया जवाब दिये हैं माननीय मंत्री जी एक बार धन्यवाद तो दे दें माननीय सदस्य ।

अध्यक्ष : भाई, यह तो आज सदन को मानना पड़ेगा कि शिक्षा मंत्री जी की तैयारी और मुस्तैदी के हम सभी कायल हैं ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : आप कायल नहीं हैं ?

श्री अवधेश कुमार सिंह : महोदय, आज माननीय शिक्षा मंत्री जी एकाध शायर नहीं कहे हैं इसीलिए पूरा सदन उनसे मुखातिब हो रहा है ।

अध्यक्ष : कोई एक सुना दीजिए, अच्छा अगली बार ।

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : वह प्रसंग होता है तब उस तरह का होता है, माहौल वैसा आयेगा तो हो जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जरा मंत्री जी, आप बैठ जाइये, पहले सुन लीजिए ।

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, अब शिक्षा मंत्री जी कैसा माहौल चाहते हैं, पूरा मंच तो लूट लिया, अब कैसा माहौल चाहते हैं ?

तारांकित प्रश्न सं0-655(श्री जयवर्धन यादव)

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज प्रखंड के ग्राम मखदुमचक में स्थित प्राथमिक विद्यालय ऊर्दू भवनहीन होने के कारण इसी ग्राम में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय ऊर्दू मदरसा में संचालित था । वर्तमान में इस विद्यालय को मध्य विद्यालय चंडोस में शिफ्ट किया गया है । मध्य विद्यालय चंडोस में कुल 18 कमरे उपलब्ध हैं तथा यह विद्यालय ग्राम मखदुमचक से 700 मीटर की दूरी पर स्थित है । ग्राम मखदुमचक में भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, भूमि उपलब्ध होने के उपरांत भवन निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

श्री जयवर्धन यादव : महोदय, यह जो उच्च विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय ऊर्दू मखदुमचक यहां से स्थानान्तरण किया गया है विश्वनाथ हाईस्कूल चंडोस में ये दूरी तो लंबी है ही साथ ही पथ निर्माण विभाग की मुख्य सड़क और एक राजकीय उच्च पथ को पार करके तब छोटे बच्चों को जाना पड़ेगा और अगर आप एक्सीडेंट का रेशियो देखेंगे विगत कुछ दिनों में तो बढ़ा हुआ है । महोदय, मेरा एक पूरक है कि मंत्री जी ने क्या विषय पर जॉच करवाया था कि छोटे बच्चों का जीवन खतरे में पड़ सकता है । मेरा यह पूरक है कि इसकी जॉच.....

अध्यक्ष : आप जॉच कराने के लिए कह रहे हैं क्या ?

श्री जयवर्धन यादव : करवायी थी कि नहीं महोदय, छोटे बच्चे का स्थानान्तरण कराकर 3 कि0मी0 दूर भेजा जा रहा है । यानी 3 कि0मी0 चलकर के एस0एच0 पार करके, एक मुख्य सड़क पथ निर्माण की है उसको पार करके जाइये और यह जॉच नहीं करवायी गयी ।

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, मंत्री लोग आपस में पीछे बात कर रहे हैं आसन की ओर नहीं देख रहे हैं ।

अध्यक्ष : लगता है आप ही का इन्फेक्शन लग गया है ।

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, अब सिचुएशन बनता जा रहा है, अब माहौल बनता जा रहा है शेर कहने का तो मैं पहले एक सेर ही सुना देता हूँ - तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें ।

अध्यक्ष : अभी जयवर्धन जी के ऊर्दू विद्यालय का भी बता दीजिए ।

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं तो जो रिपोर्ट हमें आया है उसके आधार पर यह जवाब हम दे रहे हैं । अब अगर आवश्यकता है तो हम इसकी जॉच करा लेते हैं और इसके बाद फिर इसपर कार्रवाई करेंगे ।

श्री जयवर्धन यादव : महोदय, मेरा एक आग्रह है माननीय मंत्री जी से कि तब तक पूर्ववत् स्थिति बनाकर रखी जाय और जहां अभी विद्यालय चल रहा है प्राथमिक विद्यालय ऊर्दू वहीं पर बच्चों को रहने दिया जाय और वहीं पर पठन-पाठन का कार्य संचालित हो ।

अध्यक्ष : वह आप अलग से लिखकर दे दीजिएगा मंत्री जी देखवा लेंगे ।

श्री जयवर्धन यादव : महोदय, आश्वस्त कर दें काफी सदस्यों से कन्सर्न है । महोदय, मेरा आग्रह होगा पुनः मंत्री जी से

तारांकित प्रश्न सं0-656(श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय)

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कैमूर जिलान्तर्गत रामपुर प्रखंड के सबार पंचायत में स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय सबार के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना बी0एसआइ0डी0सी0एल0 को स्वीकृति प्राप्त हुई है । तद् आलोक में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना द्वारा इसकी निविदा की गयी है जिसमें मात्र 1 निविदाकार द्वारा भाग लिये जाने के कारण एक निविदा की स्थिति में इसकी पुनर्निविदा आमंत्रित की गयी है । इस पुनर्निविदा में दो निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया है जिसका तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है । अब तो टेंडर हो ही गया है शीघ्र इसका निर्माण हो जायेगा ।

श्रीमती रिंकी रानी पण्डेय : माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

टर्न-7/03.03.2020/ज्योति-पुलकित

श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेयः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाये ।

कार्यस्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 3 मार्च, 2020 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :

1-श्री महबूब आलम, 2-श्री सुदामा प्रसाद एवं 3-श्री मो0 नवाज आलम ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है । अब शून्य काल ।

(शून्यकाल)

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग..

अध्यक्ष : शून्य काल होने दीजिये ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत डोभी एवं आमस में बस पड़ाव..

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग का रोड मैप, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा..

अध्यक्ष : आप कभी बिना महत्व के मुद्दे को उठाते हैं क्या ?

श्री महबूब आलम : किसानों से धान की खरीद नहीं हो रही है ।

(इस अवसर पर मा0 सदस्य श्री महबूब आलम, श्री सुदामा प्रसाद एवं श्री सत्यदेव राम वेल में आकर बोलने लगे)

(व्यवधान)

श्री विनोद प्रसाद यादवः महोदय, गया जिलान्तर्गत डोभी एवं आमस में बसों के ठहराव के लिए कोई बस पड़ाव नहीं है। बसें जी0टी0 रोड के किनारे रूकती है, जिससे हमेशा दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है । जनहित में उक्त स्थानों पर बसों के ठहराव हेतु बस पड़ाव निर्माण कराने की माँग करता हूँ।

अध्यक्ष : महबूब जी, आप आसन को कोई भी ऐसा काम करने पर मजबूर नहीं करिये जो आपको अच्छा नहीं लगे । यह बटाईदार किसानों का अभी कुछ मुद्दा आया है क्या यह इस तरीके से अब समझ लीजिये तीन आदमी खड़े हैं एक ही दल के और तीनों के हाथ में तीन तख्ती है एक बटाईदार किसान है, एक कदवन जलाश्य है, एक धान खरीद है अब अगर ये सब लाईये तो आसन को कोई अप्रिय काम करने के लिए मजबूर नहीं करिये ।

श्री श्रवण कुमार मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रौपर डिमान्ड भी है, महोदय और जो माननीय सदस्य बात रखना चाहते हैं कृषि विभाग की डिमांड भी आ रहा है महोदय, जो बात कहना है महोदय, इस सदन में कृषि विभाग के डिमांड पर रखे । उसका जवाब सरकार देगी ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : महोदय, मानसी प्रखंड अंतर्गत चकहुसैनी पंचायत में पी.एच.डी. केक पंप हाउस बंद रहने से चकहुसैनी, खुटिया पंचायत एवं मानसी बाजार के लोगों को

शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है । अविलम्ब स्वच्छ आर्सेनिक और आयरण मुक्त जलापूर्ति सुविधा करावें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला मुख्यालय में रिक्शा/ई-रिक्शा चालकों के लिए पड़ाव नहीं होने के कारण रिक्शा/ई-रिक्शा चालकों को भारी कठिनाई होती है और बेवजह पुलिस कोपभाजन होना पड़ता है। अतः शहर में रिक्शा/ई-रिक्शा चालकों के लिए पड़ाव बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री सत्य नारायण सिंह : राज्यों में शहीदों को सम्मानित करने की स्वस्थ परंपरा है, जिसके अंतर्गत रोहतास जिलांतर्गत डेहरी ऑन सोन के तार बंगला मोड़ चौक का नामकरण अमर शहीद रवि रंजन के नाम पर किये जाने की मांग करता हूँ ।

विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया शहर को जाम मुक्त करने हेतु गुलाबबाग जीरोमाइल आरएन साह चौक रामबाग सहित दर्जनों स्थान पर इलेक्ट्रोनिक ट्रैफिक सिग्नल लगाने की आवश्यकता है। अतः सुचारु यातायात हेतु पूर्णिया में दर्जनों स्थान पर इलेक्ट्रोनिक ट्रैफिक सिग्नल की स्थापना करने की मांग करता हूँ ।

श्री श्यामबाबु प्रसाद यादव : पिपरा विधान सभा क्षेत्र सहित पूर्वी चम्पारण जिला के गन्ना किसानों का सासामुसा, सिंधवलियाँ हरखुआ चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान करने से किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय बनी हुई है। अतः किसानों के गन्ना मूल्य का शीघ्र भुगतान करने का मांग करता हूँ ।

श्री सरोज यादव : जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक-467, दिनांक 11.02.2020 एवं पत्रांक-514, दिनांक 15.02.2020 द्वारा सचिव योजना एवं विकास विभाग को श्री सीता राम श्रीधर कार्य पालक अभियंता, श्री अफताब आलम, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं सहायक अभियंता रामस्वरूप, प्रसाद के विरूद्ध अनुशासिक कार्रवाई करने की मांग करता हूँ ।

श्री रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, जिला मधुबनी प्रखंड अन्धराठाढ़ी ग्राम रखवारी थाना रुद्रपुर निवासी को दिनांक 29.02.2020 को दुकान से घर जाने के रास्ते में नीरज ठाकुर पिता श्री नारायण ठाकुर को छुरा मार कर मार दिया । अतः मैं दस लाख मुआवजा देने की माँग करता हूँ ।

श्री ललन पासवान : महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत नौहट्टा प्रखंड के कछुहर मोड़ से भवनवॉ नकटी होने हुए बुधुआ तक 10 कि.मी. पथ कच्ची है और आवागमन बाधित है । जनहित में पक्कीकरण कराने हेतु मांग करता हूँ ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया थाना के हरपुर किसुनी निवासी रुखसार खातून पति नूर आलम सहित उनके तीन बच्चों की हत्या दिनांक

19.02.2020 को कर दी गई । ये लोग काफी गरीब परिवार के है । आश्रितों को उचित मुआवजा सहित परिवार के अन्य सदस्यों के लिये सुरक्षा की माँग करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा भाई, वीरेन्द्र जी, पूरा सदन इस बात को समझेंगा । आज कृषि विभाग की मांगों पर तीन घंटे का विमर्श, वाद-विवाद, बहस है । एक आदमी बटाईदार का तख्ती लिये हुए है, एक आदमी धान का तख्ती लिखे हुए है, अगर आप किसानों की समस्या के प्रति ईमानदार है तो इसको बहस के दौरान उठाइएगा, तो सरकार जवाब देगी । अभी तख्ती लेकर बीच में आने से क्या होता है, नहीं-नहीं ये गलत है।

श्री विद्यासागर केशरी : महोदय, अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखंड अन्तर्गत मरियारी पंचायत के भट्टावाड़ी गाँव में अवस्थित संस्कृत महाविद्यालय से जाना होता है। जिसका भगनावशेष अभी भी मौजूद है, जिसके अंतर्गत 108 बीघा जमीन भी है, इसे पुर्नजीवित कर पठन-पाठन एवं भवन निर्माण की मांग करता हूँ ।

(इस अवसर पर सी.पी.आई माले के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गए ।)

अध्यक्ष महोदय : अब हम समझे कि क्यूं जगह पर वापस गए । अब उन्हीं का ध्यान शून्यकाल । देखिए-देखिए... सुदामा जी तैयार है, हम नाम नहीं पुकारे। अपना पढ़ने में कितने मुस्तैद है, लेकिन दूसरे पढ़ते है तो उसको व्यवधान डालते है ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, सहादरा (दिल्ली) झिलमील रोलिंग मिल में कार्यरत दीपक सिंह (28) पिता- स्व0 सूबेदार सिंह, ग्राम- सलेमपुर थाना चांदी, जिला भोजपुर की मौत 25 फरवरी 2020 को दिल्ली दंगे में हो गई । मृतक की पत्नी को 10 लाख रूपये और एक सरकारी नौकरी देने की माँग करता हूँ ।

श्री महबूब आलम : महोदय, बिहार में घाटे की खेती का भार बटाईदार किसानों ने अपने कन्धे पर उठा रखा है, लेकिन सरकार द्वारा संचालित कृषि लाभ इन्हें प्रमाणपत्र के आभाव में नहीं मिल पाता । राज्य की कृषि का 80 प्रतिशत भूभाग आबाद करने वाले बटाईदार किसानों का पंजीकरण कर पहचान-पत्र दिया जाए ।

श्री मो. नवाज आलम : भोजपुर जिलान्तर्गत आरा प्रखंड में इंदिरा आवास योजना लक्ष्य से काफी पीछे है दौलतपुर पंचायत में लक्ष्य 135 था लेकिन सिफ 51 इंदिरा आवास हुआ है । यही स्थिति सभी पंचायतों की है। मैं लक्ष्य को पूरा-पूरा करने एवं दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

श्री शत्रुघ्न तिवारी : अध्यक्ष महोदय, सारण जिलान्तर्गत अमनौर बाजार से एस0एच0-73 में निर्मित बाईपास सड़क के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती है, जिससे जानमाल की क्षति होती है ।

मैं बाईपास सड़क का निर्माण जनहित में करने की मांग करता हूं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला में 3245 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 220 केन्द्रों का संचालन झोपड़ी से किया जा रहा है, जहां बुनियादी सुविधाएं नहीं है । सरकार की कई योजनाओं का संचालन केन्द्र से हो रहा है।

अतः सभी केन्द्रों को भवन एवं बुनियादी सुविधा उपलब्ध करावे ।

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, तुरकौलिया प्रखंड के माधोपुर मधुमालत पंचायत में पूर्व मुखिया शब्बीर अहमद शेख टोला तथा शोहिल छपरा सहनी टोला में सपर्क पथ नहीं होने के कारण आवागमन ठप है ।

अतः जनहित में उक्त पथ को अवलिंब बनावे ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचना । माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद, सत्यदेव राम एवं अन्य छः सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना ।

ध्यानाकर्षण सूचना

सर्वश्री सुदामा प्रसाद, सत्यदेव राम एवं अन्य छः सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सोन नहर प्रणाली के लिए इधर सोन नदी में लगातार पानी का अभाव हो रहा है । इस वर्ष भी सोन नहरी इलाके में 40 प्रतिशत सूखा रहा । नहरों के लिए पानी तभी मिल पाता है, जब बाढ़ की स्थिति रहती है । उस पानी को रोक कर रखने हेतु वर्ष 1990 में कदवन डैम (इन्द्रपुरी जलाशय) का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया था । सोन नहरों का जीवन 140 साल हो जाने के कारण जीर्णशीर्ण नहरें किसानों की सम्पूर्ण सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

अतः सोन नदी में शीघ्रातिशीघ्र इन्द्रपुरी जलाशय का निर्माण करने और नहरों का व्यापक सर्वे कराकर मरम्मतिकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 1973 में अविभाजित बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बीच सोन नदी के जल के हिस्सेदारी के संबंध में हुये समझौते के अनुसार बिहार राज्य के लिये कुल उपलब्धता 7.75 एम0ए0एफ0 (मिलियन एकड़ फीट)है जबकि सिंचाई के लिये जल की

आवश्यकता 8 एम0ए0एफ आकलित है । बिहार राज्य हेतु सोन नदी बेसीन से कुल प्राप्त होनेवाले 7.75 एम0ए0एफ0 से मध्य प्रदेश स्थित बाणसागर डैम से 1 एम0ए0एफ0 जल एवं उत्तर प्रदेश स्थित रिहंद जलाशय से 2.59 एम0ए0एफ0 जल प्राप्त होता है ।

उक्त समझौते के लगभग 76 वर्षों के पश्चात् राज्य में फसल पद्धति, क्रॉप पैटर्न में बदलाव तथा सिंचाई तीव्रता में वृद्धि के कारण सिंचाई हेतु जल के मांग में भी वृद्धि हुई है । दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्त्तन के कारण वर्षापात में कमी हुई है एवं भूगर्भ जल स्तर में कमी हो रही है। इस वजह से समय-समय पर मध्य प्रदेश से पानी की उपलब्धता की कमी रहती है । दूसरी तरफ स्पष्ट है कि बिहार राज्य में सिंचाई हेतु सोन नदी के जल की मांग में वृद्धि हुई है, जबकि सोन नदी स्थित इन्द्रपुरी बराज पर जल की उपलब्धता में कमी आ गयी है । फलस्वरूप बिहार राज्य में सिंचाई हेतु जल के मांग अनुरूप बाणसागर का एकरारनामा एवं रिहंद एकरारनामा के अनुसार बिहार को आवंटित 1 एम0ए0एफ0, 2.59 एम0ए0एफ0 जल की आपूर्त्ति में कठिनाई हुई है।

वर्ष 1990 में कदवन डैम का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा कर तो दिया गया । परंतु यह योजना महज संचिकाओं एवं पत्रचार, अखबार तक ही सीमित रह गया । सोन बेसीन अंतर्गत रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, अरवल, गया एवं पटना जिले में सुनिश्चित सिंचाई सुविधा मुहैय्या कराये जाने के दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा दिनांक 14.02.2017 को रोहतास जिला के नौहट्टा प्रखंड के मटियांव गांव में प्रस्तावित जलाशय के स्थल की स्वयं निरीक्षण किया गया एवं इसके विभिन्न आयामों एवं अंतर्राज्यीय पहलुओं पर संबंधित अभियंताओं के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया ।

उक्त परिप्रेक्ष्य में कदवन जलाशय योजना वर्तमान में बिहार एवं झारखंड के विभाजन के पश्चात् बिहार भूभाग के लिये इन्द्रपुरी जलाशय योजना के रूप में नामित करते हुये दिनांक 28.06.2017 को संपन्न मंत्रीपरिषद् की बैठक में इन्द्रपुरी जलाशय योजना का विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार किये जाने के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी । डी0पी0आर0 तैयार करने का कार्य परामर्शी द्वारा दिनांक 21.08.2017 से किया जा रहा है । परामर्शी द्वारा योजना का पी0पी0आर0, हाईड्रोलॉजी पावर पोटेन्शियल अध्ययन, जियोलॉजी रूपांकन, बाढ़ गाद अध्ययन इत्यादि प्रतिवेदन स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग को समर्पित किया गया है । केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त पृच्छाओं का निराकरण कर उसे उपलब्ध करा दिया गया है । केन्द्रीय जल आयोग के अंतर्राज्यीय मामले निदेशालय-2, सिंचाई आयोजन निदेशालय, नीब अभियांत्रिक एवं

विशेष विश्लेषण निदेशालय तथा केन्द्रीय मृदा सामग्री अनुसंधालय,नई दिल्ली से प्राप्त पृच्छाओं का निराकरण कर केन्द्रीय जल आयोग को भेज दिया गया है । केन्द्रीय जल आयोग को समर्पित पी0पी0आर0 अंतर्राज्यीय दृष्टिकोण से झारखंड एवं उत्तर प्रदेश की सहमति नहीं प्राप्त होने के कारण पी0पी0आर0 की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार लगातार प्रयास में है ।

उल्लेखीय है कि इस योजना से उत्तर प्रदेश और झारखंड को सिंचाई का कोई लाभ नहीं है । परन्तु इसके कार्यान्वयन से उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में पड़नेवाले डूब क्षेत्र के अन्तर्गत रैयति भूमि के अधिग्रहण एवं वन भूमि की स्वीकृति हेतु उनका सक्रिय सहयोग अपेक्षित है । यद्यपि पी0पीआर की स्वीकृति प्रतिक्षित है परन्तु डी0पी0आर0 के विभिन्न प्रभाग का कार्य लगभग अंतिम चरण में है । पी0पी0आर0 की स्वीकृति के पश्चात् डी0पी0आर0 शीघ्र ही केन्द्रीय जल आयोग को समर्पित कर दिया जायेगा । इन्द्रपुरी जलाशय योजना के डी0पी0आर0 पर केन्द्रीय जल आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से मंजूरी एवं वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय,भारत सरकार से वन, पर्यावरण जलवायु परिवर्त्तन की स्वीकृति के पश्चात् इस योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ हो जायेगा । जवाब थोड़ा लंबा है महोदय ।

अध्यक्ष : इतना पढ़ने के बाद बोल रहे हैं कि लंबा है ।

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : महोदय, बस दो मिनट में हो जायेगा । मेरे द्वारा स्वयं दिनांक 02.03.2020 यानी कल इन्द्रपुरी बराज पर संबंधित अभियंताओं के साथ, महोदय, मुझे नहीं पता था कि आज यह ध्यानाकर्षण आनेवाला है । कल शाम में पता चला । लेकिन कल हमलोग दिनभर इन्द्रपुरी में बैठ करके पूरा इसी का हमलोग रिव्यू किये हैं और मैं कल वहीं डिहरी में था, डी0पी0आर0 तैयार किये जाने की समीक्षा की गयी और इसे तीन माह के अंदर तैयार करने का निर्देश दिया गया । जहा तक सोन नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण का प्रश्न है, इसे चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है । वह लंबा है कि क्या-क्या कराया जा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सुदामा जी आप पूरक प्रश्न पूछिये ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, इसकी कोई समय-सीमा तय करना चाहेंगे माननीय मंत्री जी ?

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : महोदय, मैंने तो बताया कि कल ही मैं वहां जा करके, कॉल अटेन्शन मेरे घर पर कल साढ़े 6 बजे आया है । कल सुबह इन्दुपुरी जाकर हमलोगों ने रिव्यू किया है और तीन महीना में इसका डी0पी0आर0 उसका जो भी डिटेल्स आना था, वह आ चुका है, तीन महीना में इसका डी0पी0आर0 सबमिट हो जायेगा । महोदय, सरकार बिल्कुल कृतसंकल्पित है और कदवन योजना, जिसका प्लेकार्ड लेकर माननीय सदस्य खड़े थे, इन्द्रपुरी परियोजना का काम जल्द ही शुरू हो जायेगा ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, धन्यवाद है और उम्मीद है कि इस काम को पूरा कर दें 3 या साढ़े तीन महीने में ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिये, साढ़े 3 महीने में क्या पूरा होगा ? माननीय मंत्री जी ने जो कठिनाईयां बताई, उसका संज्ञान आप लिये कि नहीं ? कदवन डैम जो बनना है तो उसके डूब क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और झारखंड का जमीन और एरिया आता है । मंत्री जी ने कहा है कि डी0पी0आर0 का काम जो मंत्री जी के मुस्तैदी और इनके लगे रहने के कारण 3 महीना में पूरा हो जायेगा। फिर उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश और झारखंड की सरकार अगर नहीं करेगी तो कठिनाई होती है ।

अब माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ का ध्यानाकर्षण सूचना ।

टर्न–9/अंजनी/दि0 03.03.2020

श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री संजय कुमार सिंह,स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार(परिवहन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले जे0पी0 सेतु, गांधी सेतु और राजेन्द्र सेतु भारी वाहनों के लिए बंद कर दिये गये हैं । सबसे पहले गांधी सेतु पर रोक लगाई गई फिर दिनांक 03.12.2019 से राजेन्द्र सेतु तथा दिनांक 03.02.2020 से जे0पी0 सेतु पर रोक लगा दी गई । इन तीनों पुलों पर भारी वाहनों के प्रतिबंध से उत्तर बिहार जानेवाली निर्माण एवं खाद्य सामग्रियों पर 125 किलोमीटर अतिरिक्त ढुलाई का भार पड़ेगा, जिसके कारण राज्य में महंगाई और बढ़ेगी ।

रेल विभाग ने मुख्य सचिव को जे0पी0 सेतु एवं राजेन्द्र सेतु खोलने हेतु सीसीटीवी कैमरे, दोनों छोर पर हाईट व साईड गेज एवं इलेक्ट्रॉनिक मोशन गेटवे लगाने की शर्त्त रखी है । इलेक्ट्रॉनिक मोशन गेटवे पूरी तरह से कम्प्यूटराईज्ड रहता है और पुल के दोनों छोर से गुजरने के दौरान यह पता चल जाता है कि लोड कितना है ।

अतः जे0पी0 सेतु एवं राजेन्द्र सेतु पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, दोनों छोर पर हाईट व साईड गेज एवं इलेक्ट्रॉनिक मोशन गेटवे लगाकर दोनों पुलों को चालू करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री संतोष कुमार निराला,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूर्व मध्य रेलवे द्वारा मुख्य सचिव, बिहार से जे0पी0 सेतु पर भारी वाहनों के परिचालन हेतु सीसीटीवी कैमरे दोनों छोर पर हाईट और साईड गेज एवं इलेक्ट्रॉनिक मोशन गेटवे लगाने का अनुरोध किया गया है

। उपरोक्त सुझावों पर कार्रवाई हेतु पथ निर्माण विभाग, परिवहन विभाग की बैठक रेलवे विभाग के साथ की जा रही है । वर्त्तमान में रेलवे द्वारा मुख्य सचिव, बिहार को जे0पी0 सेतु पर भारी वाहनों के परिचालन से सेतु को क्षति को देखते हुए भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में तात्कालिक रूप से भारी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंधित कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, इसपर अलग से बात हो रही है । चिन्ता हमलोगों की भी है और सरकार की भी चिन्ता है ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-10/राजेश-राहुल/3.3.20

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

<u>वित्तीय कार्य</u>

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण कृषि विभाग की अनुदान मांग पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा, इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है और इसी समय में से सरकार को भी उत्तर के लिए समय दिया जाएगा राष्ट्रीय जनता दल 60 मिनट, जनता दल यूनाइटेड 51 मिनट, भारतीय जनता पार्टी 40 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 19 मिनट, सी0पी0आई0एम0एस0 पार्टी 11 मिनट, लोक जनशक्ति पार्टी 2 मिनट, हिन्दुस्तानी आवामी मोर्चा 1 मिनट, ए0आई0एम0आई0एम0 पार्टी 1 मिनट, निर्दलीय 4 मिनट । अब माननीय मंत्री, कृषि विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करे ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

'कृषि विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 31,52,81,42,000/- (इक्तीस अरब बावन करोड़ इक्यासी लाख बियालीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।'

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष: इस मांग पर माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री मो0 नेमतुल्लाह एवं श्री कुमार सर्वजीत से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ये सभी व्यापक हैं, जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री

ललित कुमार यादव जी का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव जी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करे ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय जी, मैं कृषि विभाग पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मूव करता हूं । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित बजट 31,52,81,42,000/- (इक्तीस अरब बावन करोड़ इक्यासी लाख बियालीस हजार) रूपये की राशि में से 10 रूपये की राशि महोदय घटाया जाय.....

(व्यवधान)

महोदय मेरी पार्टी की ओर से माननीय सदस्य श्री सीताराम यादव जी कृषि विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलेंगे ।

श्री सीताराम यादवः अध्यक्ष महोदय जी, हम कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़े हुए हैं । महोदय, मैंने कृषि विभाग का बजट देखा और सुना तो लगा कि शायद किसानों के लिए कुछ होने वाला है लेकिन महोदय करोड़, अरब, खरब हम लोग सुनते हैं अब इसमें से सिर्फ बाबू लोगों के लिए ही माननीय मंत्री श्री प्रेम बाबू रखे हैं या किसानों के लिए भी कुछ रखे हैं । महोदय, कम से कम माननीय मंत्री जी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम भी तो दीजिए, आप बजट करोड़, अरब में पास करते हैं लेकिन किसान के लिए कृषि उत्पादन का जो जीन्श है उसको उसी दाम पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मैं किसानों की आय दोगुनी कर रहा हूं । महोदय, अब वह किस जंत्र और किस मंत्र से दोगुनी होने वाली है, यह बात हम माननीय मंत्री जी से आज जानना चाहते हैं कि वह कौन जंत्र और कौन मंत्र है जिससे मैं उनसे वह जंत्र और मंत्र लेकर के अपने इलाके में बांट दूंगा जिससे किसानों की आय बढ़ जाए । इन पर तो श्री राम जी की कृपा रहती है शायद वे ही दोगुनी कर दे । महोदय, अभी धान की खरीददारी बिहार में कहीं पर भी नहीं हुई है । महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी 12 सौ, 13 सौ रूपये की धान की खरीददारी हुई है, जो बिचोलिए के द्वारा खरीदा गया है । महोदय, 1840 रूपये भारत सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा धान का मूल्य तय किया गया है लेकिन किसानों को कहीं नसीब, अरे किसानों से जुड़ा हुआ मसला है विनोद बाबू चाहे सहकारिता हो या कृषि हो उन सभी में हम कृषक के हित की बात करते हैं किसान के हित की बात करते हैं, सदैव भूमि तो आप ही की है कृषि भी आप ही सहकारिता भी आप ही हैं इसलिए सुन लीजिए । थोड़ा-सा सुनने का कष्ट किया जाए श्रवण बाबू तथा महोदय, 1300 रूपया धान की खरीददारी हई है । खाद का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, कपड़ों के दाम बढ़ गए, दवाओं के दाम बढ़ गए लेकिन धान के दाम नहीं बढ़ने हैं, गेहूं के दाम नहीं बढ़ने हैं । एक

बात माननीय मंत्री जी से हम लोग पूंछना चाहते हैं कि अभी धान की खरीददारी नहीं हो रही है फिर गेहूं की खरीददारी भी नहीं होगी । अभी दो-चार रोज पहले हवा आई थी, ओले गिरे थे जिससे गेहूं की सारी फसल खराब हो गई । हमारे यहां खजोली प्रखण्ड में एक किसान हैं जिनका नाम कैलाश राव है उन्होंने रोते हुए हमें फोन किया कि हम तो लूट गए चार एकड़ में गेहूं की खेती की थी वो सारी फसल खराब हो गई गेहूं फूट गया था अब एक करवा उनको प्राप्त नहीं होगा । माननीय मंत्री जी का अरब का, खरब का ये जो बजट है महोदय, उसमें किसानों के लिए कुछ भी नहीं हैं । आप कह रहे हैं कि आप किसानों की आय दोगुनी करेंगे तो आप यह कैसे करेंगे, किस विधि से करेंगे । अभी गेहूं का भाव महोदय, 12 सौ, 13 सौ, 14 सौ रूपए प्रति क्विंटल तक बढ़ेगा और आप 2000 रूपया प्रति क्विंटल का फैसला करेंगे लेकिन यह किसानों को मिलेगा नहीं, महोदय पशुपालन में 25 रूपए प्रति लीटर में सुधा कंपनी वाला गाय का दूध खरीद रहा है । पानी बिक रहा है महोदय अमेरिका की कंपनी ने कहा था- महोदय, हमने देखा था और अखबार में पढ़ा था कि भारत में जितने भी पानी के बोतल हैं मिनरल वॉटर से भी गंदे हैं । किसी ने उसको चैलेंन्ज नहीं किया, चुनौती नहीं दी । वो गंदा पानी 20 रूपए प्रति लीटर में बिक रहा है और महोदय, जो अमृत है वह 25 रूपए प्रति लीटर में । हमने पढ़ा था मेट्रीकुलेशन में संस्कृत में शिषिरे ऋतु अग्नि, राजसम्मानम् प्रियदर्शनम् क्षीर भोजनम् अमृत तुल्यम् । महोदय, वह अमृत अब 25 रूपया में और गंदा पानी प्रेम बाबू का बिक रहा है 20 रूपया में । महोदय, विचार करने की बात है कि आज किसानों की जो दशा और दिशा है कि किसान का बेटा भी किसानी नहीं करना चाहता है, पशुपालक का बेटा भी पशुपालन नहीं करना चाहता है । महोदय, कहां से आएगा धान, गेहूं, दूध, दही, घी, मक्खन आदि बिहार में आप नोजवानों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम कृषि उत्पादित वस्तुओं का मूल्य तो आप उचित दीजिए ताकि आज गांव के नोजवान जो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं वे अपनी खेती करके पशुपालन करके गुजारा कर सकते हैं । आज तरह-तरह की घटनाएं शहरों में, देहातों में हो रही हैं किसानों के घरों में डकैती हो रही है, दुकानदार लूटे जा रहे हैं, पेट्रोल पंप लूटे जा रहे हैं ।

क्रमशः

क्रमशः

श्री सीताराम यादवः प्रेम भाई मोटे होते जा रहे हैं और वजन इनका बढ़ता जा रहा है। चिंता हमलोगों को इस बात की है और चारों तरफ जो घटनाएं हो रही हैं चूंकि नौजवान बेकार है और बेकार दिमाग एक एटम बम से ज्यादा खतरनाक होता हैं। महोदय, इसलिए मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री और बिहार सरकार से दरख्वास्त और अपील करूंगा कि कृषि उपज का दाम वाजिब होना चाहिए, दूध का दाम महोदय 100 रुपये लीटर होना चाहिए ताकि दो-चार भैंस भी किसान पालकर अपना गुजारा कर सके। छत्तीसगढ़ की सरकार महोदय 2500 रुपये क्विंटल धान की खरीददारी कर रही है। प्रेम बाबू कमजोर वर्ग से आते हैं, एनेक्सचर-1 से आते हैं, किसान के घर में ये जन्म लिये होंगे इसलिए किसान के प्रति इनको पीड़ा होनी चाहिए। मधुबनी जिला के ये प्रभारी मंत्री भी हैं लेकिन मधुबनी जिला में धान की खरीददारी नहीं हो रही है। कैसे उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिलेगा और किसान अपना पेट काटकर जो उपज देता है आप उसकी उपलब्धि गिनाते हैं कि हमारी सरकार की यह उपलब्धि है। महोदय, खाद का दाम 266 रुपये यह यूरिया के बोरा पर लिखा रहता है महोदय और वह यूरिया का बोरा 350 रुपये से लेकर 375 रुपये तक में बिकता है आप इसकी तहकीकात और जांच करवा लीजिए आप किसान के हितैषी हैं, आप किसान की हित की बात करते हैं और अरबों-खरबों में बजट पास करते हैं और किसानों की आय दोगुना नहीं कर रहे हैं, किसानों के आंख में धूल झोंक रहे हैं ये कैसे चलेगा महोदय, चिंता करने की बात है। मेरा आसन से भी दरख्वास्त होगा महोदय कि आप सरकार को निर्देशित करें और आदेश दें, निर्देश दें कि किसानों के प्रति सरकार जिम्मेवार हो। महोदय, सिर्फ मंदिर ही हमारी उपलब्धि नहीं है सिर्फ राम का मंदिर बना देंगे और खेती नहीं करेंगे तो भगवान राम उसमें उपज नहीं बढ़ा देंगे तो हमारे मित्र जो भगवान के प्रति जितना आस्थावान हैं उतना ही उनको किसानों के प्रति भी आस्थावान होना चाहिए इनसे हमारी ये उम्मीद और आशा है महोदय। महोदय, हम पशुपालन में एक चीज देख रहे हैं, पशुओं में तरह-तरह की बीमारियां हो रही हैं लेकिन महोदय हमारे जिला में एक तरफ से 5 ब्लॉकों में इनके कोई डॉक्टर नहीं है। मधुबनी जिला के कलुआही में कोई डॉक्टर नहीं है पशुपालन में, बासोपट्टी में कोई डॉक्टर नहीं है, हरलाखी में भी महोदय कोई डॉक्टर नहीं है, मधवापुर में महोदय कोई डॉक्टर नहीं है। एक तरफ से 5 प्रखण्ड हमारे यहां डॉक्टरविहीन है। हमने देखा है महोदय, हम पहले मुखिया और ब्लॉक के उप-प्रमुख होते थे, हमने देखा है कि ब्लॉक में 2 डॉक्टर होते थे एक टी.भी.ओ. और बी.ए.एच.ओ.। महोदय, वहां पशुधन सहायक होता था, वैक्सीनेटर होता था, आज एक भी डॉक्टर नहीं है, एक भी पशुधन सहायक नहीं है, वहां पर कुर्सी-टेबल नहीं है महोदय, बासोपट्टी में आपका अस्पताल टूटा हुआ है,

उसका भवन नहीं है और आप किसानों के हित की बात करते हैं, किसानों की आय दोगुना करने की बात कर रहे हैं लेकिन कहीं डॉक्टर तक नहीं है। महोदय, हम देखते थे प्रखंड में कृषि पदाधिकारी होते थे उस समय बी.एस-सी (ए.जी.) करके लोग जन-सेवक हुआ करते थे, प्रत्येक पंचायत में एक-एक जन-सेवक होता था। आज महोदय, किसान सलाहकार आपने बनाया है वे लोग भी चिल्ला रहे हैं, हंगामा और हल्ला कर रहे हैं कि सरकार हमारे पेट पर लात मारी है। बी.एस-सी, एम.एस-सी. लोगों को आपने बहाल किया है लेकिन आप उनलोगों के साथ धोखा दे रहे हैं। आपने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तो नहीं दिया और आप जो कर्मचारी दे रहे हैं उनको भी उचित पारिश्रमिक नहीं दे रहे हैं, 12 हजार या 10 हजार रुपया ही उनको मिल रहा है। तमाम लोग हमको घेरे हुए थे सेशन शुरू होने से पहले महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र के सभी कृषि सलाहकार, किसान सलाहकार आये थे कि हम लोग उनकी बात को सदन के अंदर उठायें। नीतीश कुमार जी समाजवादी विचारधारा से आते हैं, भाजपा के पक्ष में जाने से शायद वे किसान विरोधी हो गये है कि क्या हो गये हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि वो जिस स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, लोहिया जी की पाठशाला में, कपूर्री जी की पाठशाला में पढ़े हैं वे थोड़ा सोचें गरीब के प्रति, किसान के प्रति, मजदूर के प्रति, गांव के प्रति, देहात के प्रति उनको सोच बदलना चाहिए, भगवान करे बदलना चाहिए । महोदय, आपका एक भी स्टाफ नहीं है, सारा कर्मी आपका फेल है, आप कहीं भी बहाली नहीं करने जा रहे हैं, कैसे होगा किसान का उदय, कैसे कृषि का भाग्य बदलेगा, बिहार में कोई इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री या कल-कारखाना नहीं है, किसानों की ऊपज का आप उचित दाम देंगे नहीं तो कृषि कार्य कौन करेगा, किसानी की बात कौन करेगा अगर आपको नहीं आप देखेंगे। महोदय, वन्य जीव का उत्पाद चारों तरफ हड़कम्प मचाये हुए हैं गांव में महोदय, नील गाय चारों तरफ किसान को परेशान किये हुए हैं, बनैला सुअर महोदय आलू की खेती हमलोग के इलाके में खत्म हो गया, सकरकन्द जो अलुआ की खेती होती थी नगदी फसल में उसकी गिनती होती थी खत्म हो गया, गोभी की खेती, बैगन की खेती महोदय, समूचा वह फल को खा रहा है कहीं कोई खेती नहीं हो रही है। बंदर का उत्पाद महोदय इतना पहुंच गया है कि तैयार धान को चीरकर वह बंदर नोच के फेंक दे रहा है।

अध्यक्ष: अब आपका दो मिनट बचा है।

श्री सीताराम यादव: महोदय, किसान तबाह है, दो मिनट है महोदय मैं बोल ही रहा हूँ। मैं अपील करूंगा आपसे, किसान परेशान है, किसान तबाह है, किसानों की बदहाली को महोदय समझा जाय और सुअर को मारने का उपाय किया जाय। अच्छा ठीक है दो मिनट और बढ़ा दिया जाय। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपने बनाया तो ठीक है, वन्य जीव

संरक्षण अधिनियम बनाया, किसानों की खेत को लूटने के लिए, किसानों की जो पुस्तैनी कृषि कार्य है उसको लूटने के लिए, हमारे जिले में महोदय तीन-तीन ईंख का मिल था लोहट, रैयाम और सकरी । माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे महोदय, मैं उनको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जबतक इस चीनी मिल से धुआं नहीं निकलेगा तो हम वोट मांगने नहीं आयेंगे । मिल बिक गया महोदय और उसके निर्माण का कहीं दूर-दूर तक हमलोग कोई कार्य शुरू होते नहीं देख रहे हैं । माननीय मंत्री जी से हम अपील करेंगे कि आप किसान के बेटे हैं, आप उस चीनी मिल को कम से कम चालू करने का काम करिये । इतिहास को स्वार्णाक्षरों में अपना नाम प्रेम बाबू लिखवा लीजिये, यह हमलोग आपसे दुआ करते हैं, हम उम्मीद करते हैं प्रेम बाबू आप किसान के बेटे हैं, कृषक हैं, चीनी मिल को आप चालू करवाइये । नगदी फसल है, महोदय अच्छा गया शहर से जीतते हैं, घर इनका जरूर देहात में होगा, नहीं अच्छा शहर के हैं तब तो हम निराश हो जायें इनसे कोई आशा, अपेक्षा और कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं, अच्छा चलिये और प्रेम बाबू आपको ये लोग शहरी बना रहे हैं, हम तो देहाती बना रहे थे लेकिन ललित जी देहाती नहीं शहरी बना रहे हैं फिर भी आपसे उम्मीद जरूर है कि आप जरूर कुछ करेंगे अरबों-खरबों का बजट आप पास कर रहे हैं, किसानों को हमलोग नेपाल में अभी प्रेम बाबू ईंख बेच रहे हैं । चूंकि हम नेपाल के बोर्डर पर से आते हैं पिछली बार ईंख मंत्री थे मोतिहारी वाले, उनका नाम भूल रहे हैं खुर्शीद साहब से हमने अपील किया था और इन्होंने किया तबतक नेपाल से हमलोग ऑर्डर करवा लिये। नेपाल की सीमा क्षेत्र में चीनी मिल है आपको बोर्डर से 10 कि0मी0 के बाद, वहां खरीददारी होती है और इंडिया के लोग ले जाकर के नेपाल में अपना ईंख बेचते हैं । हमारा मुल्क इतना बड़ा, इतना सामर्थ्यवान है लेकिन नेपाल के सामने आपकी गिनती कुछ नहीं कहते हैं कि हम इतना उन्नत कर गये, हम चन्द्रमा पर पहुंच गये पहुंचिये, अब मंगल ग्रह पर पहुंच गये पहुंचिये, एक से एक मिसाईल बना रहे हैं लेकिन कृषि के क्षेत्र में आप क्यों आंख मूंदे हुए हैं, क्यों कृषि के प्रति ख्याल नहीं रखते हैं, क्यों किसान विरोधी हैं, क्यों गांव विरोधी हैं, क्यों मजदूर विरोधी हैं, एक से एक मिसाईल आपने बनाया लेकिन आज भी हम इन्द्र के कृपा के पात्र बने हुए हैं। आज भी हम जब रोहणी नक्षत्र आता है हम किस स्तर पर खेत को जोतते हैं, उसमें हेंगा देते हैं और हम आकाश की ओर ताकते रहते हैं कि कब वर्षा होगी। हम आपके किसान डायरी किताब में पढ़ते हैं कि रोहणी नक्षत्र में बीजारोपण करना चाहिए लेकिन आप पानी नहीं दे रहे हैं। हमलोगों को कांग्रेस के जमाने में 90 प्रतिशत छूट होती थी, अनुदान से हम बोरिंग गड़ाये थे, हम मुखिया थे, प्रमुख थे, हमने बोरिंग गड़ाया था आप कहां चले गये, आप कांग्रेस को कोसते रहते हैं लेकिन आप हैं कहां? पम्पिंग सेट

मिलता था, बोरिंग मिलता था, हम देखते थे ब्लॉक में पाईप लोहा का पाईप जाम लगा हुआ रहता था इतना-इतना ऊंचा(क्रमशः)

टर्न-12/मधुप-हेमंत/03.03.2020

..क्रमशः..

श्री सीताराम यादव : आप कहाँ हैं, महोदय । क्यों नहीं आपका ध्यान उधर जाता है ? हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, श्मशान, कब्रिस्तान, इमरान, क्या-क्या करते रहते हैं, रात में, दिन में आप यही सपना देखते हैं ? कभी इधर भी तो देखिए, गाँव को देखिए, गरीब को देखिए, किसान को देखिए, मजदूर को देखिए, गाँव की हालात और उसकी काया को पलटने का काम करिये । माननीय मंत्री महोदय, चूंकि आप किसान हैं, आप गरीब हैं, आप उपेक्षित समाज से आते हैं, आपने अपमान-उपेक्षा को, तिरस्कार को करीब से देखा है, इसलिए हमारी पीड़ा से, हमारे दुःख से आप पीड़ित और दुःखी अवश्य होंगे । यह हम आपसे अपेक्षा रखते हैं । लेकिन न जाने आपका हृदय क्यों वज्र का हो गया है, क्यों पत्थर हृदय आप हो गये हैं ? एक बार तो आप पसीजिये । आप लोग कहते हैं कि हम पत्थर को पूजते हैं, तो वह भी रीझते हैं लेकिन आप पत्थर हैं कि क्या हैं, आप क्यों नहीं रीझ रहे हैं ? हम तो कबीर मत से जुड़े हुए हैं, हम तो पढ़े हैं कबीर के स्कूल में - पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली जो पीस खाये संसार । लेकिन आप तो इसके विपरीत हैं । इसीलिए महोदय, आपसे दरख्वास्त है, आपसे अपील है कि आपका हृदय इस बार हमारी प्रार्थना पर, हमने जो हृदय से आपसे अपेक्षा और उम्मीद जो रखी है, उसपर आप पसीजेंगे, हमारे खेतों में पानी जायेगा ।

महोदय, आज हमारे यहाँ कमला कैनाल है । कमला कैनाल आपका अगस्त में खुलता है । वह भी जब बाढ़ आ जायेगी, उसी बाढ़ में आपकी नहर भी अपना कमाल दिखा देगी और कहेगी कि हमने खोल दिया । जबकि नियम हम जानते हैं, 15 जून तक पानी खुल जाना चाहिए, पानी आपका अगस्त में खुलता है । वह नहर फेल हो रही है इसलिए इधर से लोग कह रहे थे कि सहकारिता का है, यह सिंचाई का है, हम तो जानते हैं कि सब भूमि प्रेम बाबू की है । सब आपका है । इसलिए सिंचाई की भी व्यवस्था किसान के हित में बढ़िया हो, इसकी व्यवस्था करिये और जितने स्टेट ट्यूबवेल आपके हैं, सभी बन्द पड़े हैं ।

(व्यवधान)

एक सेकंड - एक सेकंड । सारे स्टेट ट्यूबवेल आपके बन्द हैं, आप किसानों को निजी बोरिंग दे नहीं रहे हैं । कम से कम आप बिजली फ्री कर दीजिये । आप श्रीमुख से घोषणा करिये कि कृषि कार्य के लिए बिना पैसे के हम बिजली देंगे और 24 घंटे देंगे । लोग कह रहे हैं कि हम बिजली देंगे लेकिन देंगे और एक घंटे बाद कट गयी, आयी और कट गयी, वह नहीं । कृषि कार्य के लिए कम से कम 24 घंटे बिजली चाहिये। नहीं तो मजदूर आज के खेत में आपका इंतजार नहीं करेगा, मजदूर खेत से भाग जायेगा ।

महोदय, खाद उचित होना चाहिए, बीज उचित होना चाहिए । हम आज भी खेती करते हैं और पशुपालन भी हम करते हैं । आप जाइये, आपका बीज अभी कोई फूट गया और कोई गम्हर में भी है और कोई बीज आपका फूट गया । आपके सरकारी बीज का हम यह हाल कहते हैं, कोई बीज फूट गया है और कोई गम्हरा में है । कभी-कभी हम देखते हैं, आपके बीज में अन्न नहीं होता है । अब धान खखरी हो गया, गेहूं का बीज पूरा काला हो गया । शीश, मकई में दाने नहीं हो रहे हैं और आप बॉह चढ़वा रहे हैं कि बिहार में न्याय के साथ विकास हो रहा है । यह कैसा न्याय, यह कैसा विकास, किसका विकास, प्रेम बाबू का विकास या नन्द किशोर का विकास, किनका-किनका विकास हो रहा है, रामनारायण बाबू का विकास ? कभी इधर भी तो देखिये, महोदय ।

अध्यक्ष : सीताराम बाबू, आप सब कुछ देख रहे हैं, मेरी बत्ती नहीं देख रहे हैं । आप बत्ती अगर देख लिये तो हम ऑफ कर दें !

श्री सीताराम यादव : बहुत-बहुत धन्यवाद आपको । महोदय, आपने हमको बोलने के लिए समय दिया । मैं आपसे पुनः दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ और समय बढ़ाया जाय ।

महोदय, मैं एक चीज और पढ़ना चाहूंगा । हम किसानों के कर्ज की भी माफी चाहेंगे । किसानों के कर्ज की भी हम माफी चाहेंगे, आप अपना नाम अमर अक्षरों में लिखवा लीजिये प्रेम बाबू, आप कैबिनेट के भी मेम्बर हैं, आप कैबिनेट में इस बात को पुरजोर तरीके से उठाइये कि किसानों का कर्ज माफ हो । आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, हमलोग जानते हैं, आप प्रधानमंत्री के यहॉ भी जाकर मजबूती से उठाइये, आप बिहार में किसानों को मजबूती से मदद करिये, किसानों के हित की बात करिये और हम एक चीज जानते हैं कि जो किसानों के हित की बात करेगा, वही इस देश पर राज करेगा । आप नहीं करने जा रहे हैं, आगे आने वाले समय में हमारे नौजवान तेजस्वी प्रसाद यादव, उनका रास्ता कोई रोकने वाला नहीं है, बिहार की पुकार, नौजवानों की पुकार, गरीबों की पुकार, किसानों की पुकार.....

अध्यक्ष : श्री मेवालाल चौधरी ।

श्री मेवालाल चौधरी : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । महोदय.... (व्यवधान) सीताराम बाबू, अब हमें भी कुछ बोल लेने दीजिये ।

अध्यक्ष : मेवालाल जी, आप अपनी बात जारी रखिये ।

श्री मेवालाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने सीताराम बाबू का बड़ा जोशीला भाषण सुना लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य है कृषि का, हमारे हिसाब से बिल्कुल उल्टा है । आज तकनीक का जमाना है, सर । हम लोग अगर पारंपरिक खेती करते रहेंगे जिसको हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग कहते हैं अगर करते रहेंगे तो शायद हम लोग भी वो अचीव नहीं कर पायेंगे जो आज बिहार ने अचीव किया है । जब से माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय सुशील मोदी जी ने कृषि रोड मैप का एक टार्गेट फिक्स किया है । अगर हम पिछले चार साल का, हम 2005 से कम्पेयर नहीं कर रहे हैं, हम लोग उससे तुलना नहीं कर रहे हैं । अगर पिछले चार साल का ही डेटा देखेंगे, लगातार, हमारा चाहे वह गेहूं हो, चाहे वह चावल हो, चाहे वह मक्का हो, चाहे वह सब्जी हो, इन सबकी उत्पादकता बढ़ी है, सर । हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं । अगर हमारा एरिया बढ़ेगा तो प्रोडक्शन स्वाभाविक तौर पर बढ़ जायेगा । लेकिन आप देखेंगे कि उत्पादकता बढ़ी है जिसके लिए हमारे माननीय कृषि मंत्रीजी माननीय प्रधानमंत्री से दो-तीन बार कृषि कर्मण अवार्ड लेने गये और बिहार का नाम गौरवान्वित हुआ है । सर, अगर आप दूध का उत्पादन और अण्डा का उत्पादन देखेंगे तो हमने रिकॉर्ड पैदा किया है और आज जो परिप्रेक्ष्य है जिसकी बात कर रहे थे, सिंचाई की बात कर रहे थे, मछली उत्पादन की बात कर रहे थे । सर, हमारे राज्य में मछली की जो खपत है, अभी भी उस खपत को पूरा करने के लिए हम लोग हैदराबाद से मछली लाया करते थे लेकिन सर, बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है कि इस साल जो मछली का उत्पादन बिहार में हुआ है... (व्यवधान) ललित बाबू जो फिगर है, जो इस बार उत्पादन हुआ है, जो हमारी रिक्वायरमेंट 6.7 लाख मेट्रिक टन है उसके अगेन्स्ट में हम लोग 6.2 लाख मेट्रिक टन पैदा कर रहे हैं.... (व्यवधान) और हम बता दे रहे हैं सिर्फ दो साल के अंदर, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम चल रहा है । जितने भी आहर, पईन, नदी, तालाब की उड़ाही हो रही है । हम लोग उम्मीद करते हैं .... (व्यवधान) सुन लीजिए, सुन लीजिए अमन बाबू, सुन लीजिए ये सब डेटा कभी नहीं सुनियेगा, आप जान लीजिये, जानकारी भी ले लीजिये थोड़ी-सी । आने वाले..... (व्यवधान)

सर, सुन लिया जाये । सर, 2022 तक हम लोग उस पोजिशन पर आ जायेंगे कि हम लोग मछली का..... (व्यवधान) हम लोग मछली कम-से-कम नेबरिंग कंट्री में, जैसे नेपाल हो, म्यांमार हो, हम लोग एक्पोर्ट करने की पोजिशन में हो जायेंगे ।

...क्रमशः...

टर्न-13/आजाद:अंजली/03.03.2020

..... क्रमशः .....

श्री मेवालाल चौधरी : महोदय, हम सब्जी के उत्पादन में पिछले दो साल से द्वितीय पोजीशन में हैं और उस पोजीशन को बरकरार रखे हैं । महोदय, मेरा कुछ अपना सुझाव होगा, हम सोचते हैं माननीय लोग कुछ सुनेंगे । महोदय, आज के दिन में हमलोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में गये हुए हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, जिसके लिए लोग प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं और उम्मीद है कि अगले साल से वह प्रोडक्ट भी बाजार में आने लगेंगे । हम माननीय कृषि मंत्री जी से एक-दो चीज कहना चाहेंगे कि कृषि मंत्री जी हो सकता है कि हम आने वाले दो साल के अन्दर वेजीटेबुल में पहला भी स्थान हम कर लें पूरे भारतवर्ष में । हमलोगों को चाहिए कि हमारी कोई भी सब्जी बाहर नहीं जा पा रही है किसी कारणवश और जो अभी एक नारा दिया गया है एक जिला -एक सब्जी या कोई भी क्रौप लगाया जाय । महोदय, हमारे पास प्रोडक्शन होगी, हमारे पास उत्पादन होगा, जरूरत है कि हमलोग एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ काम करें । महोदय, मेरा निवेदन कृषि मंत्री जी से होगा कि हमलोग जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सपोर्ट प्रोमोशन पॉलिसी बनी है, हमलोग क्या स्टेट एग्रीकल्चर प्रोमोशन पॉलिसी के बारे में सोच सकते हैं जिसमें सेंटर लॉकेट कर दिया जाय, वहां पर सारी फैसिलीटीज बना दी जाय, चाहे वह कलेक्शन सेंटर हो, चाहे वह ग्रेडिंग सेंटर हो, चाहे पैकिंग सेंटर हो और वही से जो हमारे अच्छे वेजीटेबुल हैं, गुणवत्ता वाले वेजीटेबुल हैं, उसको हम बाहर भेजकर के कृषि का आय, किसानों के आय को हमलोग बढ़ा सकते हैं । महोदय, किसानों का आय दुगना होगा ।

महोदय, एक बात हमने पिछले बार भी कहा था कि हमारे पास जितने भी ग्रोवर्स हैं, जितने भी फामर्स हैं, जितने भी एक्सपोटर्स आज के दिन में कन्ट्री में एवेलेबुल हैं, जितने भी सप्लायर्स हैं, उसका एक डाटा बैंक बना दिया जाय और जो भी किसान प्रोग्रेसिव किसान हो, जो भी किसान एक उन्नतशील किसान हो, उसका

डाटा बैंक में नाम आ जाय । महोदय, अगर ललित बाबू बहुत अच्छे सब्जी पैदा करते हैं और उनके पास ग्रोवर्स जो एक्सपोटर्स का लिस्ट है, वह सीधे कंट्रेक्ट करके अपने सब्जी को बाहर बेच सकते हैं ।

महोदय, मेरा दूसरा सजेशन होगा, मेरा दूसरा एक बहुत अच्छा सुझाव होगा, हमलोग माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमलोग एक स्मॉल फारमर्स एग्री बिजनेस कन्सोर्टियम नाम पर जिस तरह से जीविका चला रहे हैं, जिसमें हम जीविका दीदी का हमलोग कम से कम वह अपने पैर पर खड़ा होकर के अपनी जीविका का पालन कर रहे हैं तो क्या सर हमलोग छोटे किसान का, स्मॉल फारमर्स एग्री बिजनेस कन्सोर्टियम के रूप में चलावे । छोटे-छोटे किसान जिनके पास जमीन उपलब्ध नहीं है, जिसका जो मार्जिनल फारमर्स हैं, वैसे किसान को महोदय हमलोग अगर उसको प्रोफेशनली स्पेशलाईज ट्रैनिंग कर दें, जैसे मशरूम प्रोडक्शन का, हनी प्रोडक्शन का अगर हमलोग उसको प्रोफशनल ट्रैनिंग दे दें तो उन लोगों का भी आय बढ़ जायेगा और हमारा जो टोटल जी0डी0पी0 विकास की बात कर रहे हैं, उसमें हमारा ग्रोथ होगा । महोदय, इस दिशा में हम माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इसपर विचार करें ।

महोदय, आज सीड की समस्या है । अभी सीताराम बाबू कह रहे थे कि अभी जो भी बाहर से सीड आ रही है, कभी उसमें मक्का का दाना नहीं लगता है, कभी धान नहीं लगता है । महोदय, बहुत बड़ी समस्या है, चूँकि प्राइवेट कम्पनी इतने एग्रेसिव होते हैं, प्राइवेट कम्पनी अपने सेल्स को इतनी मजबूती से समाज में ले जाते हैं । वह जो चैनल है, हमारे माननीय मंत्री जी के अधीन है, हमलोग उनके वेरायटी को अच्छी तरीके से टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं । सर, जरूर सरकार इसपर एक फैसला ले कि कोई भी प्राइवेट किसान अगर अपना बीज बिहार में बेचना चाहती हो तो एक सरटेन नौर्म्स हो, एक सरटेन रूल्स हो कि वह अपने तीन साल बीज को जरूर बिहार में पैदा करें ताकि जो भी एग्रो क्लाइमेटीक हो, सीड्स के लिए, वह उसके लिए आइडियली शुटेबुल हो, उसी के आधार पर अपना बीज का चुनाव करें और चुनाव के आधार पर वे अपने बीज को बेचें अन्यथा उनको एलाऊ नहीं किया जायेगा । सर, जो समस्या हर साल आती है, कभी मक्का में समस्या आती है, कभी गेहूँ में बाली नहीं लगती है, कभी धान में समस्या होती है तो शायद इस समस्या से निजात हो जायेगा और जो सीड्स का प्रोब्लम आ रही है हर साल, उस सीड्स के प्रोब्लम को हमलोग खत्म कर लेंगे ।

महोदय, मैंने एक निवेदन भी किया था पिछले साल किसी क्वेश्चन के माध्यम से, आज हम फारमर्स का इनकम दुगुना करना चाह रहे हैं । महोदय, जब तक

हम अपने टेक्नोलॉजी से अपने किसान को मजबूत नहीं करेगे, जब तक हमारी तकनीकी चाहे वह बिहार की हो या हिन्दुस्तान के किसी कोने की हो, उस तकनीकी से हम किसान को मजबूत नहीं करेंगे, शायद हमलोग आय को दुगुना नहीं कर पायेंगे । चूँकि कृषि का एक नियम है लागत कम हो और उचित समय पर कृषि कार्य की जाय, उस समय हमेशा उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ती है। मैंने सर इसी कन्सर्न में पिछले साल निवेदन किया था कि क्या यह संभव है कि पंचायत स्तर पर हमलोग एक नॉलेज बैंक, एक ज्ञान का बैंक बनाये जिसमें वैसे 10 आदमी, 10 व्यक्ति उनको प्रोफेशनली ट्रैंड करके, हमलोग उनको यह नहीं कह रहे हैं कि हमलोग उनको मानदेय दें, उनको प्रोफशनली ट्रैंड करके ज्ञान को अपना बांटे अपने किसानों के बीच में, शाम को हो, सुबह हो या जब भी हो, उनके पास यह भी फैसिलीटीज क्रियेट कर दिया जाय ताकि आय और इच्छा से वह हर चीज के बारे में डिसकस करे । महोदय, हमलोग इसके पहले भी एक स्कीम था सरकार की और अभी सरकार की चल रही है एग्री क्लीनिक एक स्कीम थी, जिसमें ग्रेजुयेट को हमलोग फाईनेंसियल सपोर्ट देते और उस फाईनेंसियल सपोर्ट से अपना क्लीनिक खोलता था, अपनी छोटी स्वायल टेस्टिंग लेबोरेटरी होती थी, अपना थोड़ा सा पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी होता था । अगर किसी तरह की समस्या आती थी, किसी किसान की समस्या आती थी तो वह एग्री क्लीनिक में जाते थे और समस्या का समाधान करते थे । महोदय, वही सिस्टम को रि–इन्ट्रोड्यूस करने की जरूरत है, दोबारा लाने की जरूरत है ताकि सर किसानों को एक कंफिडेंस बिल्डअप होने की जरूरत है । आज किसान लेक कर रहा है वह देखता है कि हम कौन सी वेरायटी लगायें, आज हमलोग क्लाइमेट और ग्लोबल चेंज की बात कर रहे हैं । सर, इतना प्रभाव है कि हमलोग हर साल 1.5 डे डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। सर, आप सभी जानते हैं कि पहले गेहूँ का सोईंग हमलोग अक्टूबर माह में करते थे, आज गेहूँ हमलोग दिसम्बर माह में भी करते हैं तो उसकी जर्मेशन कभी–कभी कम होती है । कारण यह है कि हमारा टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । वही वेरायटी हमलोग ग्रो कर रहे हैं जिसके कारण कभी जर्मेशन नहीं होता है और वह अच्छी ऊपज नहीं दे पाती है।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : आपका दो मिनट समय बच रहा है ।

श्री मेवालाल चौधरी : सर, जरूरत है यहां पर जितने भी रिसर्च ऑरगनाईजेशन डेवलपमेंट को हैंड टू हैंड साथ मिलकर चलेंगे और जो किसान की जरूरत है , उस किसान के जरूरत के अनुसार ही तकनीकी का विकास किया जाय और किसान को उस तकनीकी को देखकर के ही उनको यह बताया जाय कि ऐसे समय में आप करेंगे तो शायद आपको बहुत सफलता मिलेगी । सर, एक बड़ी समस्या है बाजार की समस्या है, आज देखेंगे

सर पंचायत में हर गांव में छोटे-छोटे बाजार लगते हैं, हमारे पास भी स्कीम है, सरकार के पास भी स्कीम है । लेकिन किसी कारणवश बैंक के नॉन कॉ-ओपरेशन से सर स्कीम सैंक्शन हो जाती है, सरकार स्कीम को मंजूरी दे देती है लेकिन बैंक के नॉन कॉ-ओपरेशन से बैंक उनको सपोर्ट नहीं करती है, उस तरह का स्कीम नहीं आ पाती है । सर, आज जितनी उत्पादन हो रही है, अगर उससे जो लौसेस हो रहे हैं, अगर उस लौसेस को ही बचा लें तो तकरीबन हम 25 हजार करोड़ का सेविंग करेंगे । सर, हमारा निवेदन माननीय कृषि मंत्री जी से यह होगा कि जहां पर हमलोग इस तरह का स्टेट एग्री एक्सपोर्ट सेंटर क्रियेट करना चाहते हैं, सर वही पर एक माइक्रो प्रोसेसिंग लगा दिया जाय और छोटे-छोटे किसान जो बाजार में नहीं बेच पाते हैं, बाजार में स्टोर्स में नहीं रख पाते हैं सर, वह अपना प्रोडक्ट लाकर के माइक्रो प्रोसेसिंग कर लें ताकि जो उसका प्रोडक्ट जो है, उसको बाजार में जाकर बेचें और वह शो कर लें ।

महोदय, कहने को बहुत था, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

टर्न-14/शंभु-धिरेन्द्र/03.03.20

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : श्री विद्या सागर केशरी ।

श्री विद्या सागर केशरी : सभापति महोदय, मैं वर्ष 2020-21 के लिए पेश कृषि विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, एक कहावत है कि सुनियोजित काम के अच्छे परिणाम मिलते हैं । यहां तक कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी राज्य सरकार ने सुशासन एवं न्याय के साथ विकास के सिद्धांत को लागू करते हुए राज्य के विकास के लिए सार्थक प्रयास किये हैं । विकास और कल्याण के पथ पर सभी क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है । महोदय, यह काम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्रद्धेय नीतीश कुमार जी एवं परम आदरणीय श्रद्धेय श्री सुशील कुमार मोदी जी के कुशल वित्तीय प्रबंधन के रूप में देखा जा सकता है । महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह ज्यादातर कृषि पर ही आश्रित है । भारत के किसान को अगर ऋषि के रूप में देखा जाय तो एक बहुत ही अच्छा संदेश समाज को जायेगा । दुनिया में हम कितना भी नाम कमा लें, दुनिया में चाहे कितना भी संसाधान जुटा लें, लेकिन किसान के खेत से बोया हुआ उपज अगर लोगों तक नहीं पहुँचेगा तो देश की स्थिति क्या हो जाएगी ? हम सोना-चाँदी आदि खा नहीं सकते, लेकिन किसान द्वारा जो उपज हमें प्राप्त होता है, उसका मूल्यांकन हमें निश्चित तौर पर बढ़िया मिलना चाहिए और

यह काम वर्तमान सरकार बखूबी अच्छी तरह से जान रही है । महोदय, आपने 1947 से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय आपने देखा होगा कि जो कृषकों के प्रति, किसानों के प्रति जो अंग्रेजों का रवैया था वो बिलकुल विपरीत था, अंग्रेज कभी भी नहीं चाहे कि जो भारतीय किसान हो, उसका उत्थान हो । उनके उत्थान के पीछे भी बहुत सारा कारण रहा होगा । पिछली सरकार के लंबी लकीर के तहत किसानों को सही रूप से उनके उपज का मूल्यांकन नहीं दिया गया, लेकिन आज बिहार में जो सरकार 15 साल से काम कर रही है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन देखा जा सकता है । बिहार की 89 प्रतिशत आबादी गॉव में निवास करती है और 76 प्रतिशत लोग कृषि के आधाारित किसी भी आजिविका पर निर्भर रहते हैं । आपने देखा है कि 94 हजार स्क्वायर वर्ग कि.मी. हमारे पूरे बिहार की जो जमीनी संरचना है उसी में जल भी है, वन भी है, बसावट भी है और कृषि क्षेत्र की भूमि भी है । इतने कम क्षेत्र में और इतना सुदृढ़ीकरण के साथ इतने अच्छे तरीके से अगर हम खेती के बदौलत समृद्ध कर रहे हैं, यह हमारी एक बड़ी उपलब्धि है । महोदय, राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा 50.84 लाख किसानों को 2670 करोड़ रूपये बैंक खाते में भेजे गये थे । हमारे बड़े भाई साहब सीताराम जी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन देने को क्या है ? देने को तो अभी सामने में जो डाटा आ रहा है उस डाटा के आधार पर मैंने अभी आकर बताया । महोदय, सरकार के द्वारा वर्ष 2019-20 में पायलट परियोजना के रूप में राज्य के सभी जिलों के प्रत्येक प्रखंड में एक ग्राम के सभी फार्म होल्डिंग का मिट्टी नमूना संग्रह कर जॉचोपरान्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जा रहा है । इस योजना के तहत इस वर्ष कुल 82 हजार 852 नमूनों का संग्रहण एवं 52 हजार 947 नमूनों का विश्लेषण तथा कुल 27 हजार 808 मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त ग्राम स्तरीय मिट्टी जॉच प्रयोगशाला परियोजना भी चलायी जा रही है । महोदय, आपने देखा होगा कि जो वर्तमान में कृषि का भूखण्ड है वह बहुत छोटे-छोटे टुकड़े में पूरे बिहार में है । उसके लिए राज्य सरकार पहले 18 जिला में चकबन्दी चलायी थी और बहुत सारे जिले के मौजे जिनकी चकबन्दी पूर्ण कर ली गयी थी वैसे पूर्ण चकबन्दी मौजे को जो चकबन्दी पूरी कर ली गयी है उसमें चक भूधारी को दखल-कब्जा दिलाने का काम सरकार करे, जिसका एक सार्थक परिणाम कृषि के क्षेत्र में निकल सकता है । महोदय, हमारे यहां हमने पशुधन पर भी बात किया, मत्स्य पर भी हमने बात किया और भेड़ बकरियों के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं की । लेकिन हमारे अररिया जिले में फारबिसगंज विधान सभा में पहले एक पशु वधशाला हुआ करता था और अभी 7-8 पशु वधशाला खुला हुआ है और 1200 से 1500 पशुओं

का वहां रोज वध होता है । महोदय, अब आप खुद सोच लें कि एक तरफ हम जल जीवन हरियाली को लेकर जिस अभियान को चला रहे हैं उस अभियान में पशु वधशाला हमारे कलंक के रूप में देखा जा सकता है । हम सरकार से और हम अपने संबंधित मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि उस पशु वधशाला को जितना जल्दी हो उसको बंद किया जाय, चूंकि उस पशु वधशाला में पर्यावरण के खिलाफ 1 हजार से डेढ़ हजार क्वींटल प्रतिदिन ईंधन के रूप में वृक्षों की कटाई हो रही है । जो अनैतिक तरीका से वृक्ष को काटकर के पशु वधशाला में लगाया जाता है ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आपका दो मिनट बचा है ।

श्री विद्या सागर केशरी : मेरे यहां कुछ समस्याएं हैं उन समस्याओं के उपर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ । महोदय, कृषि उत्पादन बाजार समिति के सन्दर्भ में राज्य सरकार ने अपनी योजनाओं के तहत एक अच्छा खासा रकम उपलब्ध कराया है । महोदय, इसमें 124 करोड़ रूपये स्वीकृत भी किये गये हैं, लेकिन हमारे फारबिसगंज विधान सभा में कृषि उत्पादन बाजार समिति के लिए भी जो रूपया उपलब्ध कराया गया है उसका क्रियान्वयन आज तक नहीं हुआ है । हम चाहेंगे कि इसी वित्तीय वर्ष में इस कार्य को अंजाम दे दिया जाय । महोदय, पहले भुसहन धान हुआ करता था और भुसहन धान के साथ में कनकजीर धान हुआ करता था । उसकी खेती बिलकुल नगण्य हो गयी है । जब वह धान हुआ करता था तो धान के खेत में जनग्वारी सांप लोटपोट किया करता था । वह जो धान का फसल था उससे चावल और चूड़ा वगैरह जो आता था वह अब नसीब नहीं होता है । हम चाहेंगे मंत्री महोदय से कि उस तरीके का बीज जहां भी उपलब्ध हो जरूर किसानों तक पहुंचे । इसकी व्यवस्था माननीय मंत्री जी सुनिश्चित करायेंगे । भूमि के विवादों के सन्दर्भ में सरकार गंभीर है- निबंधन शुल्क 50 रू0, स्टाम्प शुल्क 50 रू0 लगाकर चूंकि कृषि क्षेत्र से ही यह मामला जुड़ा हुआ है । ऐसे क्षेत्रों में भी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है । महोदय, सबसिडी किसानों को कम कीमत पर लागत सामग्रियां उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा दी जानेवाली सहायता है । इस क्षेत्र में भी लागत और डीजल सबसिडी किसानों को खेती जारी रखने के लिए काफी प्रेरित कर सकती है । बिहार में शिक्षण सिंचाई प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त टॉपअप सबसिडी दे रही है ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त करें ।

श्री विद्या सागर केशरी : टॉपअप देने के बाद राज्य के किसानों को डीप इरीगेशन पर 90 प्रतिशत और स्पींकलर इरीगेशन पर 75 प्रतिशत सबसिडी मिलती है । महोदय, हम एक चीज और कहना चाहेंगे कि पूरा जो कृषि क्षेत्र है वहां पर जहां-जहां मेड़ है । हम जल

जीवन हरियाली के उपर बहुत सारी बातें करते हैं तो जहां-जहां खेती का मेड़ है वहां पर नीम का पेड़ लगाया जाय ।

क्रमशः

टर्न-15/03.03.2020/ज्योति-पुलकित

क्रमशः

श्री विद्यासागर केशरी : नीम का पेड़ लगाया जाये । नीम के पेड़ लगने से एक तो पर्यावरण की स्थिति अच्छी रहेगी, दूसरी बात है कि कीटाणु खेत में कीट नाशक दवा के रुप में नीम कोटेड खाद का उपयोग करते हैं उस नीम कोटेड खाद की भरपाई उस पेड़ से हो सकती है आपने बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान : आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हूँ । 2020-21 31 अरब 52.81 करोड़ रुपया बजट में लाया गया है जिसमें कि सरकार की भी प्रतिबद्धता दर्शायी गयी है 2395.8 करोड़ रुपया और सरकार जो अभी जैविक मिशन जो चला रही है बिहार में सिर्फ इसमें 12 जिला को ही रखा गया है और यह 12 जिला 19-20, 21-22 तक तीन साल तक लगातार इन 12 जिले को रखा गया है जिसकी कुल राशि 155.88 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूँ कि जैविक जो मिशन है उनको सभी जिला में यानी 38 जिलों में लागू किया जाये, जिससे कि सभी किसानों को इससे फायदा होगा, साथ-साथ जो हमारा इलाका सीमांचल से आता है और प्रत्येक वर्ष 2017, 2018 और 2019 में लगातार बाढ़ से प्रभावित 18 जिला, 19 जिला लगातार प्रभावित प्रत्येक वर्ष रहता है, जिसके कारण वहाँ के किसानों को एक ही फसल पैदा होती है दूसरी फसल जो है बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाती है और बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने के साथ-साथ जो दूसरी परेशानी है जो बालू बहकर पानी के साथ आता है जिसके कारण सही खेती होनी चाहिए वह खेती अनउर्वरक हो जाने के कारण बलुआही मिट्टी हो जाने के कारण वो सही ढंग से खेती नहीं हो पाती है और जो फसल कई हेक्टेयरों में किसानों को जो नुकसान होता है जो मुआवजा राशि जो दो तीन एकड़ में दो हजार, तीन हजार कई किसानों को मिला भी है और कई किसान आज भी वह उस लाभ से वंचित हैं लेकिन जितनी राशि वो किसान लगाते हैं और जो क्षतिग्रस्त होती है सरकार को इस पर जरुर विचार करना चाहिए कि आज जो पूरे देश में जिस तरह से खासकर बिहार और कई ऐसे राज्य में एन.डी.ए. की सरकार और मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे 2007 में जिन्होंने कृषि लोन माफ किया था जिससे कि कई किसानों

को पूरे देश में इससे लाभ मिला और लाभ के साथ-साथ जो आत्महत्या दर है वो घटी, लेकिन बिहार में जो ये सब जिला जो प्रभावित होते लेकिन उनके लिए कोई मापदंड नहीं है, सरकार की तरफ से कि मापदंड यह होनी चाहिए कि जिनकी खेती पूरी की पूरी फसल खत्म हो जाती है तो उनके लिए जो मुआवजा राशि की व्यवस्था या जो सरकार की जैसे बीज की बात, खाद की बात होती है, खाद सब बहुत ज्यादा दर में देखते हैं कि उसकी कालाबाजारी बहुत होती है । कालाबाजारी के साथ-साथ जो हमें बीज हमारे क्षेत्र में फल्का ब्लॉक में मैंने लगातर एक से दो बार और कोढ़ा मेरे ब्लॉक है जिसमें कि पवई, मकदमपुर, घटवारा फलका के धनहा गोविन्दपुर कई ऐसे पंचायतों में मक्के की जो खेती किसान हमारे जो करते थे तो उनकी फसल कभी मक्का नहीं हुआ, कभी बीज लगाने के बाद भी बीज डालने के बाद उनका पौधा नहीं हुआ कई ऐसी परेशानी हुई । उसका कारण एक जो मुझे लगा और कई हमारे पदाधिकारी से भी इसपर बात हुई कि खराब बीज के कारण उनके जो फसल का जो नुकसान हुआ उसका फिर बीज की भरपाई नहीं हो पायी, साथ-साथ जो हमारे इलाके में सबसे ज्यादा केले की खेती जो बड़े पैमाने पर पैदावार होता था आज वो केले की खेती धीरे-धीरे समाप्त हो रही है । मैंने पिछले साल भी यहॉ से कई वैज्ञानिक भी भेजे, सरकार के द्वारा उसकी जॉच की जाय क्योंकि पीलिया एक बीमारी वहॉ पर निकली है उस एरिया में जिसके कारण कि वह गलवा लग करके वह केला गिर जाता है और गिरने के बाद फिर वह दुबारा उस जगह पर उसका पेड़ उत्पन्न नहीं होता और नहीं होने के कारण धीरे धीरे उस एरिया में केले की खेती समाप्त हो गयी साथ साथ अभी तक क्या उपााय होना चाहिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसपर अभी तक सरकार का या सरकार की तरफ से कोई भी कदम जो ठोस कदम होना चाहिए अभी तक नहीं उठा है । साथ साथ अभी दो-चार दिन पहले मैं अपने क्षेत्र में गयी थी कि वहॉ पर एक मेरे डिग्री पंचायत, कोढ़ा के डिग्री पंचायत में वहॉ पर किसानों के द्वारा जब हमने बातचीत किया कि क्या आप लोगों ने फसल लगायी एक नयी बीमारी जो हमारे एरिया कोढ़ा क्षेत्र में है वह है बैगन की खेती, बैगन लगाने से पहले वह सूख जा रही है । वह बैगन की खेती भी अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है, मैं आपकी बत्ती भी देख रही हूै। । दूसरा हमारा क्षेत्र फल्का प्रखंड के मुख्यालय में एक करोड़ से जल मिनार बनाया गया था आज वह जल मिनार वह बंद पड़ा है । उनको चालू करवाया जाये । साथ-साथ जो पशु और मत्स्य में जिस तरह से सबसिडी दिया जाता है शेड्यूल्ड कास्ट को, एस.सी./एस.टी. को उस पैमाने पर जिसतरह से मिलनी चाहिए जो एस. सी./एस.टी. के लिए अधिकृत है । उस तरह से बहुत ज्यादा इसमें हम समझते हैं

कि इसमें भी कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ी धांधली है इसकी जॉच करा के देखी जाय कि किस तरह से उन्हें मतलब दिया जा रहा है और जो सही जो हमारे एस. सी./एस.टी. के लोग हैं जो करना चाहते हैं, पालना चाहते हैं उन्हें नहीं मिल पा रहा है और सिर्फ पैसे लेकर उन्हें गाय या बकरी की उनकी खरीददारी नहीं होती है तो यह भी एक जॉच का विषय है और मूसापुर में हमारे पास जो कैनाल है, उस कैनाल में इस बार इतना पानी आया जिसके कारण कि कई हेक्टेयर में फसल का नुकसान हुआ । जिस रफ्तार से पानी छोड़ देना चाहिए उस रफ्तार से कई हेक्टेयर में फसल बर्बाद होने पर कैनाल को बंद कराना पड़ा जिससे फसल बचा पाये, इसके लिए भी एक स्टाफ जो हर जगह देखते हैं कैनाल पर वह व्यवस्था करनी चाहिए और साथ साथ जो हमारे यहाँ....

सभापति (श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह) : समाप्त कीजिये ।

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान : जी...जी सर, आज एक बहुत बड़ी स्थिति है कि जो नहर है । कई नहर है लेकिन बंद पड़ी है । किसानों को उससे सुविधा जो मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है । साथ साथ जो धान की जो खरीददारी हुई है उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है इसलिए मंत्री जी से मांग करते हैं कि किसानों को पैसा दिलवाने का काम कराया जाय ।

श्रीमती सावित्री देवी : आदरणीय सभापति महोदय जी, जो मुझे बोलने के लिए मौका दिया गया है । महोदय आज मैं कृषि के अनुदान मांग के विरूद्ध लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ी हूँ । महोदय, कृषि एवं पशुपालन एक विशेष प्रकार की अनुभूति है । राज्य हमारा कृषि प्रधान है, जिसे हम लोग हमेशा केवल बोलते है लेकिन बजट के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में हमारे कृषि मंत्री ने जो बजट उपबन्ध किए हैं वह अपने बजट का 3.5 प्रतिशत है ।

क्रमशः

टर्न–16/कृष्ण/03.03.2020

श्रीमती सावित्री देवी (क्रमशः) सभापति महोदय, जबकि अन्य दूसरे राज्यों से तुलना किया जाय तो काफी कम है । इसे कम से कम 7.1 प्रतिशत कुल बजट का होना चाहिए । महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय वित्त मंत्री किसानों, मजदूरों, पशुपालकों के प्रति काफी उदासीन है । यह सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का नारा जरूर देती है लेकिन हकीकत में किसानों की आय आधी कर उसकी कमर तोड़ना चाहती है । महोदय, इस बार खेती में धान की रोपाई ही नहीं हो सकी, यह हमारी जिन्दगी में पहली बार हुआ कि धान की रोपनी ही नहीं हो तो धान पैदावार कहां से होगी ? लेकिन सरकार बांका,

जमुई जिले के सभी प्रखंड, पंचायत को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया, क्यों ? क्योंकि सरकार किसान विरोधी है । महोदय, कृषि में पशुपालन, मत्स्यपालन, बकरी पालन एवं अन्य कृषि आधारित घरेलू उद्योगों में महिलाओं को कोई प्राथमिकता नहीं दी गयी है । क्या सरकार महिला किसानों के लिये इस बजट में कोई प्रावधान किये हैं ? महोदय, सरकार महिलाओं के उत्थान के लिये केवल बात करती है लेकिन बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है । इससे स्पष्ट होता है कि सरकार महिला विरोधी है । महोदय, प्रायः गांवों से पलायन इतनी ज्यादा है कि सभी पुरूष अपने रोजी-रोजगार के लिये बाहर चले गये हैं । गांवों में केवल महिलायें ही हैं । लेकिन उसके लिये कोई सुविधा कृषि पशुपालन के बजट में नहीं दिया गया है । जबकि कृषि पशुपालन में महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा रहता है । लेकिन अनुदान देने के मामले में महिला किसानों एवं महिला पशुपालकों का नाम नहीं देने की भी व्यवस्था है, जो कि बजट में होना चाहिए ।

महोदय, कृषि के क्षेत्र में कोई सकारात्मक विकास नहीं हो रहा है । अनुदान के नाम पर बड़ी-बड़ी कंपनियों को फायदा हो रहा है, न कि किसानों को। उदाहरण के तौर पर एक कुदाल अनुदान के बाद 100/-रूपये में मिलता है जबकि सरकारी दाम 200/-रूपये है । 100/-रूपया अनुदान के रूप में किसानों के नाम पर कंपनियों को दिया जा रहा है ।

महोदय, सबसे मजेदार बात यह है कि बाजार में वही कुदाल 100/-रूपये में ही मिल रहा है । तो यह स्पष्ट है कि अनुदान किसानों के लिये नहीं बल्कि कुदाल बनानेवाली कंपनी के लिये है ।

महोदय, इसी प्रकार कृषि यंत्र पर जितना भी अनुदान दिया जा रहा है, उसका लाभ कंपनी और पूंजीपति ही ले रहे हैं न कि किसान को लाभ मिल रहा है । कृषि विभाग में अनुदान की लूट को बंद किया जाय, इसे सीधे किसानों को दिया जाय ।

महोदय, कृषि उत्पादन की तर्ज पर दुग्ध उत्पादन पर भी सरकार अनुदान की व्यवस्था करे । प्रति किलो दूध के उत्पादन की लागत के अलावा 20 रूपये प्रति किलो अनुदान दिया जाय ।

महोदय, कंफेड के माध्यम से दूध का क्रय किया जाता है लेकिन दाम कम दिया जाता है । इसको बढ़ाया जाय । अनुदान की राशि देने का प्रावधान किया जाय । महोदय, बांका, जमुई तथा गया जिला बकरीपालन हेतु उपयुक्त है । लेकिन बकरी प्रजनन केन्द्र पूर्णियां में खोला गया है जो कि प्राकृतिक कारणों से सफल नहीं हो रहा है । सरकार इस बार बकरीपालन का प्रयास कर रही है । लेकिन डिपथिरिया बीमारी

के कारण सब मर रहे हैं । अतः बकरी प्रजनन केन्द्र पूर्णियां से हटाकर जमुई में खोला जाय ।

महोदय, कृषि विभाग भूमि जल संरक्षण योजना में जमुई जिला में केवल कागज पर पैसा निकाला जा रहा है । कहीं भी धरातल पर तालाब, चेक डैम एवं अन्य योजनायें नहीं दिखाई दे रहा है । इसकी भी जांच करायी जाय । जब कृषि पशुपालन द्वारा गरीब महिला किसानों एव युवाओं को कोई लाभ नहीं दिय जायेगा तो बजट की राशि में 10/–रूपये की कटौती की जाय । जय हिंद ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : माननीय सदस्य श्री ललन पासावान । आपका समय 10 मिनट है ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, कृषि विभाग के अनुदान के पक्ष में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । पहले तो मैं बधाई दे दूं माननीय कृषि मंत्री जी को जो अतिपिछड़ा के नेता, दलितों, शोषितों, गरीबों की आवाज और किसानों के प्रति संवेदना रखनेवाले हमलोगों के बड़े भाई डा0 प्रेम कुमार जी को हम बधाई देना चाहते हैं सदन के माध्यम से कि पहली बार बिहार को गेहूं और मक्का के सवाल पर 2 फरवरी, 2020 को कृषि कर्मण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया । महोदय, 40 साल लगातार कांग्रेस और 15 साल ये लूटे और कभी भारत में बिहार 1 नंबर पर एग्रीकल्चर के सवाल पर नहीं रहा ।

(व्यवधान)

थपड़ी मत पीटिये, जरा अपने को भी देखिये । आपको पुरस्कार मिलता है हत्या, बलात्कार के लिये । इसलिये यह सब मत बोलिये । हमको बोलने दीजिये, डिस्टर्ब मत कीजिये । हम आज भी सच बोलते हैं । छेड़िये नहीं, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं ।

महोदय, बिहार में तो पहले खून की खेती हुआ करती थी । महात्मा बुद्ध के समय दूध की खेती हुआ करती थी । जब ये लोग आये तो खून की खेती होने लगी । आज पहली बार किसानों को नीतीश कुमार जी ने और सुशील कुमार मोदी जी ने और प्रेम कुमार जी ने, कोई ऐसा किसान नहीं रहा, जिसको डीजल अनुदान, किसान सम्मान योजना दर्जनों योजनाओं के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे राशि भेजी जा रही है, जो उसका क्षतिपूर्त्ति होना चाहिए, चाहे वह बाढ़ हो, चाहे वह सुखाड़ से हो, चाहे वह बेमौसम से हो ।

(व्यवधान)

महोदय, बिस्कोमान इनके समय में तो मर गयी थी । बिहार में पहली बार 175 यूरिया खाद का सेंटर बहुत कम दर पर खुले हैं, पहले तो खाद की काला बाजारी हो

रही थी और पूर्णियां और नेपाल के रास्ते सारा खाद बंगलादेश भेज देते थे । अब यह सब बंद हो गया है । माननीय श्री नीतीश कुमार के राज में जो गड़बड़ करता है, वह बचता नहीं है ।

(व्यवधान)

महोदय, एक दो नहीं, जल छाजन हो, पेयजल का मामला हो, कहीं कुछ पदाधिकारी हैं, मेरे यहां भी एक पदाधिकारी हैं, जो गड़बड़ हैं, मैंने कहा कि उसको जल्द हटा दीजिये । माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार हमलोगों के भाई हैं, हमलोगों के अंग है । आपको दरअसल दिक्कत यह है कि पिछड़ा अतिपिछड़ा को देखते हैं तो आपकी छाती में दर्द होने लगता है ।

(व्यवधान)

हम बार-बार पहले भी कह चुके हैं जबतक दलित, अतिपिछड़ा आपलोगों के साथ में नहीं होगा, सब छोड़ कर ईधर आ गये । इसलिए आपलोग ठीक-ठाक रहिये । नहीं तो गड़बड़ा जायेगा ।

महोदय, कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत की सबसिडी, सारे सवालों पर किसानों को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अगुवाई में और उससे बड़ी बात यह कि कदवन जलाशय योजना माननीय मुख्यमंत्री ने अभी 1 तारीख को ऐलान किया, आजादी के 70 वर्षों पर कदवन जलाशय योजना लंबित था, पूरा दक्षिणी बिहार, एक तरफ बाढ़ और एक तरफ सुखाड़ माननीय मुख्यमंत्री ने इशारों इशारों में ही कहा कि अगली बार 2020 में जब हम आयेंगे तो बिहार के हर खेतों को पानी देंगे यानी कदवन जलाशय योजना की हरी झंडी हो जायेगी बिहार में नया इतिहास लिखेगा एन0डी0ए0 की सरकार श्री नीतीश कुमार और श्री सुशील कुमार मोदी की अगुवाई में । क्रमश :

टर्न-17/अंजनी/दि0 03.03.2020

श्री ललन पासवान :(क्रमशः) : हमारे कर्मों का और मनुष्य अपने कर्मों से, अपने चरित्रों से पहचाना जाता है । अवसर सबको मिला है, पता नहीं, आपको अवसर मिला तो आपने उसका उपयोग नहीं किया और जिन्हें अवसर मिला, वे उसका उपयोग कर रहे हैं । तो हम करें या नहीं करें, दबी जुबान से तो आपको कहना ही पड़ता है कि सड़क बन गया, बिजली आ गयी, बिजली खेतों तक चली गयी । 700 मेगावाट से 5500 मेगावाट, 5800 मेगावाट चला गया, यह सब बताने की बात थोड़े ही है, काहे आप ढ़ेला फेंक रहे हैं, आप स्थिर से रहिए । महोदय, 12 जिलों में जैविक खेती, पहले घुर

पर, गोबर पर खेती होती थी और अब जमाना बदल गया है, मोबाईल का जमाना है । आज नीतीश कुमार जी का देन है कि 12 जिलों में जैविक खेती की शुरूआत हुई है, यह प्रेम कुमार जी का देन है कि जैविक खेती से और यही कारण है कि पश्चिमी सभ्यता की आग में जब बिहार जैसे राज्यों में प्रभाव पड़ा तो सब यूरिया और जितना खाद है और उससे जो अनाज पैदा हुआ और जब उसको खाने ल गे तो बिहार में सबसे ज्याद कैंसर का रोग होने लगा । ये लोग जो गाय, बछिया रखने का काम करते थे, दूध वाला काम छोड़कर बन्दूक वाला काम कर रहे हैं । इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि दूध वाला काम शुरू रखिए तो बहुत अच्छा काम होगा और बन्दूक चलाईयेगा तो गाय छूट जायेगी। महोदय, हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं, समय का अभाव है, रोहतास और कैमूर धान का कटोरा है, मंत्री जी आप भी जानते हैं और मेरा पहाड़, बक्सरी, शाहाबाद में धान का कटोरा होता है और नालन्दा के बाद सबसे ज्यादा खेती वहीं होता है । महोदय, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कृषि विश्वविद्यालय पूसा के तर्ज पर, माननीय मंत्री जी जिस तरह से किये हैं और बिहार में धान का कटोरा में नहीं रहे, खाली वहीं रहे, ठीक है कि वहां पर है लेकिन हमलोगों के लिए बड़ा उचित होगा कि जहां एशिया महादेश में सबसे ज्यादा राईस मिलें पायी जाती है, जहां धान उत्पादन में चाहे वह कैमूर का बासमती चावल हो और हमारे पूरे इलाके में सोनाचुर का जो चावल है, वह दुनिया में प्रसिद्ध है, प्रचलित है । इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वहां पर अनुसंधान केन्द्र खोलिए, कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के तर्ज पर शाहाबाद में खुलना चाहिए, कैमूर और रोहतास में, यह हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं । महोदय, यह भी आग्रह करना चाहते हैं कि जलछाजन जो चल रहा है, मेरे यहां भी पहाड़ पर यह काम हो रहा है । जल संचयन योजना आप जो चला रहे हैं, इसमें कुछ पदाधिकारी बेलगाम हो गये हैं, उनपर थोड़ा कार्रवाई कीजिए । कभी-कभी गड़बड़ा रहे हैं तो उनको दंडित कीजिए, कुछ लोगों को सस्पेंड नहीं कीजियेगा तो विकास में रूकावट आ जायेगी क्योंकि मामला गड़बड़ा रहा है । हम सीधे तौर पर कहना चाहते हैं कि पहाड़ पर पशुओं का अम्बार है, न कि सिर्फ ग्वाला रहता है, यादवों की जमात है, वहां पर आदिवासियों की बहुसंख्यक आबादी है । 70 प्रतिशत पहाड़ पर रहनेवाले वहां पर लोग पशु पालते हैं । लाखों नहीं करोड़ों में लोग पशु पालते हैं । 15 जिला के लोग पहाड़ों पर रहता है चारा के अभाव में और पशुपालन मंत्री होंगे तो सुन रहे होंगे तो वहां पर पशुओं के लिए एक अस्पताल खोलिए । पशु मर जाते हैं दवा के अभाव में । पहली बार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी ने अकबरपुर-अधौरा सड़क देने का काम किया, इसलिए वहां पर जब गर्मी के दिन में पहाड़ तपती है तो सारे पशु पानी के

अभाव में नीचे उतरते हैं। आप छिलका बना रहे हैं लेकिन पशु अस्पताल, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस क्षेत्र का हूँ । कैमूर और रोहतास मिलाकर अधौरा और रेहल के बीच में पशुओं का एक बड़ा अस्पताल खुलवाइए और जो पुरानी परम्परा थी, हर पशुपालन अस्पतालों में सांढ़ का, गाय का जो नस्ल है, हमारी जो मिट्टी के नस्ल का जो देहाती गाय है, सबसे बड़ा कैंसर के रोग में, अमेरिका जैसे देशों में 12 लाख, 15 लाख में गाय, बिहार में पटना में देशी गाय का दूध मिल रहा है और वह दूध कैंसर के इलाज में अमृत का काम करता है, लीवर में काम कर रहा है । देशी गायों के प्रजनन का आधार बिहार में बढ़े और देशी गाय ही हमारी माता है और उसका दूध अमृत है और जर्सी गायों से ज्यादा ताकतवर दूध होता है, उसका प्रजनन बढ़ाने का काम सरकार करे और खेत-खलिहानों में व्यवस्था हो

(व्यवधान)

इसलिए हम कहना चाहते हैं कि प्रेम कुमार जी की अगुवाई में एक नहीं दर्जनों सरकार ने योजनाओं को चालू किया है और आज जो सरकार का बजट है, 2000 का बजट और आज के बजट में दस गुणा का अन्तर है । 2000 के पहले और उसके पहले 80 और 85 का बजट, सदानन्द बाबू के समय का बजट और आज के बजट में दस गुणा का अन्तर है तो यही नीतीश कुमार जी की सरकार है और उनके कारण ही आज का बजट 31सौ 52 करोड़ का । उस समय जो जूट मिल थे, चीनी मिल थे, 28 चीनी मिलें, श्रीबाबू का समय था और पूरा-का-पूरा खा गये कांग्रेस के लोग । गया में जूट का कारखाना था और आज जो दो-तीन चीनी मिलें बची हुई हैं, उसको माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने चालू किया ।

श्री सदानंद सिंह : सभापति महोदय, इन्होंने एक शब्द का व्यवहार किया है कांग्रेस के लोग खा गये, यह आपत्तिजनक है, इसको प्रोसीडींग्स से हटा दिया जाय । आप बोलिए तो ठीक से बोलिए ।

श्री ललन पासवान : कांग्रेस की सरकार खा गयी....

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सदस्य तो उत्तर नहीं दे रहे हैं कि माननीय सदस्य चिंतित हैं। सदानंद बाबू, सरकार का तो उत्तर नहीं हो रहा है, जिसके लिए आप चिंता में हैं ।

श्री ललन पासवान : जो बचा-खुचा था उसको राजद के लोग खा गये । एक-दो गो नहीं खाये, पूरा जूट मिल खा गये, चीनी मिल खा गये, जूट का कारखाना खा गये, एक-दो गो नहीं खाये, पूरा खा गये । 28 चीनी मिलें थी....

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री ललन पासवान : इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, राजेश बाबू बैठ जाइए । दिलकेश्वर बाबू वाला कांग्रेस नहीं है, आप बैठिए । महोदय, नीतीश कुमार जी के राज में बहुत

विकास हुआ है । मैंने कहा कि जो दूध की खेती होती थी, बीच में बन्दूकों की खेती शुरू हो गयी थी और जिस समय जूट की खेती होती थी तो उस समय दुग्ध की खेती होती तब काहे यह सब बात होता । सब तो लूटा गया, बिहार में कुछ बचा ही नहीं । पुल निर्माण निगम कहां चला गया था, जीरो माइनस पर था । अलकतरा पी गये, क्या-क्या खा गये यह बताइए मत । इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के अगुवाई में, माननीय मंत्री प्रेम कुमार जी की अगुवाई में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं । इन लोगों को पिछड़ा और दलित बर्दाश्त होता नहीं है । चाहते हैं कि अकेले सब माल मार लेना और अकेले ये लोग बच भी गये हैं और बाकी एक सेकुलरिज्म की बात कहकर एक आदमी को और बचाया अकलियत के लोगों को । इसलिए बाकी सब लोग भागकर चला आया। अभी भी आप अपना आचरण बदलिए, व्यवहार बदलिए, नहीं तो जो कुछ भी बचा हुआ है.....

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त करिए, माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका ।

श्री ललन पासवान : वह भी समाप्त हो जायेगा । महोदय, आपने मुझे जो बोलने के लिए अवसर दिया है, उसे लिए धन्यवाद देता हूँ ।

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, कृषि विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने लिए जो आपने अवसर दिया, इसका आभार प्रकट करता हूँ । साथ-ही, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी और पूर्णियां की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ । महोदय, अभी सीताराम बाबू जो वरीय सदस्य हैं, मैं उनकी बातों को सुन रहा था और किसान भाईयों के सम्मान में दो पंक्ति के साथ अपनी बातों को सदन में रखता हूँ -

हो विष्णु तुम धरा के हल सुदर्शन धाारक तुम
बिना शेष शय्या के होता दर्शन नित्य तुम्हारा ।

सभापति महोदय, विष्णु पालक है और किसान भाई भी अन्नदाता पूरे देश के, बिहार के हम सबों के पालक हैं।

...क्रमशः.....

टर्न-18/राजेश-राहुल/3.3.20

श्री विजय कुमार खेमका, क्रमशः धरती माता कहती है किसान को,अपने पुत्र को, कि हल से धरती का सीना चीरो और जो अन्न निकलेगा, उससे देश की जनता की सेवा करो, सभापति महोदय, हम उसका नित्य दर्शन करते हैं और तब बिहार के खेतों से आवाज आती है, खेत-खलिहानों से आती आवाज कृषि समर्पित है, ये एन0डी0ए0 की सरकार

। सभापति महोदय लेकिन हमारे प्रतिपक्ष में जो लोग बैठे हैं इनको खेतों में जो हरियाली है और किसानों के चेहरे पर जो लाली है, वह इनको नजर नहीं आती है, और सभापति महोदय इसीलिए खेत के मेड़ से एक किसान ने कहा कि ये क्या समझेंगे, चारा भी खा जाने वाले क्या समझेंगे मन तुम्हारा ? सभापति महोदय, 15 साल बनाम 15 साल कैसा शासन था सभापति महोदय, अभी सीताराम बाबू कह रहे थे कि किसानों की बड़ी दूर्दशा है और खेतों में उपज नहीं है । सभापति महोदय, यहीं बिहार है और इसी बिहार का चावल जो सीताराम बाबू बोल रहे थे, सिर्फ राम की बात मत कीजिए, अयोध्या में राम का जो मन्दिर है, उसमें भी इसी बिहार के चावल का भोग लगता है, ये है हमारा बिहार सभापति महोदय । सभापति महोदय, इनको नजर नहीं आता है कि हमारे यहां इस बार जो हमारे मंत्री है प्रेम बाबू, अति पिछड़ा से हैं, अभी बोल रहे थे सीताराम बाबू कि अति पिछड़ा और मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, सदन में केन्द्र में जब वंशवाद परिवारवाद की सरकार थी और 15 साल बिहार में भी जिनकी सरकार थी, उसमें अति पिछड़ा का क्या हाल हुआ और ये तो एन0डी0ए0 की सरकार है, जिसमें अति पिछड़ा पुरस्कृत है और उच्च पद पर बैठे हुए हैं बिहार का कल्याण करने के लिए । सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस बार का जो बजट है इसमें 3152.81 करोड़ का बजट का प्रावधान है और हमारे प्रतिपक्ष के भाई कह रहे थे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से बिहार के किसानों को सम्मानित किए जाने का काम भी एन0डी0ए0 की सरकार ने किया है और इसमें 50.84 लाख किसानों को 2670 करोड़ रूपया सीधे डी0बी0टी0 के माध्यम से खाते में देने का काम इस सरकार ने किया है । सभापति महोदय, अगर किसान खुशहाल नहीं होता और खेतों से हरियाली देखने को नहीं आती, तो हमारे बिहार को हमारे यहां कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, सभापति महोदय ग्लोबल एग्रीकलचर लीडरशिप अवार्ड फॉर बेस्ट परफोरमेंश एण्ड एनिमल हस्बेंडरी सेन्टर का भी पुरस्कार मिला है, एक नहीं बेस्ट स्टेट मीट फेडरेशन अवार्ड भी मिला, अभी दूध की बात कर रहे थे और ये अवार्ड जो है इसी एन0डी0ए0 की सरकार में मिला है, बी0एम0एल0 मंजूल अवार्ड भी बिहार को मिला, बेस्ट पोलट्री अवार्ड भी बिहार को ही मिला है । सभापति महोदय, जैविक खेती पर भी सरकार का ध्यान है और तीन साल में 155.88 करोड़ कुल खर्च होगा, ये भी इस बजट में प्रावधान किया गया है । सभापति महोदय, सिर्फ व्यक्ति का ही स्वास्थ्य नहीं बल्कि बिहार भी कैसे स्वस्थ निरोग रहे, इसके लिए हमारे खेत का भी सॉयल टेस्ट करके सरकार उसके प्रति भी गंभीर है सभापति महोदय और हमारे विपक्ष को हम आंकड़ा देना चाहते हैं कि सीताराम जी केवल चुनावी भाषण देकर चले गए, वे नहीं बोल पाए थे लेकिन उन्हें बताना चाहिए था कि सरकार में कृषि मंत्री ने, एन0डी0ए0

की सरकार ने किसानों के लिए क्या-क्या किया है ? सुदामा जी सुनिएगा और यहां 106 कृषि यंत्र बैंक की भी स्थापना की गई है और आज किसानों को अनुदानित दर पर यंत्र दिए जा रहे हैं सभापति महोदय और तो और छोड़िये हमारी सरकार अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत का अनुदान दे रही हैं । सभापति महोदय, हम अभी कह रहे थे, हमारी इस चर्चा में कह रहे थे कि हमारे पूर्णिया की ही बात करें सभापति महोदय तो कृषि कार्य में 38000 महिलाएं आगे बढ़ करके आई हैं और 200 पशुपालक के रूप में हमारे यहां महिलाएं आगे बढ़ी हैं । चाहे पशुपालन का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, मुर्गीपालन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बिहार बढ़ा है और बिहार का किसान भी बढ़ा है । सब्जी के क्षेत्र में हमारे यहां पूर्णिया भी सब्जी का क्षेत्र है वह प्रमंडल में पूर्वोत्तर उत्तर बिहार में सब्जी सबसे ज्यादा होती है और उसके लिए 25000 रूपए का अनुदान देने की व्यवस्था इस सरकार ने की है । सभापति महोदय, हमारे यहां सब्जी का क्षेत्र होने के नाते मैं कृषि मंत्री जी को एक सूझाव देना चाहूंगा और मैं देख रहा हूं कि कृषि विभाग के जो हमारे सचिव हैं और वे हमारे यहां डी0एम0 भी रहे हैं श्री श्रवण जी, कृषि विभाग की योजना को गांवों तक ले जाने का काम करते है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं और मैं आग्रह करना चाहूंगा कृषि मंत्री जी को कि पूर्णिया में जो हमारे रानीपत्रा विधान सभा का क्षेत्र है और सब्जी के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है वहां पर एक कोल्ड स्टोरेज बनना चाहिए और वहीं पर नहीं अनेक जगहों पर उसकी आवश्यकता है और आधुनिक सब्जी मन्डी का निर्माण भी वहां पर होना चाहिए और कृषि उत्पादन बाजार समिति पहले के समय में जो विघटित हो गई थी, हमारे पूर्णिया में भी बिहार की सबसे बड़ी कृषि मन्डी पटना के बाद है लेकिन उसका जीर्णोद्धार इंतजार कर रहा है इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा तथा मैं जानता हूं कि आपने 15 करोड़ रूपया उसमें देने का काम किया है लेकिन फिर भी उसका निर्माण नहीं हो रहा है इसलिए उसका तुरन्त निर्माण हो ताकि किसानों को उसका सीधा लाभ मिल सके.....

(व्यवधान)

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री विजय कुमार खेमका: महोदय अभी 1 मिनट का समय है, अभी तो हरा बत्ती भी नहीं जला है । सभापति महोदय, घर-घर बिजली हमारी सरकार पहुंचा रही है और खेतों तक भी बिजली एन0डी0ए0 की सरकार पहुंचाने का काम कर रही है । सभापति महोदय, पूर्णिया कोशी दरभंगा प्रमंडल में मछली की बड़े पैमाने पर खेती होती है लेकिन बाढ़ के समय मे, सूखे के समय में, जो किसान की मछली और मखाना बह जाता है, तो कोई भी क्षति का मुआवजा नहीं मिलता है इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम

से यह आग्रह करना चाहूंगा कि उसे भी बीमा योजना से जोड़ करके क्षतिपूर्ति का मुआवजा उसको दिया जाए और सर्पदंश में हमारे किसान, हमारे मजदूर भाइयों की सर्पदंश में मृत्यु होती है, उसे भी आपदा में जोड़ने की जरूरत है । सभापति महोदय, जो हमारे कृषि सलाहकार हैं, जो हमारे एक पूर्व के वक्ता ने भी कहा कि उनकी बड़ा उपयोगिता है और कृषि सलाहकार अनेक तरह के काम कृषि के बाद भी सरकार की अनेक योजनाओं को कृषकों तक पहूंचाने का काम करते हैं, उन्हें संविदाकर्मी के रूप में लेने का काम सरकार को करना चाहिए.....

(व्यवधान)

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): अब आपका समय समाप्त हुआ । माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह ।

टर्न-19/सत्येन्द्र-मुकुल/ 03-03-2020

श्री मनोहर प्रसाद सिंह: महोदय, हम सबों को मालूम है कि यह कृषि प्रधान देश है और बिहार में 86 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं और यहां की जो भौगोलिक संरचना है उसमें यहां का भौगोलिक क्षेत्र लगभग 9.06 लाख हेक्टेयर है और कृषि योग्य जो है वह 79.46 लाख हेक्टेयर है लेकिन सिर्फ 56.03 लाख हेक्टेयर पर खेती होती है। महोदय, चूंकि समय बहुत कम है। अभी हम लोग सुन रहे थे ललन बाबू बोल रहे थे कि हमारे यहां सबों को खाद दिया जा रहा है और खाद पर्याप्त मात्रा में सबों को मुहैया कराया जा रहा है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यूरिया की जो स्थिति है पिछले साल में, रबी की फसल में जो खाद की उपलब्धता उसका सिर्फ एक जिक्र कर देना चाहता हूं कि आवश्यकता थी 7.5 लाख टन की लेकिन आपूर्ति की गई 6. 28 लाख टन लेकिन बिक्री हुई 4.92 लाख टन तो सबको खाद कहां से मिल गई समझ में नहीं आता है। महोदय, कहा गया कि यहां किसानों को बहुत अनुदान दिया गया है और मैं किसानों के अनुदान के बारे में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कृषि इनपुट अनुदान के मामले में 23 लाख 52 हजार 5 सौ 77 आवेदन प्राप्त हुये उसमें जो कृषि सम्यक थे उन्होंने जांच सिर्फ किया 44 हजार 244 आवेदन पत्र का और बचा 23 हजार 330 आवेदन पत्र अभी भी लंबित है तो अनुदान कहां से मिल गया इसलिए अनुदान भी नहीं मिल पाया लोगों को। महोदय, कृषि की अगर उत्पादकता बढ़ानी है और जो सरकार का लक्ष्य है कि उसकी आमदनी दोगुनी करनी है तो उसकी आमदनी को दोगुनी करने के लिए कुछ मूलभूत संरचनाओं में सुधार करने की जरूरत पड़ेगी और जो सब्सिडी दी जाती है, उस सब्सिडी से वर्ष 2008 में एक शोध हुआ था। उस शोध में सैनगेन फैनअशोक गुलहाटी और सुखदेव थौराट नपे यह

शोध निकाला की जो कृषि सामग्री दी जाने वाली सब्सिडी है इससे गरीबी दूर नहीं हो सकती बल्कि कृषि विकास को गति देने की दिशा में कोई विशेष लाभ नहीं होता है इसलिए कृषि शोध, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा पर होने वाले निवेश के बाद ही उसमें सुधार हो सकता है। महोदय, कृषि के संबंध में अभी हमारे यहां बिहार के परिवारों में 48 प्रतिशत से ऊपर लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। पहली जुलाई, 2015 से 30 जून, 2016 के दौरान प्रदेश में 37 प्रतिशत किसानों ने नये कर्ज लिये हैं। महोदय, अगर इसी तरह से कर्ज में डूबते रहें तो लोगों को कठिनाई होगी और मैं समझता हूं कि जितने लोग लड़ाई में नहीं मरे हैं उससे ज्यादा किसान आत्महत्या कर के मरे हैं इसलिए उस पर विचार करना चाहिए और जो बैंक से कर्जा दिया जाता है, उस बैंक के कर्ज को सहूलियत से दिया जाये ताकि किसान अपनी आमदनी बढ़ा सके, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह):श्री सुदामा प्रसाद। आपका समय है 2 मिनट।

श्री सुदामा प्रसाद: सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। महोदय, इस कृषि बजट की जो दिशा है वह उल्टी है और किसान विरोधी है इसीलिए हम कटौती प्रस्ताव के समर्थन में हैं। किसान कौन है महोदय, किसान वह है जो खेत से अनाज पैदा करता है, चाहे उसकी अपनी खेत हो या बटाई पर ली गयी हो, ये किसान वही है और बिहार में घाटे की खेती का भार बटाईदार किसानों के कंधे पर है । यह बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भूमि सुधार आयोग गठित किया था उस आयोग की सिफारिश है कि बिहार में 77 प्रतिशत खेती बटाई पर होती है जो आज बढ़कर के 80 प्रतिशत हो गयी है और घाटे की खेती का भार उठाने वाले इन बटाईदार किसानों को खेती में उत्साहित करने के लिए इनका रजिस्ट्रेशन किया जाय, इनको पहचान पत्र दिया जाय। महोदय, यह भूमि सुधार आयोग ने कहा था लेकिन आयोग की सिफारिश को ठंढे बस्ते में डाल दिया गया, आज उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती और यहां 3,152 करोड़ 81 लाख का बजट दे दिया गया। महोदय, इस बजट में बटाईदार किसानों का हिस्सा हुआ 2,522 करोड़ 24 लाख 80 हजार रूपये। मंत्री जी अभी हैं माननीय मंत्री जी हमें ये बतायें कि बटाईदार किसान को कितना पैसा देते हैं महोदय, उनको डीजल का सब्सिडी नहीं मिलता, उनको फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिलता, उनका धान गेहूं सरकारी रेट पर नहीं बेचा जाता, हर जगह उनसे खेती करने का प्रमाण मांगा जाता है कि जाकर के आप अपनी जमीन के मालिक से लिखवा कर लाइये, कौन जमीन का मालिक देगा लिखकर। अगर आपको बिहार में खेती को जिंदा रखना है, अगर आपको खेती को आगे बढ़ाना है तो बटाईदार किसानों को आपको पहचान पत्र देना ही होगा नहीं तो खेती ही भरभरा कर भस्म हो

जायेगी। महोदय, आज कृषि लागत मंहगी हो रही है लेकिन फसलों का दाम जो है ज्यों का त्यों है । माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम डेढ़ गुणा समर्थन मूल्य देंगे अगर केन्द्र में सरकार बनेगी इस साल, राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण आयोग की रिपोर्ट है कि 1 क्विंटल धान पैदा करने में किसानों को 2,430 रूपया खर्च होता है और समर्थन मूल्य कितना दिया आपने 1,815 रूपया और वह भी 1,815 रूपया में किसान का धान नहीं लिया गया, बेमौसम की बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है, किसानों का धान दस सौ रूपया, ग्यारह सौ रूपया में बिका है महोदय और अब बिहार सरकार का 30 लाख मे0 टन धान खरीदने का लक्ष्य है लेकिन बिचौलिया द्वारा 1 हजार रू0, 11 सौ रू0 में किसानों से धान खरीदा गया है, आज वह कागज जुटाते फिर रहा है भूधारी लोगों से कि कार्ड दीजिये आपको प्रत्येक क्विंटल पर सौ रू0 देंगे, ये स्थिति है और कृषि विकास की डींग हांकी जा रही है तो महोदय हमारे कृषि मंत्री जी कृषि कर्मण पुरस्कार लेकर आये हैं लेकिन जो लोग खट कर के अपना अनाज पैदा कर रहे हैं, मकई की खेती में 17-18 में दर्जनों बटाईदार किसानों ने, मकई पैदा करने वाले किसानों ने आत्महत्या किया इसलिए कि बालियों में दाना आया ही नहीं, मकई में दर्जन भर किसानों ने मंत्री जी बतलायें कौन का तो कम्पनी का बीज उनलोगों ने खेत में इस्तेमाल किया था, क्या सरकार ने उस कम्पनी को ब्लैकलिस्टेड किया, ब्लैकलिस्टेड किया कितनी कम्पनियों को....

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)माननीय सदस्य श्री रवींद्र सिंह जी।

श्री रवींद्र सिंह: सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जो बातें रखी गयी हैं बजट में उस पर चर्चा बहुत काफी हो रही है और होगी आगे भी और माननीय मंत्री भी इसका जवाब देंगे लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि कृषि जमीन से जुड़ा हुआ चीज, भूमि से जुड़ा हुआ चीज है अगर भूमि का ही सही वितरण नहीं हुआ है तो किसानों को क्या लाभ मिलेगा, किसको किसान कहा जायेगा। महोदय, अभी एक साथी बोल रहे थे बटाईदारी के बारे में लेकिन गरीब किसान, मजदूर किसान और मध्यम किसान, धनी किसान और जमींदार भी हैं, यहां हम चाहते हैं कुछ खाका जो रखा गया है सुशासन और न्याय की सरकार, सबका साथ सब का विश्वास, सब का विकास उसका नमूना जो हमारे पास आंकड़े हैं मैं बतला देना चाहूंगा, किसका कितना जमीन पर कब्जा है, किसकी संख्या कितनी है क्या रखा गया है। देश में ब्राहम्णों की संख्या 1.1 है और जमीन का मालिक है 5.4 (क्रमश:)

टर्न-20/मधुप-हेमंत/03.03.2020

..क्रमश:..

श्री रवीन्द्र सिंह : क्षत्रिय की संख्या है 4.7 और जमीन का मालिक है 75.1, वैश्य की संख्या है 5.4 और जमीन का मालिक है 9.2, यह तीनों मिलाकर जमीन के मालिक कितने हो गए - 89.7 । अब सोच लीजिये कि व्यवसाय पर इनका कितना कब्जा है, ब्राह्मण का व्यवसाय पर कब्जा है 12.4, क्षत्रिय का कब्जा 21.2 और वैश्य का है 63.2 । मिलाकर हो गया 96.8, व्यवसाय के मालिक यही हो गये । फिर आइये नौकरी में, तो 61.0 ब्राह्मण हैं नौकरी में.... (व्यवधान) कृषि पर ही है । हड़बड़ा क्यों रहे हैं ? क्षत्रिय की संख्या है 4.7 लेकिन नौकरी में है 11.3, वैश्य की संख्या है 5.4 और नौकरी पर कब्जा है 13.4 । मिलाकर हो गया 86.3 और सवर्ण जाति का 10 प्रतिशत आरक्षण ले लिया तो 10 प्रतिशत और हो गया, तो 96.3, नौकरी, व्यवसाय और जमीन के मालिक मुट्ठी भर लोग हो गये । बाकी किनके जिम्मे दिये ?

बजट में जो आई है बात, अनुदान देंगे । किसको अनुदान दीजियेगा ? (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूं । शिक्षा में 77.4 हैं, राजनीति में 62.4 और संख्या है कुल मिलाकर 13.2 । अब इस तरह का सुशासन और न्याय रहेगा, इसको कुशासन और अन्याय कहना गुनाह होगा ! कैसे होगा ? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आप इस तरह से विकास करा देंगे ? जब जमीन का ही वितरण अन्यायपूर्ण है तो कैसे होगा ? आपने क्रांति किस-किस चीज की कर दी ? आपने बहुत चीजें की हैं । आपने पीली क्रांति की, आपने नीली क्रांति की, भूरी क्रांति की, स्वर्ण फाइबर क्रांति की, गोल्डेन क्रांति की, लाल क्रांति की, चॉदी फाइबर की, श्वेत क्रांति की, इन्द्रधनुषी क्रांति की । इससे किसको लाभ होगा ? जो भी बजट में आया है, वह किसको मिलेगा ? सभापति महोदय, एक बात जान लीजिये, अगर इस तरह की व्यवस्था को न्याय कहेंगे तो अन्याय किसको कहेंगे ? हमने तो देखा इसमें, बजट के किताब में लिखा हुआ था कि सिद्धांतों के बिना राजनीति, परिश्रम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा, यह महात्मा गॉधी जी ने कहा था, तो इसपर तो लिख देना चाहिए था । बजट तो तैयार किये हैं वित्त मंत्री । नाथूराम गोडसे के बिना भाजपा, होना चाहिए था, वह भी लिख देना चाहिए था । उनकी हत्या हुई, उनकी बातों को रखा गया है तो हत्यारे का नाम भी रखना चाहिए था । मेरे कहने का मकसद है कि अगर यही आपका सामाजिक न्याय है और मैं समझता हूँ, हम भी पहाड़ पर रहे हैं, नीचे भी रहे हैं, संघर्ष हमलोगों ने भी किया है, माननीय सदस्य ललन जी अपनी बात रख रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह किसके पक्ष में है और मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जितना अनुदान मिलेगा, किनको मिलेगा कितना परसेंट ? जब सब पर इन्हीं लोगों का कब्जा है, तो बचा क्या ? यही

कारण है कि इधर लोग न ताके और सत्ता तथा प्रशासन पर हमारा कब्जा कायम रहे और ये लोग केवल गुलामी करते रहें । इसलिये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यह बजट 16 आना 10 रू0 काटने का मैं क्या कहूं, जो भी पैसा गया है, इस बजट में आना चाहिए कि कितना पैसा पास हुआ, कितना इसमें खर्च हुआ, बचा तो क्यों बच गया, उसका दोषी कौन है और नीचे गया तो जमीन पर गया कि नहीं, बीच में कौन लूट लिया, उसके खिलाफ भी बजट में बात आनी चाहिये । लेकिन यह बात नहीं आती है । बात आती है क्या, हमलोग ईमानदारी से माननीय सदस्यगण, हम तो बहुत दिन से सुन रहे थे, हम बोलते नहीं थे डरे कि मामला गड़बड़ा जायेगा, अगर यही धर्म है, यही न्याय है, यही सुशासन है तो हम तो पूछना चाहेंगे कि अन्याय किसको कहेंगे ? कुशासन किसको कहेंगे ? अगर यही विषमता मूलक बँटवारा रहेगा तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसी को कहा जायेगा?

महोदय, बार-बार बोला जाता है कि जेल में चले गये । माननीय सदस्य तमाम लोग मौजूद हैं, वही जेल जाने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाने वाले भी हैं और आज मुख्यमंत्री बनाया हुआ मिल गया तो आप बोलते हैं कि जेल में हैं । जरा सोच लीजिये कलेजे पर हाथ रखकर कि अगर वे नहीं बनाये रहते तो बी0जे0पी0 वाले माननीय सदस्य क्या चाहते, मंत्री बनते वे आज ? वे भले पलट गये लेकिन मेरा साफ शब्दों में यह कहना है कि अगर इसी तरह से आपकी राजनीति चलेगी इस देश में, तो 72 वर्ष नहीं, हमने सुना था कि प्रजा द्वारा प्रजा के लिए प्रजा की सरकार, अब तो यह कहना होगा कि प्रजा द्वारा प्रजा को लूटने के लिए प्रजा की सरकार आपने बना दी । परिभाषा ही आपने बदल दी । लोकतंत्र का यही तकाजा रहेगा ? यही तकाजा है लोकतंत्र का ? यही लोकतंत्र के हमलोग रक्षक हैं ? हमलोग चाहते हैं कि किसी की आलोचना करने से पहले अपने गिरेबाँ में झांकें कि हम कहाँ के शिकारी हैं ।

आदरणीय नेता जी को आपलोग बोला करते हैं, आज जीवित हैं, जिन लोगों की उधर पूछ हो रही है, उनके खिलाफ ही पूछ हो रही है, अगर वे नहीं रहते तो उधर उनको सीट भी नहीं मिलती । माने तोड़ने का काम करते हैं । नेता हमको कैसा चाहिए, गुलामी वाला चाहिए, हुंकारी भरने वाला चाहिए ! माननीय सभापति महोदय, हमको लगता था बोलने में, हम तो हिचकते थे कि बोलने में किसी को, यह चीज आई बात, हम और बात रखना चाहते हैं, आपने कहा, कृषि मनुष्य का सबसे स्वास्थ्यप्रद, सबसे उपयोगी और सबसे नेक रोजगार है, यह जॉर्ज वाशिंगटन लिखे हैं । आपका सर्वे किताब में लिखा हुआ है, कृषि बिहार जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुख्य सहारा है जो उनकी खाद्य सुरक्षा, रोजगार और ग्रामीण विकास को सहारा देती है, यह तीन-चौथाई से भी अधिक आबादी को सहारा देती है, रोजगार पैदा कराने के

अलावा यह उद्योगों के लिए कच्चा-माल उपलब्ध कराती है, खाद्य आपूर्त्ति में वृद्धि करती है और गरीबी निवारण में सहायता करती है । क्या इसी विषमता मूलक बँटवारा जमीन का और आप कृषि का रोड मैप बना रहे हैं ? आप बनाइये जमीन के वितरण का रोड मैप, तब आपको पता चलेगा कि हम कहाँ रहेंगे और आप कहाँ रहेंगे । रोड मैप बनाइये, जमीन के वितरण का पहले बनाइये । खेती करना जानते नहीं हैं, कोई खानदान उनका खेती नहीं किया है लेकिन सबसे ज्यादा खेत के मालिक हैं । हम समूचे पूर्वज से लेकर आज तक खेती कर रहे हैं, हम तो एकदम मालिक नहीं हैं । मेरे कहने का मतलब है कि अगर इसी तरह से विषमता मूलक जमीन का बँटवारा, नौकरी का बँटवारा, शिक्षा का बँटवारा, आपने क्या नहीं किया, निजीकरण कर दिया, आरक्षण खत्म कर दिया बिना संशोधन के, निजीकरण कर दिया, आपने आरक्षण खत्म कर दिया । जब मंडल आयोग को लागू करना था तो 40 वर्ष लगा और वह भी आधा-अधूरा मिला और जब 10 परसेंट का हुआ तो 10 मिनट में हो गया और लागू भी हो गया । मेरे कहने का मकसद है कि आपका यह भंडाफोड़ है, अगर इसको चुनौती देनी है तो हम तैयार हैं । आर0एस0एस0 का एजेंडा कुछ और है, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का एजेंडा और है, बी0जे0पी0 का एजेंडा और है । कुल मिलाकर यही है कि मुट्ठीभर लोगों के पीढ़ी दर पीढ़ी जो राज करते आये हैं, शासन और प्रशासन और सत्ता पर कब्जा, उत्पादन के साधन पर कब्जा रहे और तमाम लोगों में फूट डालकर आप राज करना चाहते हैं । अगर जिस दिन पर्दा खुल गया, खुलने वाला ही है । इसलिए सही और गलत की कसौटी व्यवहार होता है, अपनी पहचान और इतिहास को हमने मिटाया । आपने नाम कब नहीं बदला, द्रविड़ से कह दिया दास, दास से कह दिया अनार, अनार से कह दिया दानव, दानव से कह दिया असुर, असुर से कह दिया अवर्ण । कितने नाम बदले हैं । आप बदलिये, नाम बदलना ही चाहते हैं तो बदलिये, हिन्दू शब्द नहीं था, किसी किताब में आपने नहीं लिखा है, अगर लिखा है तो फारसी शब्द में है, आपकी धार्मिक किताब में नहीं है । वह भी नाम बदल दीजिये कि हम हिन्दी, संस्कृत में क्या कहेंगे । अपना नाम बदला, फिर देव, फिर सुर, फिर सवर्ण, सवर्ण में तीन पार्ट कर दिये - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और तीनों शक्ति ले लिये । ब्राह्मण को दे दी मठ की गद्दी, बौद्धिक शक्ति ले ली, राजगद्दी क्षत्रिय को दे दी, राजनीतिक शक्ति ले ली और वैश्य को दे दी सेठ की गद्दी, धन की शक्ति ले ली, दौलत की ले ली । हमलोगों के लिए क्या बचा ? हमको शुद्र के रूप में बाँटा तो सेवा की गद्दी दी कि हमारी सेवा करके जीवित रहो और इसी की बात कहते हैं । मनु-स्मृति में आपने लिख दिया कि सारा संसार देवता के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसी धरती पर सर्वश्रेष्ठ

ब्राह्मण देवता हुआ । आपने लिख दिया कि वह कोई पाप का काम करे, कोई गलत काम करे, अन्याय करे, उसको सजा नहीं होगी । यही मनु-स्मृति आप लाना चाहते हैं । जहॉ संविधान में.... (व्यवधान) रूकिये न ! मैं कहना चाह रहा हूँ, सभापति महोदय, अगर इस तरह से सबका कब्जा आप ले लेंगे तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि यह बजट जो आया है, सिर्फ मुट्ठीभर लोगों के फायदे के लिए आया है, बाकी लोगों के नुकसान के लिए आया है ।

...क्रमशः...

टर्न-21/आजाद:अंजली/03.03.2020

..... क्रमशः .....

श्री रवीन्द्र सिंह : और मैं समझता हूँ कि 10 रू0 इसको काटकर के प्रस्ताव को पास किया जाय और नहीं तो जो फिर अन्याय हुआ है, अभी तक जारी रहेगा और इसको बदला जाय । अब राजनीति बदलने वाली है तो करवट लेने वाली भी है । मेरा कहना है कि हम एक चीज और कह देना चाहते हैं, हम बड़ी गौर से पढ़ रहे थे और सुन भी रहे थे, जन गण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता, इस राष्ट्रीय ज्ञान को हमने सुना है । मैं पूछना चाहता हूँ कि पंचम के स्वागत में क्यों रखा गया राष्ट्रीय गान को तो मैं कहता हूँ कि अगर यहां पर प्रथम गवर्नर भी बने थे लाड्र्स माऊन्ट बेटेन बने आजाद भारत का, वे चले गये, हम और आप आज तक गुलाम रह गये और यही चाहते हैं आप कि लोकतंत्र में हमारा वोट कम है, कैसे वोट मेरे पास आओ, आपस में लड़ा दो और हम ले लें । आपने हमारे साथ क्या किया है, हमारे पूर्वजों को पैर में झाड़ू बांधने का काम किया, गले में टहरी बांधने का काम किया और 7 हजार लोगों को कत्ले आम किया, जो सत्य हिंसा पर चलने वाले थे, जब महात्मा गॉधी ने सत्य हिंसा के नाम पर आजादी लेने का काम किया और आपने उनका हत्या कर दिया । कैसी बात है और आज आप लिखते हैं कि इसके बिना यह नहीं, आपका सिद्धांत यही है, अगर यह सिद्धांत है तो हम आपलोगों से कहना चाहेंगे सभापति महोदय आपके माध्यम से कि लोकतंत्र में जब हम सब भ्रष्ट हो जायेंगे तो बचेगा कौन ? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायापालिका और मीडिया भी तो क्या होगा ? आज देख रहे हैं भारत में क्या हो रहा है, क्या चाहते हैं कि भारत में जनता लड़ती रहे, एक भी लड़ाई में आप कहीं शामिल नहीं होते हैं । हम महसूस करते हैं इस बात को कि लड़ जाता है वह व्यक्ति, जो बेचारा हमारा पूर्वज बना मुसलमान, जो बना बौद्ध, सिख, इसाई, कैसे बना वह आपके अमानवीय व्यवहार के कारण बना, बौद्ध बना तो आपके अमानवीय व्यवहार के कारण , सिख बना तो आपके अमानवीय व्यवहार के कारण और

मुसलमान भी बना हमारा पूर्वज तो आपके अन्याय के कारण, जिस बात को कहते हैं अन्याय । 131 एम0पी0 हैं हमारे दलित और आदिवासी से रिजर्व सीट से जीतकर गये हैं, एक आवाज नहीं निकालते हैं । कोई मुख्यमंत्री चले जाते हैं मंदिर तो आप मंदिर को धोना शुरू कर देते हैं । यह तो अजीब बात है और आप पद देना चाहते हैं लेकिन आप प्रतिष्ठा नहीं देना चाहते हैं और वे बेचारे आपके वकालत करते हैं । हम तो वकील को देखते हैं बहस करते हुए सभापति महोदय कोर्ट में तो फीस मिल गया तो मेरा मुवक्किल एकदम निर्दोष है, अगर उधर से फीस मिला तो कहा कि यह भी सही है । हमलोग वकालत नहीं करें, विरोधी का मतलब है, लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि राजनीतिक दल राष्ट्र निर्माण के साधन है, साध्य नहीं है । हमलोग साध्य बनने का काम करें, लक्ष्य जो मिला है, वह काम करें, नहीं तो हम भ्रष्टाचार में गोता लगावें और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का कमेटी बनावें । माननीय प्रभारी मंत्री जी गये थे विनोद कुशवाहा जी, हमारे यहां अरवल जिला के प्रभारी मंत्री हैं, एकबार सभाकक्ष में मीटिंग हो रही थी, किसी ने कहा कि इंदिरा आवास में लूट हो रहा है, किसी ने कहा कि मनरेगा में लूट हो रहा है, चट से कह दिये कि जॉच की मीटिंग बैठायी जाय तो मैंने कहा कि माननीय मंत्री महोदय, यह भी एक जॉच का विषय है तो क्या, मैंने कहा कि इसमें जो नहीं लूटा होगा, अगर वह मेम्बर बनेगा तब न सही निर्णय होगा तो फिर ये लोग लूटेगा । क्या है आपका भ्रष्टाचार, गंगोत्री है, जब गंगा जल शुद्ध है तो बिसलेरी बोतल का कारखाना क्यों खड़ा किये थे और सब देवता आपके पहलवान थे तो बोर्डर पर सिपाही रखने का क्या जरूरत ? गरीब जब हथियार उठावें अपनी रक्षा में अगर उसके साथ न्याय नहीं मिलेगा, हमलोग इसको झेले हैं तो वह हो जायेगा उग्रवादी, जयश्रीराम कहकर के तलवार भेंट करवाते हो, बॉर्डर पर जाइए न, तलवार क्यों भेंट करवाते हैं, तब हो जायेंगे राष्ट्रवादी, वाह रे राष्ट्रवादी का परिभाषा, वाह आप ही है सनातन धर्म, आप ही वैदिक धर्म और आपने सिंधु घाटी की सभ्यता को आपने पूर्ण नाश कर दिया, जहां मानवता था, प्रेम और दया था, राजा-प्रजा एक था और उसको आपने बर्बाद कर दिया । अब आपको किसको बर्बाद करन चाहते हैं, अब लोग सचेत हो गये हैं, जानकारी हो गये हैं, जिस दिन इतिहास को जान जायेंगे, बहुत मुश्किल है-बहुत मुश्किल है । फिर जगह नहीं है, अंग्रेज को जो इंग्लैंड भागने का जगह था, आपको कहीं जगह नहीं बचेगा । इस बात को समझना होगा ।

अगर हम बराबर हिस्सा लेंगे, हम चाहेंगे कि अगला सरकार हमारे विपक्षी दल के नेता को अगर मौका मिल गया और मैं समझता हूँ कि मिलने वाली है तो मैं कहता हूँ कि जितनी जिनकी हिस्सेदारी है, जिनकी जितनी भागीदारी है, सबको बराबर हिस्सा में सारा चीज को वितरण करने की बात की जायेगी । आप कहां से नौकरी

देंगे, सब तो ले लिये तो देंगे किससे, किसको देंगे, इसलिए इसको समझना होगा और नहीं समझियेगा तो मैं किसी को दोष भावना से नहीं बोल रहा हूँ । मैं विधायक बना हूँ, मैं आज तक बोला कि मैं जीत गया हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को कि माता-पिता से बड़ा कोई औलाद नहीं हो सकता है, पद चाहे जितना बड़ा पा ले और जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि वार्ड में मेम्बर हो या पार्लियामेंट का मेम्बर हो, पद चाहे जितना बड़ा हो, मतदाता से बड़ा कोई हो नहीं सकता है, अगर किन्हीं ने यह नहीं समझा तो बर्बाद हो जायेगा । इसलिए मैं चाहूँगा जीत गये तो क्षेत्र के हो गये और सब जनता जो वोट दिया, उसका भी और जो वोट नहीं दिया, उसका भी । हम विपक्ष हैं भले लेकिन हमारी भी बात सुनी जाय ....

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त करें ।

श्री रवीन्द्र सिंह : अगर नहीं सुनी जाती है तो फिर सरकार का ही अंग है विपक्षी, इसको तो आपने समाप्त कर दिया, कितना बढ़िया-बढ़िया शब्द लिखा हुआ है, इसपर कभी हमलोग अमल करते हैं, नहीं करेंगे तो क्या दशा होगा । सभापति महोदय, इसमें किस लिए लिखा हुआ है, हमलोग क्या करते हैं धरती पर जाकर के, मैं कहना चाहता हूँ भ्रष्टाचार की बात करते हैं माननीय मंत्री महोदय, हमको बता दीजिए, आपका निधि में भी कमीशन चलता होगा, आप रोक दिये होंगे, नहीं रोके होंगे, मैं जानता हूँ कि आप नहीं रोके होंगे । अगर कोई मिसाल है तो बता दें कि हम रोक दिये हों, अभी मैं कहना चाहूंगा कि यह सच्चाई बात है, हमलोग यहां बोलते हैं, जनता सुनती है, कहती है कि बताइए यही सब बात, गड़बड़ करते हैं और दूसरे को भी बिगाड़ते हैं । जनता यह सब मूल्यांकन करती है, हम यह महसूस करें कि हम किसी को मान-सम्मान दे रहे हैं, हमको मांगना नहीं है, हमको मान-सम्मान बाजार में नहीं मिलेगी, हम देते जायेंगे, लोग देते जायेंगे, यही अगर चरित्र रहेगा जनता के साथ धोखा करना तो निश्चित रूप से हम तमाम लोग उसके शिकार होंगे। यही कारण है कि विचारों का जब तक परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तो सिर्फ सत्ता बदलने से लूटेरे बदल सकते हैं लेकिन लूट से वंचित जनता नहीं होगी । अब बारी आ गया है कि लूट से बचाना होगा । नहीं तो आपका सब चीज बेकार हो जायेगा । सत्ता बदलने से कोई फायदा नहीं होगा, जब तक चरित्र नहीं बदलियेगा, इसलिए अगर जनप्रतिनिधि.. ....

(व्यवधान)

अरे रुकिए आप, मैं जानता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, माननीय मंत्री महोदय, आप सुन लीजिए, मैं आपसे पूछता हूं, मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय अगर ये राजनीति चरित्र को बदलना होगा, हम तमाम लोगों को बदलना होगा, आप लोग भी

बदलिए, देश के नागरिक हैं तो प्रेम, दया और मानवता रखिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है । अगर ये धर्म नहीं है तो यहां लूटेरा भी धाार्मिक वाह रे, बेईमान भी धार्मिक वाह रे, भ्रष्टाचार भी वो भी भ्रष्ट है वो भी धार्मिक तो अधार्मिक किसको कहेंगे सब तो वही हैं तो हम किसको कहेंगे अधर्मी तो हमलोग लबादा ओढ़ लिये धर्म का और काम कीजिएगा कुकर्म का, धारा जाइयेगा सपोर्ट पर तो जनता फरिया देगी । इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं चाहूंगा अगर मानवता आपमें नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हैं प्रेम और दया के अलावा कोई मानवता नहीं ला सकता है । इसलिए सवाल यही सीधा-सीधा है, अगर आप नहीं समझेंगे तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, हमलोग के इलाके में ही आते हैं हमारे माननीय प्रेम बाबू हमारे नेता हैं, ये कृषि मंत्री हैं ये भी एक बार गए थे । लोदीपुर में एक कृषि फार्म में, मैंने कहा था इस बात को कि यहां जितने किसान को अनुदान मिल रहा है, मैंने कहा था ढैंचा आप खाद के लिए भेजते हैं और मिलता कब है, जब रोहन खत्म हो जाता है तब और जोतायेगा कब 45-50 दिन के बाद होगा, तब दोबारा खाद मिलेगा । आप न बढ़िया सिंचाई प्रचुर मात्रा में देते हैं, न समय पर देते हैं, न बीज देते हैं, न शुद्ध धान मिलता है, कोई चीज आपका नहीं है । नहीं है किसान तो जहां भी है तो मेरा कहने का मतलब है कि धागा लपेटने से, टीका करने से, घंटी बजाने से कोई धार्मिक नहीं बन जाता, बदलना है तो अपने गिरेबान में झांकिए कि हम मानव हैं, मानवता है कि नहीं, नैतिकता है कि नहीं, ये किसलिए लिखे थे इतना गांधी जी ने ये कहा था, आते ही काम कर रहे हैं, सचमुच में इसको किताब पर पढ़ कर के देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, अंदर भी लिखा हुआ है हम लोग करते क्या हैं, लिखित के विपरीत अगर हम चलेंगे तो कितना दिन आपका आचरण सही रहेगा, मैट्रिक क्लास नहीं, एम0एस0सी0 फर्स्ट डिविजन से पास कीजिए, टॉप क्लास से पास कीजिए, लेकिन विचार-आचार का कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब हो जाएगा तो सब सर्टिफिकेट बेकार हो जाएगा । झूठ बोलना, मैंने कहा था एक दिन कि ईश्वर के सब नाम लेकर ओथ लेते हैं, अगर ईश्वर होते तब पार्लियामेंट, विधान सभा में कब का भूकंप आ जाना चाहिए था । उसी का क्रिया खाकर लूट जारी है, कैसे होगा, कौन सा हम जानते हैं,

.... क्रमशः .....

टर्न-22/शंभु/03.03.20

श्री रविन्द्र सिंह : क्रमशः....मतलब ईश्वर का क्रिया खाते हैं और डरते नहीं हैं कहते हैं कि सबमें ईश्वर वास करते हैं । हम कहते हैं कि रेप किया उसमें भी ईश्वर और जिस लड़की

के साथ रेप हुआ उसमें भी ईश्वर ये भगवाने रेप करता है क्या ? क्या मामला है वाह रे देश, वाह रे धर्म, पवनियां के मजदूरी न मिले नचनियां के छूट, अजीब बात है । हम बेटा के लिए दहेज लें और बेटी को दें और दहेज विरोधी का फैसला भी देखें वाह रे देश । ऐसा होगा तो क्या होगा ? हम माननीय विधायक शपथ लिये थे कि दारू नहीं पीयेंगे न पीने देंगे और पीकर एकदम मस्त होकर कह रहे हैं तो क्या कीजिएगा, कीजिए न कार्रवाई कहां कीजियेगा । उस गरीब, मुसहर, भुइयां के यहां जिससे जीता भी है उसके पास जीने का दूसरा साधन भी नहीं था और जीने के कारण उसको जेल में बंद करते हैं और जो पूरा स्टोर करते हैं तो वहां हिसाब-किताब कितना चल रहा है । मैं बताऊं आप जान लीजिए इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी से बदलिये नहीं तो जनता पढ़ रही है, जनता आपकी किताब नहीं पढ़ेगी वह आपको व्यवहार से जानेगी कि जो बोलता है सो करता है कि नहीं । जो बोलिये सो कीजिए झूठ मत बोलिये । इसीलिए मैं चाहूंगा कि जनता के कसौटी पर खड़े नहीं उतरियेगा तो बात वही सही है जो न्यायसंगत हो, तर्कसंगत हो और व्यावहारिक हो, अगर इससे बाहर होइयेगा तो सब बात गलत हो जायेगी । इसीलिए बजट जो है मैं चाहूंगा कि बजट में आ जाय कि जमीन का भी वितरण भूमि सुधार करके उसका समान रूप से वितरण किया जाय नहीं तो उनको मालिक बना दिया जाय जो जोत के करते हैं उनको खाली बनिहार मजदूर नहीं रखा जाय । हम भी खेती करते हैं और आपदा आती है तो रसीद नहीं दे पाता है वह आदमी तो पैसा वह ले लेता है जो पहले के नाम पर दिया था, वह बेचारा वंचित हो जाता है । क्या कीजियेगा उसको ? अब मजदूर जो है किसान है काम, लेकिन मजदूर है । गरीब किसान अपने खेती करता है कुछ आपसे भी लेता है उनसे भी लेता है जिनके पास अधिक खेती है । आप ईमानदारी रखिये और नहीं तो मैं समझता हूँ कि अब धीरे-धीरे 72 वर्ष बात हो गयी लोकतंत्र में अब तक कोई परिवर्तन नहीं और भूखे जो लोग रह रहे हैं रोड पर घर बिना, आप कह रहे हैं कि अहरा पर कब्जा कर लिया है जिनको बहुत बढ़िया-बढ़िया जमीन कब्जा है उनका कब्जा हटान में आपका हालत खराब हो जा रहा है और गरीब को कह रहे हैं बिना व्यवस्था किये हुए हटाने का काम कर रहे हैं, बड़ी बहादुरी करते हैं और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, बहुत लोग तो कहते थे कि नक्सली तो समाप्त हो जायेगा सरकार अगर चाहती तब हम कहते हैं कि अगर वह चाहती तो शोषण भी खतम हो जाता नक्सली पैदा ही नहीं होता, अगर रोकना है तो ऐसे ही कीजिए । मैं अभी भी कह रहा हूँ आधुनिक हथियार की जरूरत नहीं है, आधुनिक विचार की जरूरत है और विचार आपने नहीं लाया तो निश्चित रूप से हथियार से कब्जा करने का मंशा आप तोड़ दीजिए । मैं दावा करता हूँ आप कभी नहीं लड़ पाइयेगा पब्लिक

से वह बिगड़ जा रही है । अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय नहीं हैं लेकिन मैं सभापति महोदय से कहना चाहूंगा कि रोड पर जो एक्सीडेंट होता है । हम जानते हैं कि एक मरेगा तो नहीं मिलेगा तो क्या उसके साथ दो-चार मरेगा तब मिलेगा ? उसमें भी परिवर्तन कीजिए जो है अनुदान सबको दीजिये, इलाज सबका सरकारी खर्चा पर हो, विकलांग हो जाय तो उसकी मदद की जाय । सोन कमांड क्या ? सब नहर सिजनली हो गया और बरसाती हो गया । तीन प्रमंडल का 12 जिला सोन नहर से प्रभावित है, अगर समय पर पानी नहीं मिलेगा तो समय पर दाना नहीं डालेगा बीज का और समय पर नहीं डालेगा तो रोपनी भी नहीं होगा । नहर के पिछले हिस्से में पानी नहीं पहुंच पाता है, सब बैंक खतम हो रहा है इसलिए पक्कीकरण कराया जाय ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री रविन्द्र सिंह : और युद्ध स्तर पर सोन कमांड का जो है इन्द्रपुरी बराज में स्टोर बनाया जाय और रिहन्द और बांध सागर का निर्भरता खतम हो, अपना स्वतंत्र हो जाय । मैं यही चाहता हूँ कि अगर बजट में आया है तो कृषि के लिए सिंचाई, कृषि के लिए दवा, उपकरण सब आसानी से सस्ता उपलब्ध हो और बाजार उसको नजदीक मिल जाय ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय, मैं 2020-21 के लिए पेश कृषि विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूँ । महोदय, हम सबसे पहले आज एन0डी0ए0 की सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी और कृषि विभाग के मंत्री आदरणीय प्रेम कुमार जी को बधाई देना चाहूंगा कि आज उनके कुशल नेतृत्व में किसान की आमदनी दुगुनी हो रही है । महोदय, आज विपक्ष के साथी माननीय सदस्य का हम सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के भी माननीय सदस्य का हम टोकाटोकी सुन रहे थे जब हमारे पक्ष के सदस्य बोल रहे थे और माननीय विपक्ष के सदस्य का प्रवचन भी हम सुन रहे थे, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि आज किसान की चिंता हमारे माननीय सदस्य विपक्ष के सदस्य कर रहे हैं । लेकिन उस समय कहां थे जिस समय में 70 साल- देश की आजादी का 70 साल हुआ और एक ही दल के 54-55 साल सरकार चलाये और विपक्ष के लोग भी 15 साल सरकार चलाये, लेकिन महोदय उस समय दिन में किसान की बात करते थे, लेकिन जब घर जाते हैं तो परिवार की चिंता करते हैं कि हमारे परिवार की उन्नति कैसे स्थायी हो । महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि उस समय कहां थे जब गांव के किसान, मजदूर शहर के तरफ जा रहे थे । गांव के किसान जो हमारे भाई हैं वह अपनी जमीन बेचने पर मजबूर थे और शहर में 1 कट्ठा जमीन खरीदने को मजबूर थे इसलिए क्योंकि गांव में कोई व्यवस्था हमारे किसानों के लिए नहीं था । जब किसान

भाइयों के घर में कोई बीमार होता था तो खटिया पर लादकर शहर की ओर जाते थे । किसी गांव में शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी कि अपने परिवार के बच्चे को वह शिक्षा दे सके, लेकिन आज महोदय, मैं इस सदन में कहना चाहूंगा गर्व से कहना चाहूंगा कि आज जो लोग शहर में बसे हैं आज गांव के तरफ जा रहे हैं और गांव के तरफ अच्छे-अच्छे घर बनाने का काम कर रहे हैं । इसलिए कि गांव में विकास हुआ है, किसान भाइयों के लिए विकास हुआ है । आज उस गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है, आज स्वास्थ्य की सुविधा है । आज गांव से शहर में जाने के लिए 10 से 15 मिनट का समय लगता है और गांव से शहर की ओर लोग जा रहे हैं । इसलिए आज हम एन0डी0ए0 की सरकार को बधाई देना चाहेंगे कि आज हमारे गांव की व्यवस्था शहर से भी अच्छा होते जा रही है । मैं कहना चाहूंगा हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे आदरणीय मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसानों की आमदनी दुगुनी करेंगे । मैं आपको इस सदन से बताना चाहूंगा माननीय महोदय कि किसान अपनी आमदनी को दुगुना कर रहा है और अगर आपको दिखायी नहीं देता है, आप नहीं जानते हैं तो चलिए मेरे साथ जब किसान के बीच में चलियेगा तो मैं बताने का काम करूँगा कि आज जो किसान डीजल खरीदकर पंपसेट चलाते थे और पैसा ज्यादा लगता था और उनकी आमदनी कम होती थी, पानी का पटवन करते थे तो उसमें खर्च ज्यादा होता था । महोदय, लेकिन आज कोई खेत नहीं है, आज 80 परसेंट ऐसा खेत है जिसमें बिजली पहुंच गयी है और किसानों को पानी मिल रहा है, सिंचाई कर रहा है और सीधे आमदनी दुगुनी हो रही है । महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारी सरकार दुगुनी आमदनी के तरफ अग्रसर है । मैं बताना चाहूंगा कि पूर्वी चम्पारण में मदर डेयरी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण हुआ और बापूधाम मिल्क केन्द्र एवं कलेक्शन सेंटर आज गांव-गांव में दूध कलेक्शन कर रहा है और किसानों को 50 रू0 से 60 रू0 तक किसानों का दूध का दाम मिल रहा है और किसान खुशहाल है । महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि प्रतिमाह 10 करोड़ रूपया किसानों के खाते में जाता है और उसमें कोई बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट खाते में जाता है । आज किसान खुश है और हमारे किसान के परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और परिवार खुश है ।

क्रमशः

टर्न-23/03.03.2020/ज्योति-पुलकित

क्रमशः

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि बात कर रहे थे हम कल भी इस सदन में सुन रहे थे बेरोजगारी की बात कर रहे थे लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि

आज बेरोजगारी की बात हो रही है लेकिन आज बेरोजगारी भी दूर हुआ है आज एन.डी.ए. के कुशल नेतृत्व में बेरोजगारी भी दूर हुई है । हमारे गांव की महिलाएँ जीविका दीदियों के माध्यम से लाखों समूह बनाने का काम किया है । मैं बताना चाहूंगा कि हमारे परिवार के हमारे गांव के हमारे समाज की महिलाएं जब पैसा के लिए किसी के दरवाजे पर जाती थीं और हमारे भाई और हमारी किसान भाई जब जाते थे तो क्या होता था वहॉ चार दिन पॉच दिन जाते थे और वहाँ पर ....

सभापति(श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह): अब आप समाप्त करिये ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : वहाँ जाते थे और जब उनको दस रुपये सैकड़ा, पाँच रुपया सैकड़ा के दर से उनको पैसा दिया जाता था लेकिन आज जीविका दीदी के माध्यम से जितने हमारी समूह की महिलाएं हैं आज हमारा मोदी बैंक घर घर जाता है और उसको पैसा देता है और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें आज जो है, आज रोजगार सृजन कर रही हैं और आगे बढ़ रही है । मैं आपके माध्यम से आदरणीय माननीय कृषि मंत्री जी से दो मांग अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारे मेहषी में लीची की बहुत अधिक खेती होती है, वह प्रसिद्ध है लेकिन जिस तरह गेहूँ और धान का इन्श्योरेंस कराते हैं उसी तरह लीची की भी इन्श्योरेंस कराया जाय । एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कि भारत सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है मेहषी कृषि फार्म की जमीन है लीची पौध अनुंसधान केन्द्र के लिए और वहॉ पैसा भी आवंटित हो गया है और जमीन के लिए एन.ओ.सी. की मांग हो रही है, मांग की है मैं आग्रह करुंगा कि एन.ओ.सी. की व्यवस्था करायी जाय ताकि मेहषी कृषि फार्म के जमीन में लीची पौध अनुसंधान केन्द्र का निर्माण हो सके । महोदय, आपने मौका दिया इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए और पिपरा विधान सभा के तमाम मतदाता मालिकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ । जयहिंद, जय भारत ।

सभापति (श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह) : माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार, आपका 4 मिनट का समय है ।

श्री राजेश कुमार : सभापति महोदय, आज मैं विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हूँ । आज जो कृषि विभाग का बजट माननीय वित्त मंत्री और सह उप मुख्यमंत्री द्वारा 25 जनवरी, 2020 को यह लाया गया है । उसमें कुछ बात बजट के पक्ष में है । जैसे हम लोगों को विपक्ष की आशा थी, किसानों को आशा थी, बेरोजगार नौजवानों की आशा थी उस आशा पर यह बजट खरा नहीं उतरा है । वह इसलिए भी कि बजट के शुरु में आप देखेंगे तो बड़ी ही चालाकी और चतुरता से उप

मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है पिछली सरकार 2004-05 में 23 हजार 885 करोड़ को बढ़ाकर आठ गुणा की है जिसमें 2 लाख 501 करोड़ रुपये का प्रावधान किए हैं और यह सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है । इस संदर्भ में मुझे यह कहना है कि इस बजट को यदि आप पूरे 2004 और 2020 में आयेंगे तो करीब 13 साल का ये आंकड़ा है और यह 13 साल में 15 साल इस सरकार ने काम किया है और इस 15 साल में इनका आंकड़ा यदि हम प्रति ईयर करते हैं तो 15 साल में जिसमें 15 हजार 423 करोड़ प्रतिवर्ष हुआ, 13 साल में और यदि इसको 13 साल को प्रति माह के हिसाब से करेंगे तो प्रति माह जो है 1285.86 करोड़ 26 हजार रुपये हुए । अब यह सरकार कहती है कि हमने आठ गुणा बढ़ोत्तरी कर दिया तो यह आपका पूरे देश का जो बजट है उसमें पूरे देश के बजट में यह आपका पच्चीसवॉ स्थान पकड़ता है और सरकार कहती है कि हमने 8 गुणा बजट कर दिया । इस संदर्भ में मैं गोरख पाण्डे का जी का एक शेर है कि '' हवा का रुख हम समझते हैं, हवा का रुख हम समझते हैं, हम उसे पीठ क्यों देते हैं, हम समझते हैं क्या है पक्ष में, विपक्ष में हम समझते हैं, हम इतना समझते हैं कि समझने से डरते हैं और चुप रहते हैं ।'' आप बजट में आपने कहीं न कहीं पिछली सरकार को घेरने की कोशिश की है लेकिन यहॉ के किसानों को आपने मार्गदर्शन नहीं दिया है । यदि आप एक उदाहरण लेना चाहेंगे तो यू.पी.ए. सरकार की जो एक उपलब्धि का उदाहरण देना चाहेंगे कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो पूरे देश में किसानों ने आत्महत्या की और उनकी दर्द को उनकी पीड़ा को समझने के लिए मनमोहन सिंह प्रधान मंत्री ने जो 400 करोड़ रुपये की ऋण माफी किया किसानों का और आपके बजट में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो किसान लगातार मौसम की मार से मार खाता है उसके लिए आपने कुछ नहीं किया है । वित्त मंत्री का बजट भाषण जो 25 फरवरी को हुआ उसमें पेज नं. 21 और कंडिका 5 में एक नयी योजना हमने देखी है । उस योजना की मैं जरुर सराहना करता हूँ लेकिन जैसा कि '' मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत नयी फसल प्रबंधन एवं नयी बुआई की विधियों जैसे हैप्पी सीडर व जीरो टिलेज से तथा रेज्ड बेड पर बुआई एवं तकनीक के तहत किसानों को अनुदान देने का प्रावधान है और इसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 6065.50 लाख का प्रावधान किए हैं हम एक उदाहरण देना चाहेंगे कि कुटुम्बा विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जो है बड़ी अपनी इच्छा से वहॉ गए हैं मैं अभिनंदन करता हूं कि कुटुम्बा प्रखंड में चिलखी गांव में स्ट्रॉबेरी का निरीक्षण करने गए थे और 24, 25 और 26 तारीख की ओलावृष्टि में किसानों

की फसल बर्बाद हो गयी है और वहां के किसान स्ट्रॉबेरी की खेती से लाभ लेने से वंचित हो गए हैं ।

सभापति (श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह) : आपका समय समाप्त हुआ । श्री राजेन्द्र कुमार आपका समय तीन मिनट है ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, कृषि विभाग की अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ । महोदय, सदन में बहुत सारे आंकड़े सामने में मिले हैं और आंकड़ों की बात करना हम उचित नहीं समझते । हमारे माननीय सदस्य ललन पासवान जी बड़े भाई हैं । उनके द्वारा कुछ बातें सदन में आयी हैं । हम आज सदन के माध्यम से ललन बाबू को बतलाना चाहते हैं कि जिनकी बात आप कर रहे थे, आंकड़े की जब बात आयी है तो आप सदन छोड़ कर बाहर थे आपको पता चल जाता । जहाँ घोटाले की बात करते हैं और निर्लज्जता की हद करते आप लोग 56 तरह का जो घोटाला किया हो सृजन घोटाला से लेकर पैखाना घोटाला तक वह घोटाले पर 15 साल को ले जाते तो आप अपने विकास के संदर्भ में शायद बतलाना नहीं चाहते इसलिए खास कर कहना चाहते है कि आप यह बात बतलाये हैं कि पिछड़ा का बेटा मंत्री है मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि पिछड़ा का बेटा मंत्री है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं लेकिन आज जो किसानों की हालत हो गयी है बिहार में बटाईदार किसान कौन है ? जो 60 फीसदी किसान हैं अपने मेहनत के बल पर फसल को उपजाते हैं और सरकार कहती है कि यह एवार्ड मिलता है, यह एवार्ड मैंनेजएवार्ड है इसको एवार्ड नहीं कहते यह मैनेजएवार्ड लेकर और पीठ थपथपाने का काम करते आप लोग और कहते कि एवार्ड मिलता है । यह जो बैकवर्ड, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति के 60 फीसदी जो किसान हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं हम बड़ी आग्रहपूर्वक कहना चाहते हैं कि आज भी ये तड़पते हैं इनको डीजल अनुदान नहीं मिलता है । इनको खाद का अनुदान नहीं मिलता है क्योंकि ये अभी चिन्हित नहीं हो पाए अभी तक कि हम किसान हैं ।

क्रमशः

टर्न–24/कृष्ण/03.03.2020

श्री राजेन्द्र कुमार (क्रमश :) इनके द्वारा जो मिहनत किया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि उन बटाईदार किसानों को चिन्हित करके अगर परिचय पत्र नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर पिछड़ा, अतिपिछड़ा और दलितों के साथ भारी अन्याय है । उन्हें परिचय पत्र क्यों नहीं दिया जाता, हम आग्रह करना चाहते हैं । शहरों से आये हुये

हमारे माननीय विधायक हैं या जो भाजपा के माननीय विधायक हैं, वे किसानों के दुख एवं तकलीफ के विषय मे बोलते हैं । महोदय, हम चैलेंज करते है कि भाजपा के जितने भी विधायक हैं, उनमें 95 परसेंट शहरों से जीत कर आते हैं । इनको क्या पता है कि किसाानों का दुख-दर्द क्या है ? भैंस के आगे बिन बजाये, भैंस रहे पगुराय । आप कहते हैं कि आप किसानों के संदर्भ में बोलना चाहते हैं । किसानों के विषय में आपको कुछ जानकारी नहीं है । सभापति महोदय, खास करके हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहेंगे कि आज कृषि आधारित रोजगार सृजन की जो बातें आयी थी, फुड प्रोसेसिंग की बात आयी थी, वह क्या हुआ ? अगर निश्चित तौर पर सरकार गंभीर होती, गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, अन्नदाता किसान जो भगवान हैं, उसके प्रति यह सरकार गंभीर नहीं है । अगर सरकार गंभीर होती तो फुड प्रोसेसिंग के द्वारा रोजगार देने का काम करती ।

श्री तारकिशोर प्रसाद: माननीय सभापति महोदय, हम जिस पार्टी से आते हैं, भारतीय जनसंघ के समय से ही हम सबों की एक राजनीतिक अवधारणा रही है कि हर खेत को पानी और हर खेत को काम देंगे । लेकिन हमारी एन0डी0ए0 सरकार ने उस अवधारणा को आगे बढ़ाकर हर खेत को पानी, हर खेत को बिजली और हर गांव को सड़क देने का काम किया और हमारा जो यह नेतृत्व है सम्मानीय नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी जी का, उनके मार्गदर्शन में कृषि के क्षेत्र में हमारे जो माननीय कृषि मंत्री हैं प्रेम कुमार जी, उनके द्वारा एक गुणात्मक परिवर्त्तन कृषि के क्षेत्र में लाया गया । लगता है कि हमारे जो विपक्ष के भाई हैं, वे इस बात को समझने के लिये तैयार नहीं हैं । मुझे काफी दुख हुआ, मुझे लगता है कि मेरा इस सदन में 15वां साल है, लेकिन पहली बार विपक्ष के द्वारा कृषि पर कोई दृष्टि ही नही रखी गयी, एक बतकही के द्वारा लगातार बेंच पीटा जाता रहा और लोग वाद-विवाद करते रहे लेकिन कृषि पर उन्होंने एक भी दृष्टि नहीं रखी । जबकि आपको पता है कि 89 परसेंट आबादी गांवों में निवास करती है और 76 परसेंट आबादी खेती पर निर्भर है। उसके बावजूद भी विपक्ष के द्वारा कोई विजन नहीं देना इस बात का सबूत है कि हमारा जो विपक्ष है, वह कृषि के प्रति गंभीर नहीं है ।

सभापति माहेदय, अभी हमारे राजेन्द्र भाई बोल रहे थे कि कृषि कर्मण का जो पुरस्कार 2016-17 में मक्का का और 17-18 में गेहूं पर मिला है, उन्होंने कहा है कि यह प्रबंधन के द्वारा दिया गया है । महोदय, हमें दुख होता है जब राज्य सरकार ईमानदारी से कोई काम करती है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है । अगर हम पूरे देश में बेहतर परिणाम ले रहे हैं और उसके कारण भारत सरकार हमें पुरस्कृत

करती है तो विपक्ष कहता है कि यह प्रबंधन का कमाल है । यह अपने आप में दुखद है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अभी राजेन्द्र राम जी ने एक और बात कही कि जो शहरी क्षेत्र के विधायक हैं, वह कृषि पर बात करते हैं । अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से उनको बताना चाहते हैं और खुली चुनौती देते हैं कि इसी विधान सभा में अलग से कृषि पर एक सेमिनार हो जाय और सारे शहरी विधायक कृषि पर जितनी बातें कहेंगे और सरकार की बात को कहेंगे और जो बतकही पर ताली बज रही थी, सामाजिक परिवर्त्तन और सामाजिक बदलाव की बात पर जो बतकही चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि रैली के पहले जो रात में नौटंकी और जो नाच हुआ करता था, उसी तरह की बातें हो रही थी । महोदय, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, हमारा जो पूर्णियां प्रमंडल है, पूर्णियां प्रमंडल और नौगछिया जिला में केला की खेती बड़े पैमाने पर होती है और वहां पनामा ब्रीज के कारण जो केला की खेती है उसमें काफी झरण हुआ है । हम आग्रह करेंगे कि कटिहार में केला का टिशू प्रयोगशाला खोलें, जिससे वहां के किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी को जहां कृषि कार्यालय सिर्फ जिला स्तर पर हुआ करता था, वहां इन्होंने प्रत्येक पंचायत में एक कृषि सलाह केन्द्र को खोलकर किसानों को उनके दरवाजे पर अपनी बातों को कहने का काम किया । लगातार कृषि मेला के द्वारा जो कृषि यंत्र है, उसको किसानों तक पहुंचाने का काम किया है । हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दोगुनी करेंगे । वह फसल का बेहतर ऊपज और फसल के लागत में कमी करके इस को हम पूरा कर सकते हैं । उस ओर हमारी सरकार लगातार गंभीर है और केन्द्र सरकार सहयोग करके इस परिणाम के करीब पहुंचाने का काम किया है ।

महोदय, हम अपने कृषि मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जितने भी किसान भवन बने हैं, वहां पर जांच प्रयोगशाला की स्थापना करें क्योकि कृषि विज्ञान केन्द्र और जिला स्तर का जो कृषि कार्यालय है, सिर्फ उसी स्तर पर अभी मिट्टी जांच केन्द्र है, अगर अब इसे वहां तक करेंगे, मुझे लगता है कि इससे किसानों को बेहतर लाभ होगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आपका 2 मिनट समय ही बचा है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पहले बिहार के किसान परम्परागत ढंग से खेती करते थे, जो जलवायु परिवर्त्तन हुआ है और उसके कारण जो नुकसान हुआ है, उसको देखते हुये हमारी सरकार ने जलवायु के अनुरूप, मौसम के अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने हेतु

कार्यक्रम तय किया है और उसी का परिणाम है कि हम मौसम के अनुरूप अपने फसल का ऊपज कराकर बेहतर परिणाम ले रहे हैं । हम आपके द्वारा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि कृषि के क्षेत्र में बिहार में आपने एक बड़ा परिवर्त्तन लाने का काम किया है, सदियों तक बिहार की जनता उसको याद रखेगी । बिहार के हमारे जो किसान हैं, वे अन्नपूर्णा हैं, उनके लिये आप जो बेहतर काम कर रहे हैं, आनेवाले दिनों में बिहार में एक स्वर्णगाथा के रूप में उसको जाना जायेगा । बहत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कृषि विभाग द्वारा पेश किये गये बजट पर विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार एवं सुझाव रखे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के प्रति आभार और सम्मान प्रकट करना चाहता हूं कि आपके कुशल निर्देशन में कृषि रोड मैप के माध्यम से राज्य के किसान उतरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। कृषि रोड मैप कार्यक्रमों के कार्यान्वय के फलस्वरूप वर्ष 2011-12 में चावल के क्षेत्र में, 2012-13 में गेहूं के क्षेत्र में और 2015-16 में मोटे अनाज मक्का में क्षेत्र में 2016-17 में मोटे अनाज मक्का तथा 2017-18 में गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिये भारत सरकार द्वारा चार-चार राज्यों को कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार दिये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी जी, जिनके बेहतर वित्तीय प्रबंधन है, राज्य विकास को रफ्तार देने का काम किया है । महोदय, आजादी के बाद पूर्ववर्त्ती सरकारों द्वारा कृषि एवं किसानों के विकास के लिये योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं किये जाने के कारण किसानों के हालत में जितना सुधार होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया । महोदय, किसानों के समक्ष आज भी कई चुनौतियां हैं, जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है । महोदय, इस अवसर पर मैं महान कवि दुष्यंत जी की दो पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा -

"यह पीर हुई पर्वत सी,
अब पिघलनी चाहिए ।
इस हिमालय से अब ,

कोई गंगा निकलनी चाहिए । "

अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के करोड़ों किसानों की ओर से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं । देश में पहली बार सशक्त नेतृत्व में सबल किसान का सपना कृतार्थ हो रहा है । महोदय, जब से बिहार में एन0डी0ए0 की सरकार एवं केन्द्र में हमारी सरकार आयी है, किसानों के लिये ऐतिहासिक कार्य किये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि कृषि रोड मैप से जो बिहार को सम्मान मिला है और जिस तरह से जलवायु परिवर्त्तन हो रहा है, मौसम बदल रहे हैं, उन चुनौतियों में हमारे किसानों ने बहादुरी दिखाने का काम किया है ।

क्रमश :

टर्न-25/अंजनी/दि0 03.03.2020

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : (क्रमशः) : हम राज्य सरकार की ओर से बिहार के किसानों को बधाई देते हैं कि उनके परिश्रम, मेहनत का परिणाम है कि लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार का अवार्ड मिल रहा है । महोदय, पहली बार हमलोगों ने बिहार में किसानों के लिए पोर्टल बनाया है और 1 करोड़ 24 लाख किसान पंजीकृत किये गये हैं । महोदय, हमारी सरकार रैयत किसान को ही नहीं, हम बटाईदार किसानों को भी सारी सुविधा प्रदान करने का काम कर रहे हैं । महोदय, बटाईदार जो हमारे किसान हैं, उनका हम निबंधन कर रहे हैं । डीजल अनुदान बटाईदारों को भी दिया जा रहा है । आपदा की स्थिति में कृषि इनपुट अनुदान बटाईदारों को दिया जा रहा है । बीज, खाद सभी प्रकार की जो योजनायें हैं, बिहार पहला राज्य है, जहां रैयत के साथ गैर रैयत को हमारी सरकार सुविधा देने का काम कर रही है । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि कृषि इनपुट सब्सिडी में 6 लाख 19 हजार 202 गैर रैयत किसानों को अनुदान का लाभ मिला है । राज्य सरकार द्वारा किसानों की सहायता के लिए सिंचाई के लिए डीजल पर अनुदान की राशि 50 रूपया प्रति लिटर से बढ़ाकर 60 रूपया प्रति लिटर किया गया है । वर्ष 2019-20 में 01 अप्रैल 2019 से अब तक 6.41 लाख किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मद में 88.45 करोड़ रूपया का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया गया है । बाढ़/सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को आकस्मिक फसल का बीज मुफ्त उपलब्ध कराया गया है । आपदा से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए जब-जब बिहार में संकट आया है, वर्ष 2018 में जब खरीफ के मौसम में हथिया नक्षत्र में बारिश नहीं हुई थी और राज्य में 25 जिले के 280 प्रखंड जो थे, वे सुखाड़

की चपेट में आ गये और माननीय मुख्यमंत्री जी दशहरा के समय में अविलम्ब बैठक बुलाकर साढ़े 14 लाख किसानों के खाते में 934 करोड़ डी0बी0टी0 के माध्यम से राशि उपलबध कराने का, कृषि इनपुट देने का काम किया गया । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में पूरे राज्य में 82 लाख किसानों ने ऑनलाईन अप्लाई किया और भारत सरकार के पोर्टल पर 62 लाख को लोड किया और अभी तक हमने 56 लाख किसानों के खाते में 27 अरब, आजादी के बाद पहली बार 27 अरब 45 करोड़ 42 लाख रूपये उपलब्ध करा दिये गये । एक समय था, कांग्रेस का राज था, तत्कालिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि 100 रूपया दिल्ली से चलता है और रास्ते में 90 रूपया लिकेज हो जाता है लेकिन हमारी सरकार ने 100 में 100 रूपया खर्च करती है । हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में 2745 करोड़ रूपया दिया गया, हम चैलेंज देते हैं कि अगर पैसा नहीं गया होगा तो जो सजा दीजियेगा, उसके लिए हम तैयार हैं । डी0बी0टी0 के माध्यम से खाते में राशि जा रही है । पहली बार जब शिकायत आयी बीज के बारे में कि किसानों को समय पर नहीं मिल पाता है तो हमलोागों ने ऑनलाईन व्यवस्था किया और पहली बार किसानों को ऑनलाईन व्यवस्था किया गया । रब्बी के मौसम में सात लाख किसानों का पोर्टल पर लोड है, कोई भी व्यक्ति उसकी जांच कर सकता है, किस किसान को किस पंचायत में, किस प्रखंड में दिया गया और पहली बार हमलोगों ने बांका जिले से किसानों के लिए बीज होम डिलेवरी करना शुरू किया है और आनेवाले समय में बिहार राज्य बीज निगम है, हमने तय किया है कि अब किसानों को दुकान का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, हम चरणबद्ध तरीके से किसान भाईयों को हम होम डिलेवरी के माध्यम से बीज उपलब्ध कराने का काम करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : अभी तो इन्होंने अपना भाषण शुरू ही किया है ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, हम कहना चाहते हैं कि वर्ष 19-20 में हमने पहली बार हॉर्टिकल्चर निदेशालय जो हमारा है 23 जिलों के 14 बागवानी फसलों के लिए चिंहित किया गया है । प्रकृति ने हमें वरदान दिया है....

अध्यक्ष : एक मिनट रूक ही जाइयेगा तब स्थिर से बोलियेगा ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, तेरे अश्क सियासत वाले, अपने दर्द मुहब्बत वाले,
बिन दरबाजों का घर हूँ मैं, कौन लगाये मुझपे ताले ।
प्यास सदियों की है लम्हों में बुझाना चाहे,
कत्ल करके जमाने से मुझको फसाना चाहे,

अंग्रेज से लेकर कल तक किसानों को किन-किन ने लूटा है,
सबको पता है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन से बहिगर्मन किये)

सब कर लेना, लम्हें जाया मत करना ।
गलत वक्त पर, जज्बे जाया मत करना ।।
सूखे रेत वाली नदी, बरसात में बाढ़ लायेगी ।
भूलने की आदत है जमाने की, तुम्हारी भी भूल जायेगी ।।

महोदय, नीतीश कुमार जो हमारे नेता हैं एन0डी0ए0 के, उनका जो लक्ष्य है-

हयात ले के चलो, कयानात ले के चलो ।
चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो ।।
विकास ही हमारा मसौदा है, किसी से नहीं कोई सौदा है ।

महोदय, विपक्ष के लोगों को मौका मिला था लेकिन वे मौका चूक गये । महोदय, जब अच्छा काम हो रहा है तो उनको परेशानी हो रही है । जल-जीवन-हरियाली एवं बदलते मौसम पर-

बड़ी तपीश है, अपने गुनाहों की शहर का मौसम खुशगवार नहीं होता ।
करते रहते प्रकृति से छेड़छाड़, कहते हैं राजी परबर दिगार नहीं होता ।।
पेड़ रहे तो पत्ते, फूल और फल भी आयेंगे ।
थे दिन अगर बुरे, तो अच्छे भी आयेंगे ।।

महोदय, मुझे खुशी है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल अगुवाई में आज बिहार विकास के मार्ग में आगे बढ़ रहा है और लगातार हमलोग काम कर रहे हैं और आगे के लिए प्रयास कर रहे हैं और जिन साथियों का सुझाव हेतु आया है, उसपर हम निश्चिततौर पर विचार करेंगे । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि बिहार को प्रकृति ने हमें वरदान दिया है और उसी का परिणाम है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल अगुवाई में बिहार विशेष उद्यानिक फसल उत्पाद विकास योजना शुरू किया और आज आम के लिए भागलपुर, दरभंगा, पटना, सहरसा, टमाटर के लिए रोहतास, हरी मिर्च के लिए समस्तीपुर, लहसुन के लिए पूर्वी चम्पारण, हल्दी के लिए पश्चिम चम्पारण, मटर के लिए भोजपुर और अनानास के लिए किशनगंज और लीची के लिए समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, केला के लिए कटिहार, खगड़िया और प्याज के लिए शेखपुरा और बक्सर, आलू के लिए नालन्दा, अमरूद के लिए कैमूर, मधु के लिए वैशाली और पपीता के लिए गया, 14 क्रॉप के लिए 23 जिलों का चयन किया गया है । महोदय, कलस्टर में खेती करने जा रहे हैं, इन जिलों में किसानों को मोटिवेट करके हमने तय किया है । 10 लाख की योजना है और 9 लाख

सबसिडी है, किसान भाई को मात्र एक लाख रूपया लगाना होगा । कलस्टर में खेती होगी और खेती के बाद ड्रेसिंग की व्यवस्था है, पैकेजिंग का है और प्रोसेसिंग का है । माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि बिहार का व्यंजन देश के हर थाली में हो, उसको कृषि विभाग साकार करने का काम कर रही है । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि बागवानी विकास योजनाओं के तहत वर्ष 21019-20 में 585 हेक्टेयर में आम, 24 हेक्टेयर में अमरूद, 98 हेक्टेयर में लीची, 1383 हेक्टेयर में टिशू कल्चर केला, 91 हेक्टेयर में पपीता, 11 हेक्टेयर में स्ट्रॉबेरी के नये बागान की स्थापना के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गयी है ।

महोदय, ड्रिप तथा स्प्रींक्लर सिंचाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में किसान भाईयों को कम पानी में खेती कैसे हो और हमलोगों ने माइक्रोऐसन के माध्यम से 90 प्रतिशत अनुदान है, 10 प्रतिशत किसानों को लगाना पड़ता है । पहले व्यवस्था काफी कठिन थी, इसको हमलोगोकं ने सरल बनाया है । स्प्रींक्लर पर 75 परसेंट अनुदान सरकार दे रही है और पहली बार हमलोगों ने कम्युनिटी पर पांच हेक्टेयर पर मुफ्त का एक बोरिंग भी देने का फैसला हमने किया है ताकि किसान को बोझ न पड़े। जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत कृषि विभाग के द्वारा मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है । राज्य के 13 जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा किनारे दोनों ओर हम जैविक खेती करने का है और जो हमारा शेष जिला बच गया है, उसके लिए निश्चित तौर पर सरकार की योजना है । हम निश्चित तौर पर उन जिलों को भी 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर योजना कार्यान्वित की जा रही ाहै , जिससे जैविक खाद, बीज, दवा आदि क्रय के लिए 11,500/-रूपये प्रति एकड़ सहायता दी जायेगी, तीन वर्षों तक प्रमाणीकरण का काम निःशुल्क होगा ।

क्रमशः

टर्न-26/राजेश-राहुल/3.3.20

श्री प्रेम कुमार, मंत्री, क्रमशः महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-21 में जैविक खेती के अतिरिक्त महोदय, अन्य सभी जिलों में आने वाला जो हमारा वित्तीय वर्ष होगा, वहॉ भी हमलोगों ने जैविक खेती की योजना बनाने का काम किया है । जैविक प्रमाणीकरण के लिए किसानों को कोई शुल्क नहीं देना होगा,इसका वहन राज्य सरकार करेगी और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बिहार महोदय होगा । महोदय, हम कहना चाहते है खाद की चर्चा कर रहे थे महोदय, खरीफ के मौसम में महोदय, हमें जरुरत था 9 लाख मिट्रिक टन और मुझे बताते हुए यह खुशी हो रही है कि 9 लाख 79 हजार

मिट्रिक टन आज बिहार में खाद है, उसीतरह से महोदय रब्बी में 19-20 में 12 लाख मिट्रिक टन की जरुरत थी, तो हमें समीक्षा में जब मालूम हुआ कि शौर्ट कर रहा है दो लाख मिट्रिक टन, तो हमने तुरत ही माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाया और भारत सरकार से पत्राचार किया और तुरत वहॉ से खाद हमने मेकअप कराया और अभी तक महोदय उर्वरक की जो शिकायत आयी है, तो 1266 जगहों पर छापामारी भी की गयी है, 199 अनियमितता भी पायी गयी है, 16 एफ0आई0आर0 भी किया गया है, 147 अनुज्ञाप्ति को रद्ध भी किया गया है और 288 लोगों से महोदय स्पष्टीकरण की मांग भी की गयी है, इसतरह महोदय लगातार हमलोग एक-एक बात को बारिकी से देख रहे हैं और फसल अवशेष प्रबंधन पर बिहार में एक बड़ा ही सेमिनार हुआ था और इसमें दुनिया के कई देशों के लोग आये थे और किसानों के सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाह पर हमलोगों ने कृषि यांत्रिक मशीन पर 80 प्रतिशत तक अनुदान देने का काम कर रहे हैं, राज्य सरकार जल एवं मिट्टी के संरक्षण के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में मिट्टी एवं जल संरक्षण योजना के तहत 2350 जल संचय संरचना का निर्माण किया गया है, गाद की सफाई आदि भी कार्य किया गया है और 450 हेक्टेयर में पौधारोपण का कार्य किया गया है, 1916.21 हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है, पूर्वोत्तर भारत के लिए हरित क्रान्ति योजनान्तर्गत 680 सामुदायिक सिंचाई कूप, निजी बोरवेल एवं सामुदायिक बोरवेल की स्थापना की गई है एवं 2347 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था की गई है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना प्रतिबूंद अधिक फसल अंर्तक्षेप अन्तर्गत 306.5 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है महोदय । जलछादन उपलब्धी तक 560 संचय संरचना का निर्माण किया गया है इस सुविधान्तर्गत 2369.51 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है । महोदय, आधुनिक कृषि तकनीक के प्रचार-प्रसार के लिए राज्य के 534 प्रखण्डों में, 447 प्रखण्डों में हमारा ई-किसान भवन हमारा काम कर रहा है और जिलों में महोदय पहले हमारे विभाग के निदेशालय अलग-अलग थे लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निदेश पर समेकित कर, संयुक्त कर राज्य के सभी स्थानों पर कर लिये गये है,जब गांव के दौरे पर जाते थे, तो किसान भाइयों ने कहा कि ब्लॉक जाने में काफी कठिनाई होती है, महोदय, इसका क्या समाधान निकल सकता है हमारे पास बहुत से कृषि सलाहकार हैं, कृषि समन्वयक हैं उसका सही से कैसे समाधान खोजा जाता है और महोदय हम लोगों ने 8405 ग्राम पंचायतों में जहां हमारा पंचायती राज भवन था और जहां नहीं भी था किराये पर मकान लेकर महोदय आज 8405 ग्राम पंचायतों में किसानों की सहायता के लिए कृषि कार्यालय शुरू किए गए हैं । महोदय 2019-20 में रब्बी तथा खरीफ के मौसम में

किसान चौपाल लगाए गए, जब कृषि मंत्री महोदय हमें बनाया गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा तो हमें लगा कि कृषि विभाग का कार्य सारा पटना से सम्पन्न नहीं किया जा सकेगा, तो गांवों में जा करके किसान चौपाल लगाए जाए और हमने पहली बार किसान चौपाल लगाए और उस चौपाल में राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में केन्द्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया और किसानों ने अपनी बात रखी । इन सारी बातों का रिकॉर्ड हमने बनवाया था महोदय और जो हमारा कृषि रोडमैप का टास्क है, जो हर जिले में बना हुआ है, उसको देखते हुए यह रिकॉर्ड हमने सभी जिला के डी0एम0 के पास भिजवाया, हमने विभाग को कहा कि आप सभी जिला पदाधिकारियों को कहा कि टास्क फोर्स की बैठक हर मंगलवार को बिहार में होती है, आप हर मंगलवार को टास्क फोर्स की बैठक करें और हमने यह रिपोर्ट रखवाई और विभाग देखेगा, डी0एम0 साहब देखेंगे कि कहां क्या जरूरत है और जो सम्बन्धित विभाग होगा, वह कार्य सम्पन्न करेगा । इस तरह हमने किसान चौपाल लगाकर काफी किसानों को और उसके अलावा महोदय, हम लोगों ने करीब 97358 किसानों को जिलास्तरीय आत्मा के द्वारा, जो माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं महोदय कि देश के किसानों की आय दोगुनी हो और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि किसानों की खेती में लागत बहुत कम हो, तो हम लोगों ने 97358 किसानों को ट्रेनिंग करवाई थी महोदय और एक्सपोजर मीट भी करवाया कि दुनिया कैसे बदल रही है । हमारे अन्नदाता किसान भाई-बहन देख रहे हैं और महोदय, 46123 किसानों को परिभ्रमण भी कराया गया, कुल 1986 कार्यक्रम हुए हैं महोदय, 712 किसान पाठशाला खोली गई हैं फसल सुरक्षा का, एक बहुत बड़ा चैलेन्ज हमारे सामने है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम बदल रहा है महोदय और तरह-तरह की बीमारियां आ रही हैं जैसे- केला की खेती में पनामा नामक बीमारी आ गई है, मक्का की खेती में फॉलआर्मी बीमारी आ गई और किसान वैसे भी नीलगाय की बात कर रहे थे, बनेला सुअर की बात हो रही थी और लोग बता रहे थे और कीट-मकौड़ों से महोदय हमारा 20 से 25 प्रतिशत हमारे खाद्यान का नुकसान हो रहा है, फसल सुरक्षा के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसे करे, एक बार में तो सम्भव है नहीं, धीरे-धीरे रास्ता निकाल रहे हैं, अब कई लोगों ने कहा कि नीलगाय पर आप कार्रवाई कीजिए । उसपर क्या कार्रवाई करे, तो उसकी नसबन्दी करवा दीजिए, जा करके अब ये तो वन विभाग का काम है, वन विभाग के नियम कानून हम जान नहीं रहे हैं, इसके लिए हम वन विभाग से संपर्क करेंगे, अगर नीलगाय से वाकई में नुकसान हो रहा है, तो हम आग्रह करेंगे पर्यावरण एवं वन विभाग से मिल करके कि कोई रास्ता निकाले ताकि आने वाले समय में फसलों का नीलगाय से जो नुकसान हो रहा है उसका रास्ता निकलना चाहिए

महोदय । उसी तरह महोदय कुल मिलाकर किसान गोष्ठी महोदय, किसान विज्ञान केन्द्र हमारा सभी जिलों में खोले गये है और महोदय हमलोगों ने करीब 543 किसानों का गोष्ठी भी करवाया है और 36 किसान वार्तालाप का आयोजन दो महीना पहले किया है कि 'किसानों की बात-कृषि मंत्री के साथ' तो महोदय महीने में एक बार वीडियो कन्फ्रेंसिंग से डायरेक्ट बात करते हैं और बात-चीत के दौरान हम किसानों से जानकारी लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ कि क्या कमी है,क्या आपका सुझाव है, महोदय तीसरा बार मैं कर चुका हूँ, किसानो का लगातार सुझाव आ रहे हैं, किसानों को कृषि के संबंध में समसामयिक तकनीकि जानकारी विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए खेती बारी नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया है, किसानों के पास जा रहा है, महोदय, कृषि रोडमैप के अन्तर्गत नये प्रकार के कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए 2019-20 में 163.53 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है और महोदय, 81 प्रतिशत कृषि यंत्रों पर राज्य सरकार द्वारा 40 परसेंट से लेकर 80 परसेट अनुदान तक दिया जा रहा है और पहली बार महोदय अनुसूचित-जाति एवं अनुसूचित-जनजातीय भाइयों की तरह अति पिछड़ी जाति के भाइयों के लिए भी यह सुविधा प्रदान की गयी है । महोदय, बिहार राज्य कृषि निर्माताओं द्वारा भी जो राज्य में कृषि यंत्र निर्माता है, बड़े पैमाने पर यंत्रों का निर्माण होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी का निदेश था और हम लोगों ने इस प्रस्ताव को बढ़ाया । मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर सहमति दी कि जो कैबिनेट में हम लोगों ने पास करवाया है कि महोदय, बिहार में हमारे जो इन्डस्ट्री हैं, कल्चर आधारित इन्डस्ट्री जो हैं वे जो उत्पादन करेंगी उसमें 10 परसेंट का हम और अधिक उनको सुविधा देंगे, जिससे यहां के इन्डस्ट्री के जो लोग हैं उनको और अधिक सुविधा मिलेगी । भारत सरकार के द्वारा विधायी दिशा-निर्देश वित्तीय वर्ष 2019-20 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना नए स्वरूप में शुरू की जा रही है महोदय, इसके अन्तर्गत 2019-20 में राज्य के सभी जिलों के प्रत्येक प्रखण्ड के एक ग्राम के सभी फॉरफेडरिंग का मिट्टी नमूना लेकर जांचोपरान्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जा रहा है महोदय । महोदय, खेती के लिए मिट्टी बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने सॉयल हेल्थ कार्ड, जो मिट्टी में 16 पोषक तत्व पाए जाते हैं किसान भाइयों को पता नहीं रहता है कि कितनी आयरन की कमी है, कितना फास्फोरस नहीं है, कितना नाइट्रेट की कमी है, तो महोदय, हमारी सरकार सॉयल हेल्थ कार्ड दे रही है और किसानों को बता भी रहे हैं कि आप खेतों में जब खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सॉयल हेल्थ कार्ड के हिसाब से करेंगे, तो निश्चित तौर पर लागत कम होगी और धरती माता भी खुश रहेगी, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं ।

क्रमशः

टर्न-27/सत्येन्द्र-मुकुल/03-03-2020

क्रमशः

श्री प्रेम कुमार, मंत्रीः इस तरह से लगातार अभी तक महोदय भारत सरकार का जो कृषि विश्वविद्यालय, कृषि संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में महोदय बिहार कृषि महाविद्यालय, सबौर जो हमारा है, वह जो 24वें रैंक पर था महोदय, आज महोदय घटकर के 18वें रैंक पर आ गया है । बिहार कृषि विश्वविद्यालय के आई0सी0टी0 बेस्ड ई-एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन फॉर इनहान्स्ड टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन डिलीवरी परियोजना को भारत सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस के लिए महोदय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। वर्ष 1920-21 में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर महोदय जो अधिकारियों का हमारे यहां कमी थी, हमलोग अधिकारी की कमी झेल रहे थे, हमें खुशी है महोदय कि बिहार कृषि सेवा कोटि में 53, रसायन कोटि में 43, पौधा संरक्षण कोटि में 34 और उद्यान कोटि में 36 सहायक कृषि निदेशक की महोदय नियुक्ति हो गयी । इस प्रकार कुल मिलाकर 166 राजपत्रित पदाधिकारी की नियुक्ति की गयी है। आत्मा योजना अन्तर्गत 476 प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, 1,287 सहायक तकनीकी प्रबंधक, 388 लेखापाल/आशुलिपिक की नियुक्ति हेतु महोदय विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसके विरूद्ध 22 जिलों में महोदय इसकी नियुक्ति कर ली गयी है । बेरोजगार युवक एवं युवतियों को कृषि के क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कुल 4,852 व्यक्तियों को कृषि के 23 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ-साथ मछली पालन, गौ-पालन, बकरी-पालन, फार्मिंग वर्मी कम्पोस्ट, मशरूम का उत्पादन, बागवानी इन चीजों को हम बढ़ावा दे रहे हैं और 23 पाठ्यक्रमों में यहां के जो किसान भाई-बहन हैं, उनको हम महोदय प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि वर्ष 2020-21 को एक ओर केन्द्रीय बजट में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित कई कदम उठाये गये हैं, कृषि उद्यान, किसान रेल एवं सक्षम स्तर पर भंडारण की व्यवस्था, जिला स्तर पर फसल को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाई देने का काम किया जा रहा है। महोदय, केन्द्र के साथ कदम से कदम मिलाकर हमारी राज्य की सरकार माननीय मुख्यमंत्री की

अगुआई में राज्य की सरकार कृषि रोड मैप बनाकर के किसानों को कृषि के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। कृषि रोड मैप की परिकल्पना सपना सकार हो रही है। राज्य में कृषि के विकास में नये नये कीर्तिमान स्थापित हो रहा है इसलिए यहां के लोगों के बीच कृषि के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। महोदय,आई0आई0टी0,आई0आई0एम0 से पढ़े हुए युवक लाखों करोड़ों की नौकरियों छोड़कर कृषि कार्य में संलग्न हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय,कृषि रोड मैप से हमारे किसान भाईयों की तकदीर बदल गयी है। अध्यक्ष महोदय,भारत में पहली हरित क्रांति की शुरूआत पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में हुई और फसलों के उत्पादन में महोदय अधिक वृद्धि हुई परन्तु विकास की दौर पर प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का ध्यान नहीं रखा गया जिसका परिणाम आज हमारे सामने हैं । अंधाधूंध रासायनिक उर्वकों एवं कीटनाशक के व्यवहार से आज न केवल पंजाब की पूरी मिट्टी खराब हो गयी है बल्कि इस प्रक्रिया से ऊपजाई गयी प्रदूषित अनाज से कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही है इसलिए महोदय हमलोग पूरी तरह सचेष्ट है और हमारी सरकार टिकाऊ विकास के लिए प्रयासरत है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी जलवायु को सुरक्षित एवं संरक्षित रखते हुए विकास की ईमारत लिखी जा रही है और हमारे इस प्रयास में केन्द्र सरकार का भी भरपुर सहयोग मिल रहा है। खेतों के मिट्टी जांच कर आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों के उपयोग के लिए किसानों का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आज हमलोग जैविक खेती के साथ साथ पानी को बचाने में भी जुटे हुए हैं । महोदय, आपको पता होगा पानी के खपत का 90 प्रतिशत उपयोग सिंचाई में होता है इसलिए पानी बचाने की जिम्मेवारी कृषि विभाग की है । महोदय, जहां एक ओर फसलों के सिंचाई के लिए वर्षा जल का अधिक उपयोग करने हेतु हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, दूसरी जो कम पानी में अधिक फसल उत्पादन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर रहे हैं इसलिए ड्रीप तथा माइक्रो स्प्रिंक्लर जैसे कार्यक्रम में 90 प्रतिशत तक महोदय हमलोग अनुदान भी देने का काम कर रहे हैं। महोदय, कृषि के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है। जलवायु परिवर्तन का परिणाम हमलोग देख रहे हैं अनियमित मौसम, कभी बाढ़, कभी सूखाड़, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, ब्रजपात जैसे प्राकृतिक आपदाएं आये दिन देखने को मिल रही है, इससे कृषि के साथ साथ पूरा मानव जीवन एवं हमारा पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है, इससे हमारा फसल उत्पाद प्रभावित हो रहा है । महोदय, सरकार इस दिशा में भी गंभीर प्रयास कर रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल दिशा निर्देशन में जल जीवन हरियाली की योजना कार्यान्वयन की जा रही है, इसके लिए 24 हजार 524 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है इससे जलवायु अनुकूल खेती के लिए काम किये जा रहे हैं। महोदय, इन सभी

समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के द्वारा गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं। महोदय, मेरा मानना है कि कार्य तभी सफल हो पायेंगे जब व्यापक जन भागीदारी होगी और जन भागीदारी के लिए जागरूकता जरूरी है । महोदय, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुआई में बिहार में ऐतिहासिक मानव श्रृखंला का निर्माण किया गया था। स्कूल कॉलेज में इस पर बराबर चर्चा करायी जा रही है। कृषि विभाग द्वारा राज्य के सभी 8450 पंचायतों में किसान चौपाल लगाकर इसके लिए किसानों को जागरूक महोदय किया गया है। हमारी सरकार विकास के साथ साथ आने वाले पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ माहोल तैयार करने में लगी हुई है। महोदय, मौसम प्रतिकुल हो रहा है परन्तु सरकार इस प्रतिकुल मौसम में भी बेहतर से बेहतर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विपक्ष की जिद है जहां बिजली गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसियां बसाने की। महोदय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग महोदय जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धूरी है। किसानों की आमदनी बढ़ाने में फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, गौ-पालन, मत्स्य पालन की भी अहम भूमिका है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्वरोजगार के सृजन में भी इस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। अध्यक्ष महोदय, राज्य की लगभग 89 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से इस विभाग से जुड़ी हुई है । यह विभाग पशु पक्षी मत्स्यजन्य विभिन्न उत्पादों के द्वारा राज्य के जी0डी0पी0 में अह्म योगदान देकर राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का महोदय काम कर रहा है। केन्द्र एवं राज्य सरकार पशुपालन गब्य एवं मत्स्य प्रभाग के व्यापक विकास हेतु दृढ़संकल्पित है। यही कारण है महोदय कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पशु एवं मत्स्य के लिए अलग से मंत्रालय बनाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस प्रक्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील है। राज्य में स्वीकृत तृतीय कृषि रोड मैप के अन्तर्गत इस विभाग के तीनों प्रभागान्तर्गत अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं, कार्यक्रमों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु विभाग सतत प्रयत्नशील है ताकि राज्य दुग्ध, मांस, अंडा, मछली उत्पादन में वृद्धि कर आत्मनिर्भर हो सके। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज बिहार का दुग्ध बिहार में महोदय प्रतिदिन 19 से 20 लाख लीटर महोदय दुग्ध का उत्पादन हो रहा है और बिहार का दुग्ध नेपाल जा रहा है, दिल्ली महोदय जा रहा है । बिहार का दुग्ध महोदय बंगाल जा रहा है, बिहार का दुग्ध झारखंड जा रहा है और मछली में महोदय आज हमारा बिहार का मछली अब बिहार के बाहर जाना महोदय शुरू हो गया है और इस तरह से बिहार में बदलाव हो रहा है और बिहार बदल रहा है ।अब महोदय समय हो रहा है और महोदय जो हमारा विषय, बहुत सारा विषय है इसलिए हमारा आग्रह होगा सारा का सारा..

अध्यक्षः प्रेम बाबू, अगर बहुत सारा है तो सदन पटल पर रख सकते हैं।

श्री प्रेम कुमार,मंत्रीः जी जी, वही चाह रहे हैं महोदय, आपका जो आदेश महोदय है, आदेश का पालन होगा, सारा का सारा हम जमा कर देते हैं जो भाषण का पार्ट बन जायेगा।

अध्यक्षः लेकिन पद्य वाला कुछ बचा है तो वह बतला दीजिये।

(माननीय मंत्री का वक्तव्य-परिशिष्ट द्रष्टव्य)

श्री प्रेम कुमार,मंत्रीः और महोदय बस अंत कर रहे हैं । महोदय, अमीर खुसरों ने कहा था-

खुसरों पांती प्रेम की,बिरला बांचे कोय,
वेद पुराण पोथी पढ़े प्रेम बिना का होय।।

माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए

कठिन परिश्रम स्वभाव सरल हो,
करते रहते दिन रात काम तो कैसे न राज्यों का भला हो।।

माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है

नीतीश कुमार आपसे है जनजनप को आश,
जल जीवन हरियाली से बुझेगी धरती व जीवन की प्यास।।

और महोदय राज्य के किसान भाई बहनों के लिए

कृषक न होते तो अन्न न होते,
अन्न न होते तो हम सब जीवित न होते,
शायद भगवान भी भूखे सोते।

इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया का सहयोग हैख

हे लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ,सजग कराते रहते हर एक को हरदम,
तेरे खबरों से ही होता है दिन का शुभारंभ ,
तेरा हो अभिनंदन तेरा हो अभिनंदन।।

कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करते हैं।

योजनाओं को धरा पर उतारता चला,
राज्य के कृषकों को हो रहा भला।।

अब माननीय अध्यक्ष जी लिए अंत में हम कहना चाहेंगे

शांति से सदन चलता, कुशल अध्यक्ष जी के नाम,
राज्य की जनता का सदन में सत्त होता रहता काम।।

अंत में विपक्ष चले गये महोदय, कहना चाहते हैं महोदय

वक्त है कम, लगा दो जितना हो दम,
कुछ को मैं जगाता हूँ ,कुछ को तुम जगा दो।।

अध्यक्षः वाह ! गद्यांश ही ज्यादा था और ये पथ निर्माण मंत्री जी के लिए चुनौती है।

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अंत में हम अपने साथी ललित यादव जी से आग्रह करेंगे कि जो कटौती के प्रस्ताव उन्होंने पेश किया है और उसको मतलब जाकर के वापस लें और सर्वसम्मति से हमारा बजट महोदय पास किया जाय।

टर्न-28/मधुप-हेमंत/03.03.2020

अध्यक्ष : सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मॉग 10 रूपये से घटाई जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''कृषि विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 31,52,81,42,000/- (इकत्तीस अरब बावन करोड़ इक्यासी लाख बयालीस हजार) रूपये अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मॉग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक- 03 मार्च, 2020 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 25 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक- 04 मार्च, 2020 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

कृषि विभाग

का

बजट 2020–21

डॉ० प्रेम कुमार

माननीय कृषि मंत्री, बिहार

का

वक्तव्य

वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट उपस्थापन के समय माननीय मंत्री कृषि का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

सर्वप्रथम मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के प्रति करोड़ों किसानों की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि देश में पहली बार **सशक्त नेतृत्व–सबल किसान** का सपना चरितार्थ हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपके कुशल निर्देशन में कृषि रोड मैप के माध्यम से राज्य के किसान उतरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। कृषि रोड मैप कार्याक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप वर्ष 2011–12 में चावल, वर्ष 2012–13 में गेंहूँ, वर्ष 2015–16 में मोटे अनाज (मक्का), वर्ष 2016–17 में मोटे अनाज (मक्का) तथा वर्ष 2017–18 में गेहूँ के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को कुल पाँच कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय,

आजादी के बाद पूर्ववर्त्ती सरकारों द्वारा कृषि एवं किसानों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं किये जाने के कारण किसानों के हालात में जितना सुधार होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया। महोदय किसानों के समक्ष आज भी कई चुनौतियाँ हैं जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है। महोदय इस अवसर पर मैं महान कवि दुष्यंत जी की एक पंक्ति उद्धृत करना चाहूंगा।

यह पीर हुई पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए ।
इस हिमालय से अब, कोई गंगा निकलनी चाहिए।।

महोदय,

जब से बिहार में एन0डी0ए0 की सरकार एवं केन्द्र में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई है किसानों के लिए ऐतिहासिक कार्य हो रहें है।

अध्यक्ष महोदय,

वर्ष 2020–21 के केन्द्रीय बजट में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित कई कदम उठाये गये हैं। कृषि उड़ान, किसान रेल एवं सूक्ष्म स्तर पर भंडारण की व्यवस्था, जिला स्तर पर विशेष फसल को बढ़ावा देने जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र को एक नयी ऊँचाई देने का काम किया गया है।

अध्यक्ष महोदय,

केन्द्र के साथ कदम से कदम मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार कृषि रोड मैप बनाकर किसानों एवं कृषि के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। कृषि रोड मैप की परिकल्पना अब साकार हो रही है। राज्य में कृषि के विकास में नये नये कृतिमान स्थापित हो रहे है। राज्य के युवाओं एवं बुद्धिजीवियों का कृषि के प्रति आर्कषण बढ़ रहा हैं। अब आई0आई0टी0, आई0आई0एम0 से पढ़े हुए नवयुवक लाखों की नौकरियाँ छोड़कर कृषि कार्य में संलग्न हो रहे है। बड़ी–बड़ी कम्पनियाँ अब कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए आगे आ रही है।

अध्यक्ष महोदय,

कृषि रोड मैप की योजनाओं एवं हमारे अन्नदाता किसान भाई/बहनों की कड़ी मेहनत के बदौलत राज्य में फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। परन्तु हम उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने की प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति भी सचेत हैं महोदय।

अध्यक्ष महोदय,

भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरूआत पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में हुई। वहां फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि तो हुई परन्तु विकास की इस दौड़ में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का ध्यान नहीं रखा गया। जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। अंधाधुंध रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के व्यवहार से आज न केवल पंजाब की पूरी मिट्टी खराब हो गयी है। बल्कि इस प्रक्रिया से उपजायी गई प्रदूषित फसल उत्पादों के सेवन से उन राज्यों में कई गंभीर बिमारियां उत्पन्न हो रही है। इसलिए महोदय हमलोग पूरी तरह सचेत हैं। हमारी सरकार टिकाउ विकास के लिए प्रयासरत है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी, जल तथा वायु को सुरक्षित एवं संरक्षित रखते हुए विकास की इवारत लिखी जा रही है, और हमारे इस प्रयास में केन्द्र सरकार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। खेतों की मिट्टी की जाँच कर आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों के उपयोग के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। हमलोग जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। जैविक खेती के साथ–साथ हम पानी को भी बचाने में जुटे हैं। महोदय आपको पता होगा कि कुल पानी की खपत का 90 प्रतिशत पानी का उपयोग फसलों की सिंचाई में होता है। इसलिए पानी बचाने की बड़ी जिम्मेवारी कृषि विभाग की भी है। इसलिए जहां हम एक ओर फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा जल के अधिक से अधिक उपयोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर कम पानी में अधिक फसल उत्पादन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए ड्रीप एवं स्प्रीकंलर सिंचाई पर 90 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। प्रत्यके खेत में वर्षा जल संचय हेतु संरचना निर्माण के लिए किसानों को अनुदान दिया जा रहा है ताकि वर्षा जल से ही फसलों की सिंचाई हो सके एवं भूगर्भीय जल को संरक्षित किया जा सके।

महोदय, आज कृषि के समक्ष जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है जलवायु परिवर्तन का परिणाम हमसब देख ही रहे हैं। अनियमित मॉनसून, कभी बाढ़, कभी सुखाड़, ओला वृष्टि, अति वृष्टि, बज्रपात जैसी प्राकृतिक आपदाएँ आये दिन देखने को मिल रही है। इससे कृषि के साथ–साथ पूरा मानव जीवन एवं हमारा पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। हमारा फसल उत्पादन प्रभावित हो रहा है महोदय। सरकार इस दिशा में भी गंभीर प्रयास कर रही है। भविष्यद्रष्टा माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल दिशा निर्देशन में जल जीवन हरियाली की योजना कार्यान्वित की जा रही है इसके लिए 24524 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। इसी तरह जलवायु अनुकूल खेती के लिए भी कार्य किये जा रहे हैं।

महोदय इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा गंभीर प्रयास किये जा रहे है परन्तु महोदय मेरा मानना है कि यह कार्य तभी सफल हो पायेगे जब इसमें व्यापक जनभागीदारी होगी। व्यापक जनभागीदारी के लिए जागरूकता जरूरी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में ऐतिहासिक मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया है। स्कूल कॉलेजों में इसपर निरन्तर चर्चा करायी जा रही है। कृषि विभाग द्वारा राज्य के सभी 8,405 पंचायतों में किसान चौपाल लगाकर इसके लिए किसानों को जागरूक किया गया है। तो महोदय हमारी सरकार विकास के साथ–साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित एवं अनुकूल माहौल तैयार करने में लगी हुई है। महोदय मौसम प्रतिकूल हो रहा है, परन्तु सरकार इस प्रतिकूल मौसम में भी बेहतर से बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की ।

मुझे भी जिद है वहीं आशियां बसाने की ।।

अध्यक्ष महोदय,

अपने बजट भाषण के प्रारंभ में मैं अपनी विभाग की आगामी कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी आपके माध्यम से सदन को संक्षेप में देना चाहूंगा। इसके बाद विस्तार से हरेक विषय पर चर्चा करूंगा।

- किसानों को बीज से लेकर बाजार तक हर जरुरी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी।
- राज्य में रैयत के साथ–साथ गैर रैयत किसानों अर्थात बटाईदारों को भी विभागीय योजनाओं का लाभ दिया जायेगा।
- नये एवं अधिक आमदनी देने वाले नगदी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जायेगा – स्ट्रॉवेरी, ड्रैगन फ्रूट, शहजन आदि की खेती को बढ़ावा दिया जायेगा।
- बिहार के कृषि उत्पादों को देश से बाहर निर्यात हेतु आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक्सपोर्ट पैक हाउस की स्थापना की जायेगी।
- नील गायों से फसलों की क्षति से बचाने हेतु व्यापक कार्य योजना बनाई जायेगी।
- उद्यानिक उत्पादों यथा फल, सब्जी आदि के ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, ब्राण्डींग एवं मार्केटिग के लिए छोटे–छोटे उद्योग की स्थापना हेतु 90 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। इसके लिए 10 लाख रूपये तक के लागत वाली ईकाई के लिए 9 लाख रूपया सरकार द्वारा अनुदान दिया जायेगा।
- किसानों को फल–सब्जी आदि तोडने के उपरान्त खेतों से मंडियों तक या रेलवे स्टेशनों/एयरपोर्ट तक पहुँचाने हेतु रेफ्रिजरेटेड वैन/शीतलीकृत वाहन उपलब्ध कराया जायेगा ताकि परिवहन के दौरान उनकी गुणवत्ता बनी रहे।

- फल/सब्जियों के सुरक्षित भंडारण हेतु गांवों में सोलर कूल चैम्बर यानि मिनी कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।
- शहरों में घरो के छतों पर सब्जी उत्पादन हेतु रूफ टॉप गार्डेनिंग की योजना को विस्तार दिया जायेगा।
- इस वर्ष से सभी किसानों को कृषि फिडर के माध्यम से सिंचाई एवं अन्य कृषि कार्य हेतु सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध करायी जायेगी।
- किसानों के उत्पाद को सही समय पर उचित मूल्य दिलाने हेतु राज्य में अवस्थित कृषि उत्पादन बाजार समितियों का जीर्णोद्वार किया जायेगा। बाजार प्रांगणों में बिजली, पानी, शौचालय, सफाई, सुरक्षा, सडक, चाहरदिवारी आदि का निर्माण कराया जायेगा। बाजार मूल्य की जानकारी देने हेतु डिजिटल रेट डिस्प्ले बोर्ड लगाया जायेगा तथा ऐप के माध्यम से किसानों को बाजार मूल्य की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।
- फलों एवं सब्जियों के बेहतर मार्केटिंग हेतु कॉम्फेड की तर्ज पर फेडरेशन बनाया जायेगा।
- कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य की योजनाओं में अतिपिछड़ों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान अनुदान दिया जायेगा।
- राज्य में तैयार होने वाले कृषि यंत्रों पर 10 प्रतिशत अधिक अनुदान दिया जायेगा।
- समुहिक खेती को बढ़ावा देने हेतु पंचायत स्तर पर FIG/FSG एवं प्रखंड स्तर पर FPO बनाया जायेगा तथा इसके लिए किसानों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। विभाग की सभी योजनाओं में FPO को प्राथमिकता दी जायेगी।

- बीज अनाज एवं प्याज के भंडारण हेतु छोटे–छोटे गोदामों के निर्माण हेतु अनुदान दिया जायेगा।
- टाल क्षेत्रों की कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान किया जायेगा तथा टाल क्षेत्रों को दलहनी बीज उत्पादन के हब के रूप में विकसित किया जायेगा।
- राज्य को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। इसके लिए शीघ्र ही राज्य में बीज उत्पादन पॉलिसी बनाई जायेगी।
- राज्य के कुछ महत्वपूर्ण एवं विशेष फसलों जैसे कतरनी धान, जर्दालु आम, मगही पान, शाही लीची को संरक्षित एवं विकसित करते हुए इसका क्षेत्र विस्तार किया जायेगा।
- राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार में बिहार को प्राप्त 4 करोड़ की राशि से पटना में किसानों को ठहरने के लिए गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जायेगा। जो किसान कृषि कार्य से राजधानी आयेंगे उनके ठहरने एवं खाने की व्यवस्था रहेगी।
- अभी तक राजनेता एवं अधिकारी विदेश भ्रमण पर जाते थे। लेकिन अब कृषि की आधुनीक तकनीक को देखने समझने के लिए किसानों को सरकारी खर्चे पर विदेश भेजा जायेगा।
- राज्य में पाँच नये कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी।
- जैविक खेती को को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के किसानों का जैविक प्रमाणीकरण कार्य निःशुल्क किया जायेगा।

- राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शोध को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिभा सम्मान योजना की शुरूआत की जायेगी, जिसमें विश्वविद्यालय के द्वारा पेंटेंट कराये जाने, प्रभेद विकसित करने आदि प्रमुख उपलब्धियों के लिए विश्वविद्यालय को अनुसंधान प्रोत्साहन ग्रान्ट दिया जायेगा। इसके साथ ही कृषि छात्रों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर प्रतिभा को सम्मानित करने के उद्देश्य से छात्रों को प्रतिभा स्टाइपेंड योजना की शुरूआत की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय,

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दोनों किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृतसंकल्पित है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए विभाग कई स्तरों पर कार्य कर रहा है। हम किसानों की खेती का लागत मूल्य को कम करने का प्रयास कर रहे है, इसके लिए मिट्टी जाँच के आधार पर उर्वरकों का संतुलित उपयोग, बीजोपचार, कम पानी से खेती, आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है। वही दूसरी ओर कीट व्याधि से फसलों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए भी व्यापक कार्य योजना बनायी जा रही है।

महोदय,

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक वर्ष कुल फसल उत्पादन का लगभग 10 से 15 प्रतिशत कीट व्याधियों के कारण नुकसान हो जाता है, जिससे किसानों की आमदनी पर प्रभाव पड़ता है। तो महोदय, हम इसके लिए भी प्रयासरत है। किसानों को हम आधुनिक तरीके से खेती के प्रबंधन का प्रशिक्षण भी दे रहे है।

अध्यक्ष महोदय,

कृषि रोड मैप के तहत कृषि विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किसानों के ऑनलाईन पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है। कृषि विभाग के वेबसाईट पर **1.24 करोड़ किसान पंजीकृत** हो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय,

ऑनलाईन किसानों के पंजीकरण के बाद कृषि विभाग के द्वारा कृषि योजनाओं में अनुदान की राशि किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे भेजी जा रही है। वर्ष 2019–20 में खरीफ 2019 में वर्षापात की कमी के कारण 5 लाख हेक्टेयर में धान की खेती नहीं हो सकी। राज्य के कुछ जिलों में बाढ़ से फसल क्षति हुई। सितम्बर माह में अत्यधिक वर्षापात से फसल प्रभावित हुआ। प्राकृतिक आपदा की इन परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा किसानों की सहायता के लिए सिंचाई के लिए डीजल पर अनुदान की राशि 50 रू० प्रति लीटर से बढ़ाकर 60 रू० प्रति लीटर किया गया। वर्ष 2019–20 में 01 अप्रैल 2019 से अबतक 6.41 लाख किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मद में 88.45 करोड़ रू० भुगतान किया गया है। किसानों को आकस्मिक फसल का बीज मुफ्त उपलब्ध कराया गया। आपदा से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए फसल इनपुट अनुदान दिया जा रहा है। आपदा से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए कृषि इनपुट अनुदान मद में 12.52 लाख किसानों को 556 करोड़ रू० आधार से जुड़े बैंक खाते में भुगतान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय,

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के 56 लाख किसानों के बैंक खाते में 2745.82 करोड़ रू० भेजे गये हैं।

अध्यक्ष महोदय,

आधुनिक खेती का आधार बीज है। राज्य के किसानों को अधिक उपजशील प्रभेद के प्रमाणित बीज आसानी से उपलब्ध हो सकें इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये हैं। वर्ष 2019–20 में पहली बार किसानों से बीज की मांग से लेकर बीज की आपूर्ति तक की ऑनलाईन व्यवस्था की शुरूआत रबी 2019–20 से की गयी है। इसके तहत किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार बीज की ऑनलाईन मांग करते हैं। जिला कृषि पदाधिकारी बीज विक्रेता को ऑनलाईन बीज का आवंटन करते हैं। बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा आपूर्ति आदेश ऑनलाईन दिये जा रहे हैं तथा ओ0टी0पी0 के माध्यम से किसानों को बीज की आपूर्ति अनुदानित दर पर सुनिश्चित की जा रही है। रबी 2019–20 में 648184 किसानों को 303699 क्विंटल गुणवत्ता वाले बीज इस व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराये गये हैं। इस वर्ष किसानों के घर पर भी बीज की आपूर्ति की होम डिलिवरी व्यवस्था की शुरूआत बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा की गयी है। इसके तहत इस रबी मौसम में बांका जिला में सफलतापूर्वक बीज की आपूर्ति की गयी है। गर्मा मौसम से इसे विस्तारित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा बीज अनुदान की राशि बिहार राज्य बीज निगम को उपलब्ध करायी जा रही है। इस नयी व्यवस्था के फलस्वरूप राज्य के किसानों को काफी कम मूल्य पर उन्नत बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाया है।

वर्ष 2020–21 में बीज उत्पादन से लेकर किसानों को सुगमतापूर्वक बीज आपूर्ति की सम्पूर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा। बीज अनुदान के प्रशासन में टेक्नोलॉजी के प्रयोग से पारदर्शिता एवं जबाबदेही लायी जायेगी। कृषि प्रक्षेत्रों पर गुणवत्ता वाले बीज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जायेगा। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, बीज ग्राम

योजना, बीज उत्पादन एवं प्रसंस्करण संबंधित आधारभूत संरचना के विकास, अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराने की योजना एवं नेशनल मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल के कार्यान्वयन पर विशेष बल दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय,

बिहार प्रमुख फल एवं सब्जी उत्पादक राज्य है। पूरे देश में सब्जी उत्पादन में हम तीसरे एवं फल के उत्पादन में छठे स्थान पर हैं। राज्य में बागवानी के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित मिशन ऑन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के साथ–साथ मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना तथा बागवानी पर आधारित राज्य योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं। इसके साथ ही बिहार राज्य उद्यानिक उत्पाद विकास योजना, घरों के छत पर बागवानी विकास की योजना, पुराने पॉली हाउस का जीर्णोद्धार योजना, सब्जी/मशाला उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु तकनीकी हस्तक्षेप, शेडनेट के अन्दर पान की खेती, मखाना विकास योजना, सहजन की खेती को विस्तार देने की योजना के तहत किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा तकनीकी को अपनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। बागवानी फसलों के क्लस्टर विकसित किये जा रहे हैं। वर्ष 2019–20 में 23 जिलों के लिए 14 बागवानी फसल चिन्हित किये गये हैं तथा इन जिलों में फसल विशेष के विकास के लिए बिहार विशेष उद्यानिक फसल योजना शुरू की गयी है। हम किसानों को फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी में संगठित कर रहे हैं। फार्मर प्रोड्यूसर संगठन को उत्पादन के पश्चात उपज के उचित रख–रखाव, मूल्य संवर्धन, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग तथा प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए आधारभूत संरचना निर्माण हेतु 90 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। 10 लाख की योजना में मात्र 1 लाख किसानों लगाना होगा शेष 9 लाख रूपया सरकार अनुदान के रूप में देगी।

बागवानी विकास योजनाओं के तहत वर्ष 2019–20 में 585 हेक्टेयर में आम, 24 हेक्टेयर में अमरूद, 98 हेक्टेयर में लीची, 1383 हेक्टेयर में टिशू कल्चर केला, 91 हेक्टेयर में पपीता, 11 हेक्टेयर में स्ट्रॉबेरी के नये बागान की स्थापना के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गयी है। बागवानी विकास योजनाओं में इस वर्ष 70 हजार मधुमक्खी बक्से किसानों को दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार किसानों को अनुदान दे रही है। राज्य में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 40 हजार वर्गमीटर में शेडनेट तथा 40 हजार वर्गमीटर में पॉली हाउस की स्थापना की जा रही है। राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस वर्ष 150 हेक्टेयर में मखाना की खेती के लिए किसानों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। ताजे फल एवं सब्जियों को इच्छित तापमान पर संरक्षित रखने हेतु सौर ऊर्जा से संचालित नयी तकनीकी युक्त पोर्टेबुल सोलर कोल्ड रूम की योजना ली गई है जिसकी इकाई लागत 13.00 लाख रूपये का 50 प्रतिशत अनुदान दी जा रही है। ड्रिप तथा स्प्रींक्लर सिंचाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ड्रिप सिंचाई पर 90 प्रतिशत तथा स्प्रींक्लर सिंचाई पर 75 प्रतिशत अनुदान किसानों को उपलब्ध करा रही है।

वर्ष 2020–21 में उद्यानिकी फसलों के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अतिरिक्त राज्य योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। किसानों को नये बागानों की स्थापना के लिए आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। क्लस्टर के आधार पर बागवानी फसलों के विकास पर बल दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय

मौसम बदल रहा है। बदलते मौसम के साथ खेती को बदलने की भी जरूरत हो गयी है। कृषि विभाग मौसम के अनुकूल कृषि कार्य के लिए किसानों को हरसंभव तकनीकी उपलब्ध करा रही है। जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत कृषि विभाग के द्वारा **मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम** की शुरूआत की गयी है। इस कार्यक्रम के प्रथम फेज में आठ जिलों के 40 गाँवों को सीधे कृषि वैज्ञानिकों के देख–रेख में मॉडल मौसम अनुकूल कृषि गाँव के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह योजना गया, नवादा, नालंदा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया एवं मधुबनी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का कार्यान्वयन डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, बॉरलौग इन्सटीच्यूट ऑफ साउथ एशिया, पूसा एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पूर्वी क्षेत्र, पटना के द्वारा किया जा रहा है।

मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के महत्व को देखते हुये वर्ष 2020–21 के बजट में इस कार्यक्रम का विस्तार सभी जिलों में करने के लिए राशि का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय

जल–जीवन–हरियाली अभियान के अधीन सिंचाई जल के संरक्षण तथा अधिकाधिक उपयोग के उद्देश्य से बूँद–बूँद सिंचाई (ड्रीप सिंचाई) को बढ़ावा देने के लिए ड्रीप सिंचाई की स्थापना के लिए राज्य सरकार 90 प्रतिशत अनुदान दे रही है। **वर्ष 2020–21 में सूक्ष्म सिंचाई योजना के अधीन ड्रीप तथा माइक्रो स्प्रिंक्लर से सिंचाई के लिए गहन कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।**

अध्यक्ष महोदय

राज्य सरकार गंगा नदी की स्वच्छता एवं अविरलता के प्रति पूर्ण रूप से संकल्पित है। गंगा नदी के किनारे के जिलों को मिलाकर एक जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जैविक कॉरिडोर में शामिल किसानों को जैविक खेती के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। राज्य सरकार जैविक खेती को अपनाने के लिए किसानों को 11500 रू० प्रति एकड़ अग्रिम अनुदान देगी। राज्य के 13 जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर की स्थापना के लिए 155 करोड़ रू० स्वीकृत किया गया हैं। भारत सरकार के द्वारा बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी को जैविक प्रमाणीकरण संस्था के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी के द्वारा राज्य के किसानों का जैविक प्रमाणीकरण का कार्य निःशुल्क किया जायेगा।

वर्ष 2020–21 में 21000 एकड़ में जैविक प्रमाणीकरण का कार्य किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय

विगत वर्षों में फसल अवशेष को जलाने से पर्यावरण का प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। फसल अवशेष के प्रबंधन के ज्वलंत विषय पर राज्य सरकार के द्वारा 14–15 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। विद्यालय स्तर पर छात्रों को कृषि एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। विद्यालय के छात्रों को फसल अवशेष नहीं जलाने का संकल्प दिलाया गया। रेडियो जिंगल तथा कृषि प्रसार रथ के माध्यम से कृषि एवं पर्यावरण से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी का ग्राम स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। फसल अवशेष प्रबंधन हेतु किसानों की सहायता के लिए इससे जुड़े कृषि मशीन पर किसानों को 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशरूम पालन से लेकर पशुपालन तक विभिन्न विकल्पों पर सरकार विचार कर रही है।

वर्ष 2020–21 में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को उपयुक्त प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा ताकि किसान इन यंत्रों को सुविधा से अपना सकें।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य सरकार जल एवं मिट्टी के संरक्षण के लिए दृढ़संकल्पित है। वर्ष 2019–20 में मिट्टी एवं जल संरक्षण की राज्य योजना के तहत 2350 जल संचयन संरचना का निर्माण, गाद की सफाई आदि का कार्य किया गया एवं 485 हे0 में पौधा रोपण कार्य किया गया एवं 2916.21 हे० में सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। पूर्वोत्तर भारत के लिए हरित क्रांति योजना अन्तर्गत कुल 680 सामुदायिक सिंचाई कूप, निजी बोरवेल एवं सामुदायिक बोरवेल की स्थापना की गयी है एवं 2347.50 हे० में अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था की गयी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रतिबूँद अधिक फसल (अन्य अन्तःक्षेप) अंतर्गत 306.05 हे० क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम उक्त अवधि तक 507 जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया। इस योजना के अंतर्गत 2369.51 हे० क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्वि की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में जलछाजन विकास योजनान्तर्गत 979 विभिन्न आकार के भूमि एवं जल संरक्षण से संबंधित संरचना का निर्माण/जीर्णोद्वार किया जायेगा, तथा 38974 हेक्टेयर में पौधा रोपण का कार्य किया जायेगा। राज्य योजना 2020–21 हेतु कुल 4249 भूमि एवं जल संरक्षण का निर्माण/जीर्णोद्वार तथा 997.44 हेक्टेयर में पौधा रोपण का कार्य किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय,

आधुनिक कृषि तकनीक के प्रचार–प्रसार के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। राज्य के 534 प्रखंडों में से 447 प्रखंड में ई–किसान भवन की स्थापना की गयी है। पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय स्थापित किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में सभी पंचायत स्तर पर रबी तथा खरीफ मौसम में किसान चौपाल लगाये गये। जिला स्तरीय आत्मा के द्वारा 97358 किसानों का प्रशिक्षण, 46123 किसानों को परिभ्रमण तथा 1986 प्रत्यक्षण, 712 किसान पाठशाला, 543 किसान गोष्ठी, 36 किसान वैज्ञानिक वार्तालाप का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय आत्मा के द्वारा 350 कृषक उत्पादक संगठन, 1382 कृषक हितकारी समूह का गठन किया गया।

किसानों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम की शुरूआत इस वर्ष से की गयी है जिसके तहत गेंहूँ, आलू, गोपालन एवं मत्स्यपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को प्रखंड स्तर पर किसान श्री, जिला स्तर पर किसान गौरव एवं राज्य स्तर पर किसान श्रेष्ठ पुरस्कार देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है।

उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी विक्रेताओं को कृषि तकनीकी जानकारी में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से देशी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कृषि विभाग के द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों के सक्रिय सहयोग से कौशल विकास मिशन के तहत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके तहत इस वर्ष 840 युवक/युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है।

वर्ष 2020–21 में कृषि रोड मैप के तहत किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए किसान पाठशाला, किसान चौपाल, किसान परिभ्रमण तथा किसान प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय,

कृषि रोड मैप के अंतर्गत नये प्रकार के कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019–20 में 163.513 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी। 81 प्रकार के कृषि यंत्रों पर राज्य सरकार किसानों को 40 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है। इस योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े कृषि यंत्रों को प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है तथा हैप्पी सीडर, स्ट्रा बेलर, रोटरी मल्चर, स्ट्रा रीपर, सुपर सीडर एवं स्ट्रॉ मैनेजमेन्ट सिस्टम पर सामान्य श्रेणी के किसानों को 75 प्रतिशत तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 1.48 लाख से अधिक किसानों से नये यंत्र के लिए आवेदन प्राप्त हुये हैं। कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर से लेकर अनुमण्डल स्तर तक कृषि मेला का आयोजन किया जा रहा है।

राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं को गुणवत्तायुक्त आधुनिक कृषि यंत्रों के निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने तथा कृषि यंत्र निर्माण के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित कृषि यंत्रों पर किसानों को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान का प्रावधान किया गया है। राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित कृषि यंत्रों के परीक्षण में लगने वाले शुल्क की शत–प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान किया गया है।

राज्य योजना के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा संचालित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजना के माध्यम से कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 10.00 लाख, 25.00 लाख एवं 40.00 लाख तक की लागत से कस्टम हायरिंग हेतु कृषि यंत्र बैंक तथा 80.00 लाख रूपये की लागत वाले दो हाईटेक हब की स्थापना का लक्ष्य है। उक्त सभी कृषि यंत्र बैंक/हाईटेक हब की स्थापना पर 40 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। इसके अलावा चयनित ग्रामों में 10.00 लाख रूपये तक की लागत से कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना की जानी है, जिसमें 80 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। इस योजना में जीविका समूह को शामिल किया गया है, जिसके फलस्वरूप राज्य में अबतक कुल 106 कृषि यंत्र बैंको की स्थापना की जा चुकी है।

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजना अन्तर्गत ही भारत सरकार द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में कृषि कल्याण अभियान फेज–II के तहत् बिहार में चयनित 13 आकांक्षी जिलों यथा–अररिया, औरंगाबाद, बाँका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णियाँ, शेखपुरा एवं सीतामढ़ी के चयनित 25–25 आकांक्षी ग्रामों के प्रत्येक ग्राम में 10–20 कृषि यंत्रों/उपकरणों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने हेतु 916.65 लाख रू0 की लागत से योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य योजना के अतिरिक्त सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजना के कार्यान्वयन पर विशेष बल दिया जायेगा। कृषि यांत्रिकरण योजना के माध्यम से फसल अवशेष के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय,

कृषि रोड मैप के तहत सतत एवं टिकाऊ खेती हेतु राज्य के 38 जिलों में जिलास्तरीय मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओं एवं प्रत्येक प्रमंडल में एक–एक अर्थात कुल 09 चलंत मिट्टी जाँच प्रयोगशाला के अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र के स्तर पर मिट्टी जाँच प्रयोगशाला कार्यरत हैं। इन राजकीय मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओं में किसानों के खेत से संग्रहित मिट्टी के नमूनों की निःशुल्क जाँच की जा रही है तथा मिट्टी जाँच के आधार पर कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना वर्ष 2015 से चलायी जा रही है। प्रथम चक्र (अप्रैल 2015 से मार्च 2017) के लक्ष्य 13,08,778 के विरूद्ध शत प्रतिशत मिट्टी नमूना संकलन एवं विश्लेषण किया गया एवं कुल 66 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उपलब्ध कराया गया है। द्वितीय चक्र वर्ष 2017–19 में 13,08,778 नमूना संग्रहण एवं विश्लेषण का लक्ष्य है। लक्ष्य के विरूद्ध कुल 11,50,356 नमूनों का संग्रहण एवं विश्लेषण किया जा चुका है तथा कुल 60,27,738 मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को वितरित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2019–20 से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का क्रियान्वयन नये स्वरूप में किया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य के सभी जिलों के प्रत्येक प्रखंड के एक ग्राम के सभी फार्म होल्डिंग का मिट्टी नमूना संग्रह कर जाँचोपरान्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष कुल 1,60,477 नमूना संग्रहण एवं विश्लेषण का लक्ष्य है। लक्ष्य के विरूद्ध कुल 1,05,000 नमूनों का संग्रहण एवं 73,100 नमूनों का विश्लेषण किया जा चुका है तथा कुल 45,697 मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के बीच वितरित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त ग्राम स्तरीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला परियोजना भी चलायी जा रही है। इस योजना अंतर्गत चयनित गाँवों में कुल 28 ग्राम स्तरीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला परियोजना की

स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत 5 लाख की लागत पर ग्राम स्तर पर स्वरोजगार के उद्देश्य से ग्राम स्तरीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला (मिनी लैब) की स्थापना की जानी है जिसमें व्यक्तिगत श्रेणी के लाभार्थियों को लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 3.75 लाख का अनुदान का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य के सभी जिलों के प्रत्येक प्रखंड के पाँच ग्राम के सभी फार्म होल्डिंग का मिट्टी नमूना संग्रह कर जाँचोपरान्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जायेगा तथा मिट्टी नमूनों की जाँच के आधार पर स्वायल हेल्थ कार्ड निर्गत किये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय,

कृषि रोड मैप के अधीन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। कृषि रोड मैप कार्यक्रमों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार कृषि विश्वविद्यालय को 18वाँ स्थान प्राप्त हुआ। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के *"आई.सी.टी. बेस्ड ई–एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन फॉर इनहान्स्ड टेक्नोलॉजी एण्ड इन्फॉर्मेशन डिलिवरी "* परियोजना को भारत सरकार द्वारा ई–गवर्नेन्स के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इस वर्ष पहली बार आई.आई.टी., कानपुर एवं कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, कनाडा के सहयोग से मैसीव ओपन ऑनलाईन कोर्स (एम.ओ.ओ.सी.) प्रारंभ किया गया जिसमें 2000 से अधिक विद्यार्थी विशिष्ट योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए। विश्वविद्यालय पुस्तकालय में ई–पुस्तकालय तथा डिजीटल पुस्तकालय की स्थापना की गयी है। विश्वविद्यालय द्वारा तीसी फसल के लिए सबौर तीसी–2, चना फसल के लिए सबौर चना–2 तथा बैंगन फसल के लिए सबौर–सदाबहार प्रभेद विकसित किया गया। धान फसल की

सीधी बुआई में खरपतवार प्रबंधन, गेहूँ फसल में पोटैशियम नाइट्रेट के छिड़काव द्वारा अवसान ताप (टर्मिनल हीट) तनाव को कम करने, रबी मक्का में उच्च उर्वरता एवं पौधा घनत्व से उत्पादकता में वृद्धि, धान फसल के खेत की मिट्टी में आर्सेनिक प्रदूषण के प्रबंधन हेतु स्यूडोमोनास कुल के जीवाणु की पहचान, प्याज फसल में खर–पतवार प्रबंधन तथा धान को सुखाने के यंत्र जैसे अत्याधुनिक कृषि तकनीक का विकास किया गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा उद्यमिता विकास के उद्देश्य से इन्क्यूवेशन सेंटर की स्थापना की गयी। कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों के गाँवों में जाकर 'कृषि वैज्ञानिक किसानों के द्वार' कार्यक्रम के तहत किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आधुनिक कृषि तकनीक के त्वरित प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से सबौर में एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की शुरूआत की गयी।

वर्ष 2020–21 में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में रोग एवं व्याधि से सहिष्णु, विपरित मौसमी परिस्थितियों से सहिष्णु फसल प्रभेदों के विकास पर बल दिया जायेगा। बायोफोर्टिफाइड चावल प्रभेद के विकास के लिए अनुसंधान के कार्य किये जायेंगे।

कृषि रोड मैप के अधीन वर्ष 2020–21 में राज्य में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को गति प्रदान करने के लिए कृषि अभियंत्रण/कृषि व्यवसाय प्रबंधन/जैव प्रौद्योगिकी/फूड टेक्नोलॉजी/सामाजिक विज्ञान के नये महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी। साथ ही राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शोध को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिभा सम्मान योजना की शुरूआत की जायेगी, जिसमें विश्वविद्यालय के द्वारा पेंटेंट कराये जाने, प्रभेद विकसित करने आदि प्रमुख उपलब्धियों के लिए विश्वविद्यालय को अनुसंधान प्रोत्साहन ग्रान्ट दिया जायेगा। इसके साथ ही कृषि छात्रों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर प्रतिभा को सम्मानित करने के उद्देश्य से छात्रों को प्रतिभा स्टाइपेंड योजना की शुरूआत की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय,

केन्द्र एवं राज्य की सरकार हर परिस्थिति में कृषि एवं किसानों के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सदन के माध्यम से मैं राज्य के अन्नदाता किसान भाईयों एवं बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार हर सुख–दुःख की घड़ी में आपके साथ दृढतापूर्वक खड़ी है। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति राज्य के विकास की गति को रोक नहीं पायेगी।

रोकेगी हमें क्या राहों की तिरगी ।
लाखों चराग हैं मेरे अजमे सफर के साथ ।।

अंत में मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि कृषि विभाग के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु स्कीम मद में 2395.08 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 757.7342 करोड़ रू० कुल 3152.8142 करोड़ रू० के बजट मांग को अनुमोदित किया जाय।

बहुत बहुत धन्यवाद!!!

कृषि विभाग : प्रमुख उपलब्धियाँ

अध्यक्ष महोदय,

अपने बजट भाषण के क्रम में मैं पिछले वित्तीय वर्ष 2019–20 तक विभाग की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बताना चाहूँगा :–

- कृषि रोड मैप कार्याक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप वर्ष 2011–12 में चावल, वर्ष 2012–13 में गेंहूँ, वर्ष 2015–16 में मोटे अनाज (मक्का), वर्ष 2016–17 में मोटे अनाज (मक्का) तथा वर्ष 2017–18 में गेंहूँ के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को कुल **पाँच कृषि कर्मण पुरस्कार** दिया गया है।
- कृषि विभाग के पोर्टल पर **1.24 करोड़ किसान पंजीकृत** हो चुके हैं।
- विभागीय पोर्टल पर रैयत के साथ–साथ गैर रैयत किसानों अर्थात बटाईदारों का भी पंजीकरण कराया गया है। 1 करोड़ 24 लाख में ~~93 लाख 73 हजार 864 रैयत~~, 2 लाख 32 हजार 508 गैर रैयत ~~एवं 96 लाख 6 हजार 372 रैयत। गैर रैयत~~ के रूप में पंजीकृत हुए है।
- कृषि इनपुट सब्सिडी में 6 लाख 19 हजार 202 गैर रैयत किसानों को अनुदान का लाभ दिया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा किसानों की सहायता के लिए सिंचाई के लिए **डीजल पर अनुदान** की राशि **50 रू० प्रति लीटर से बढ़ाकर 60 रू० प्रति लीटर** किया गया।
- वर्ष 2019–20 में 01 अप्रैल 2019 से अबतक 6.41 लाख किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मद में 88.45 करोड़ रू० भुगतान किया गया है।
- बाढ़/सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को आकस्मिक फसल का बीज मुफ्त उपलब्ध कराया गया।

- आपदा से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए **कृषि इनपुट अनुदान मद** में **12.52 लाख किसानों को 556 करोड़ रू०** आधार से जुड़े बैंक खाते में भुगतान किया गया है।
- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना** के माध्यम से राज्य के **56 लाख किसानों के बैंक खाते में 2745.82 करोड़ रू०** भेजे गये हैं।
- वर्ष 2019–20 में पहली बार किसानों से बीज की मांग से लेकर **बीज की आपूर्ति तक की ऑनलाईन व्यवस्था** की शुरूआत रबी 2019–20 से की गयी है।
- इस वर्ष किसानों के घर पर भी **बीज की आपूर्ति की होम डिलिवरी** व्यवस्था की शुरूआत बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा की गयी है।
- वर्ष 2019–20 में 23 जिलों के लिए 14 बागवानी फसल चिन्हित किये गये हैं तथा इन जिलों में फसल विशेष के विकास के लिए **बिहार विशेष उद्यानिक फसल योजना** शुरू की गयी है।
- बागवानी विकास योजनाओं के तहत वर्ष 2019–20 में 585 हेक्टेयर में आम, 24 हेक्टेयर में अमरूद, 98 हेक्टेयर में लीची, 1383 हेक्टेयर में टिशू कल्चर केला, 91 हेक्टेयर में पपीता, 11 हेक्टेयर में स्ट्रॉबेरी के नये बागान की स्थापना के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गयी है।
- ड्रिप तथा स्प्रींक्लर सिंचाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार **ड्रिप सिंचाई पर 90 प्रतिशत** तथा स्प्रींक्लर सिंचाई पर 75 प्रतिशत अनुदान किसानों को उपलब्ध करा रही है।
- जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत कृषि विभाग के द्वारा **मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम** की शुरूआत की गयी है।
- राज्य के 13 जिलों को मिलाकर **जैविक कॉरिडोर** की स्थापना के लिए 155 करोड़ रू० स्वीकृत किया गया हैं।

- भारत सरकार के द्वारा **बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी** को जैविक प्रमाणीकरण संस्था के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी के द्वारा राज्य के किसानों का जैविक प्रमाणीकरण का कार्य निःशुल्क किया जायेगा।
- **फसल अवशेष प्रबंधन** हेतु किसानों की सहायता के लिए इससे जुड़े कृषि मशीन पर किसानों को **80 प्रतिशत तक अनुदान** दिया जा रहा है।
- राज्य सरकार जल एवं मिट्टी के संरक्षण के लिए वर्ष 2019–20 में मिट्टी एवं जल संरक्षण की राज्य योजना के तहत 2350 जल संचयन संरचना का निर्माण, गाद की सफाई आदि का कार्य किया गया एवं 485 हे0 में पौधा रोपण कार्य किया गया एवं 2916.21 हे० में सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।
- पूर्वोत्तर भारत के लिए हरित क्रांति योजना अन्तर्गत कुल 680 सामुदायिक सिंचाई कूप, निजी बोरवेल एवं सामुदायिक बोरवेल की स्थापना की गयी है एवं 2347.50 हे० में अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था की गयी है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रतिबूँद अधिक फसल (अन्य अन्तःक्षेप) अंतर्गत 306.05 हे० क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।
- समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम उक्त अवधि तक 507 जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया। इस योजना के अंतर्गत 2369.51 हे० क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्वि की गयी है।
- आधुनिक कृषि तकनीक के प्रचार–प्रसार के लिए राज्य के 534 प्रखंडों में से 447 प्रखंड में **ई–किसान भवन** की स्थापना की गयी है।
- जिलों में संयुक्त कृषि भवन का निर्माण कराया गया है।
- पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय स्थापित किया जा रहा है।

- वर्ष 2019–20 में सभी पंचायत स्तर पर रबी तथा खरीफ मौसम में किसान चौपाल लगाये गये।
- जिला स्तरीय आत्मा के द्वारा 97358 किसानों का प्रशिक्षण, 46123 किसानों को परिभ्रमण तथा 1986 प्रत्यक्षण, 712 किसान पाठशाला, 543 किसान गोष्ठी, 36 किसान वैज्ञानिक वार्तालाप का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय आत्मा के द्वारा 350 कृषक उत्पादक संगठन, 1382 कृषक हितकारी समूह का गठन किया गया।
- किसानों को कृषि के संबंध में सम–सामयिक तकनिकी जानकारी एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए खेती–बारी नाम से त्रै–मासिक पत्रिका प्रकाशित की जा रही है।
- कृषि रोड मैप के अंतर्गत नये प्रकार के कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019–20 में 163.513 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी। 81 प्रकार के कृषि यंत्रों पर राज्य सरकार किसानों को 40 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है। पहली बार अति पिछड़ी जातियों के किसानों को अनु.जाति/जन जाति के समान अनुदान का प्रावधान किया गया है
- बिहार राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित कृषि यंत्रों पर किसानों को **10 प्रतिशत अधिक अनुदान** का प्रावधान किया गया है। राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित कृषि यंत्रों के परीक्षण में लगने वाले शुल्क की शत–प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2019–20 से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का क्रियान्वयन नये स्वरूप में किया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य के सभी जिलों के प्रत्येक प्रखंड के एक ग्राम के सभी फार्म होल्डिंग का मिट्टी नमूना संग्रह कर जाँचोपरान्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष कुल 1,60,477 नमूना संग्रहण एवं

विश्लेषण का लक्ष्य है। लक्ष्य के विरूद्ध कुल 1,05,000 नमूनों का संग्रहण एवं 73,100 नमूनों का विश्लेषण किया जा चुका है तथा कुल 45,697 मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के बीच वितरित किया जा चुका है।

- भारत सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार कृषि विश्वविद्यालय को 18वाँ स्थान प्राप्त हुआ।
- बिहार कृषि विश्वविद्यालय के *"आई.सी.टी. बेस्ड ई–एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन फॉर इनहान्स्ड टेक्नोलॉजी एण्ड इन्फॉर्मेशन डिलिवरी "* परियोजना को भारत सरकार द्वारा ई–गवर्नेन्स के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है।
- वर्ष 2019–20 में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर बिहार कृषि सेवा के कृषि अभियंत्रण कोटि में 53, रसायन कोटि में 43, पौधा संरक्षण कोटि में 34 तथा उद्यान कोटि में 36 सहायक निदेशक की नियुक्ति की गयी है। इस प्रकार कुल 166 राजपत्रित पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई।
- आत्मा योजनान्तर्गत 476 प्रखंड तकनिकी प्रबंधक, 1287 सहायक तकनिकी प्रबंधक, 388 लेखापाल एवं आशुलिपिक की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। जिसके विरूद्ध अभी तक 307 प्रखंड तकनिकी प्रबंधक, 824 सहायक तकनिकी प्रबंधक, 239 लेखापाल एवं आशुलिपिक की नियुक्ति हो चुकी है शेष प्रक्रिया में है जल्द ही नियुक्ति कर ली जायेगी।
- बेरोजगार युवक एवं युवतियों को कृषि के क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कुल 4852 व्यक्तियों को कृषि के 23 पाठयक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया है।
- कृषि में उपादान विक्रेताओं यथा खाद, बीज, कीटनाशी विक्रेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फलस्वरूप इन्हें कृषि की सामान्य जानकारी होनी आवश्यक है। इसके लिए अभी तक राज्य के 3040 उपादान विक्रेताओं को एक वर्षीय प्रशिक्षण दिया गया है।

विपक्ष का किसानों के प्रति झूठी हमदर्दी परः–

- तेरे अश्क सियासत वाले, अपने दर्द मुहब्बत वाले।
  बिन दरबाजों का घर हूँ मैं, कौन लगाये मुझपे ताले।।

विपक्ष के इल्जाम परः–

- प्यास सदियों की हैं लम्हों में बूझाना चाहे।
  कत्ल करके जमाने से मुझकों फसाना चाहे।
  अंग्रेज से लेकर कल तक किसानों को किन–किन ने लूटा सबकों पता है।

विपक्ष के बार–बार टोकने परः–

- सब कर लेना, लम्हें जाया मत करना।
  गलत वक्त पर, जज्बे जाया मत करना।।

विपक्ष की गलती परः–

- सुखे रेत वाली नदी, बरसात में बाढ़ लायेगी।
  भूलने की आदत है जमाने की, तुम्हारी भी भूल जायेगी।।

हमारा लक्ष्य है, हमारे नेता का लक्ष्य है सरकार का लक्ष्य हैः–

- हयात ले के चलों, कयानात ले के चलो।
  चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो।।
- विकास ही हमारा मसौदा, किसी से नहीं कोई सौदा।

जल–जीवन–हरियाली एवं बदलते मौसम परः–

- बड़ी तपीश है, अपने गुनाहों की शहर का मौसम खुशगवार नहीं होता।
  करते रहते प्रकृति से छेड़छाड़, कहते है राजी परबर दिगार नहीं होता।।
- पेड़ रहे तो पत्ते, फूल और फल भी आयेंगे।
  थे दिन अगर बुरे, तो अच्छे भी आयेंगे।।

सदन के सभी सदस्यों, साथियों, मित्रों से मैं अपनी आत्मा की आवाज कहता हूँः–

- ऐ प्रभु देना है तो निगाहों में ऐसी रसायन दे।
  मैं देखूं आइना तो, खुशहाल किसान दिखाई दे।।

अमीर खुसरों ने कहाः–

- खुसरों पाँती प्रेम की, बिरला बाँचे कोय,
  बेदपुरान, पोथी पढ़े प्रेम बिना का होय।।

माननीय प्रधानमंत्री जी के लिएः–

- कठिन परिश्रम स्वभाव सरल हो।
  करते रहते दिन–रात काम जो कैसे न राज्यों का भल/हो।।

माननीय मुख्यमंत्री जी के लिएः–

- हे नीतीश कुमार, आपसे है जन–जन को आश।
  जल जीवन हरियाली से बूझेगी धरती व जीवन की प्यास।।

राज्य के अन्नदाता किसान भाईयों एवं अन्नपूर्णा बहनों के लिएः–

- कृषक न होते तो अन्न न होते, अन्न न होते तो हमसब जीवित न होते।
  शायद भगवान भी भूखे सोते।

इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मिडिया के लिएः–

- हे लोकतंत्र के चर्तुथ स्तंभ, सजग कराते रहते हर एक को हरदम।
  तेरे खबरोां से ही होता है, दिन का शुभारंभ।।
  तेरा हो अभिनंदन, तेरा हो अभिनंदन।।

कृषि विभाग के कर्मी एवं अधिकारी के लिएः–

- योजनाओं को धरा पर उतारता चला,
  राज्य के कृषकों का हो रहा भला।

माननीय अध्यक्ष जी के लिए–

- शांति से सदन चलता, कुशल अध्यक्ष जी के नाम।
  राज्य की जनता का सदन में सतत होता रहता काम।

अंत में पक्ष–विपक्ष से एक निवेदनः–

- वक्त है कम लगा दो, जितना हो दम।
  कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो।